रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

6.1.83

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1983/माघ 1, 1904
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1983/MAGHA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

स्टाम्प

का० आ० 442.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की दिनांक 25 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या फा० संख्या 331/82-बि० क० (का० आ० 3775) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के कालम 3 में क्रम संख्या 14 तथा 15 के सामने दिये गये आंकड़ों को क्रमशः "6.0360" तथा "63.95" के स्थान पर "6.3635" तथा "74.70" आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[संख्या 1/83-स्टाम्प/फा० संख्या 33/1/82-बि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th January, 1983

STAMPS

S.O. 442.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 34|82-Stamps F. No. 33|1|82-ST (SO. 3775), dated the 25th October, 1982, namely :—

In the Table to the said notification, against serial number 14 and serial number 15, in column 3, for the figures "6 0360" and "63.95", the figures "6.3635" and "74.70" shall be substituted, respectively.

[No. 1/83-Stamps/F. No. 33/1|82-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1982

का० आ० 443.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की उपधारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की

सिफारिश पर उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता तथा हबीब बैंक लिमिटेड, बंबई को तारीख 19 दिसम्बर, 1970 के एस० ओ० 3949 में प्रदान की गई छूट को, 31 दिसम्बर, 1983 तक और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाती है।

[संख्या 15/36/82-बी० ओ०-III]

एल० आर० कटारिया, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 31st December, 1982

S.O. 443.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, extends for a further period of one year till the 31st December, 1983, the exemption granted in S.O. 3949 dated the 19th December, 1970 to the National Bank of Pakistan, Calcutta and the Habib Bank Limited, Bombay from the provisions of sub-section (2) of section 11 of the said Act.

[No. 15/36/82-BO-III]

L. R. KATARIA, Under Secy.

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1982

का० आ० 444.—केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना द्वारा, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29वा) की धारा 11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय की दिनांक पहली नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या का० आ० 3160 के अन्तर्गत, पूंजी निर्गम नियंत्रण के लिए गठित परामर्शदात्री समिति की कार्यविधि को पहली नवम्बर, 1982 से पांच महीने की अवधि के लिए बढ़ाती है।

[संख्या एस० 8(1)-सी०सी०आई०(II)/82]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

Office of the Controller of Capital Issues

New Delhi, the 28th December, 1982

S.O. 444.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby extends the tenure of the Advisory Committee on Capital Issues Control constituted under this Ministry's Notification No. S.O 3160 dated the 1st November, 1980 by a period of five months with effect from 1st November, 1982

[No. S. 8(1)-CCI(II)/82]

N. K. SEN GUPTA, Jt. Secy

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

अधिसूचना सं० 4/82

कलकत्ता, 1 अक्तूबर 1982

का० आ० 445—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173 जी (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि

(i) मद सं० 15ए(2) और

(ii) मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रथम अनुसूची के मद सं० 15(1) के अधीन आने वाली किसी वस्तु से निर्मित की जाती है कि सभी निर्माता/निर्धारिती कच्चे माल के लेखा का रख-रखाव फार्म IV में करेंगे जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट के 1 के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 55(ए) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए यह भी आदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रथम अनुसूची के मद सं० 15(ए(1) के अन्तर्गत आने वाली कोई भी वस्तु प्रधान कच्चा माल होगा जिसका मात्रा फार्म आर०टी० 5 में प्रयुक्त कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के त्रैमासिक विवरण में प्रस्तुत किया जायेगा।

बशर्ते कि जहां उपर्युक्त उत्पादित वस्तुएं लागू होने वाले सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से अस्थाई रूप से मुक्त हो या जहां इस समय तक न किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो, यद्यपि निर्माता के पास इस प्रयोजन के लिए लाइसेंस हो, ऐसे निर्माता/निर्धारिती को कच्चा माल के लेखा का फार्म IV में रख-रखाव करना आवश्यक है या प्रयुक्त मालों और निर्मित वस्तुओं का फार्म आर०टी० में त्रैमासिक विवरण ही प्रस्तुत करना आवश्यक है।

फार्म 4

(नियम 173 ओ)

कच्चा माल और अवयव का लेखा

फैक्ट्री का नाम एवं पता

कच्चे माल/अवयव का विवरण

तारीख	आदिशेष	प्राप्त मात्रा	कुल योग	निर्माण में प्रयुक्त हुई मात्रा	
				उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	अन्य वस्तुएं
1	2	3	4	5	6

अन्य रूप में निपटान की गई मात्रा		व्यर्थ या नष्ट हुई मात्रा	अन्तशेष	उत्पाद शुल्क योग्य निर्मित की गई वस्तुओं की मात्रा	अन्य निर्मित की गई वस्तुओं की मात्रा	टिप्पणी
निपटान की प्रकृति	मात्रा					
7	8	9	10	11	12	13

शुल्क दाता या उसके एजेंट का हस्ताक्षर
14
माह का कुल योग

[सं० स० IV (8)/1-के०उ०/82]

बा० एन० रंगवानी, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise

NOTIFICATION NO 4/82

Calcutta, the 1st October, 1982

S.O. 445:—In exercise of the power conferred upon me under rule 173G(4)(a) of the Central Excise Rules, 1944 it is hereby ordered that all manufacturers/assessees of excisable goods falling under

(i) Item No. 15 A(2) and

(ii) Item No. 68, which are manufactured from any goods falling under Item No. 15A(1) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) shall maintain account of raw materials in Form-IV, enclosed as Annexure-I to this Notificat

In exercise of the powers conferred on me under rule 55(a) of the Central Excise Rules, 1944 it is also ordered that any goods falling under Item 15A(1) of the First Schedule to the Central Excises & Salt Act, 1944 (1 of 1944) shall be the principal raw materials, the quantity of which should be furnished in the quarterly return of raw materials used and of goods manufactured in Form R.T. 5:

Provided that where the aforesaid goods produced are, for the time being, exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon; or where no excisable goods are being produced for the time being although the manufacturer holds a licence for the purpose of such manufacture/assessee are not required to either maintain the account of raw materials in Form-IV or submit quarterly return of materials used and of goods manufactured in Form R.T. 5.

FORM-IV

(Rule 173G)

Account of Raw Materials and Components.

Name & Address of the Factory ------------------------------

Description of raw material/components ------------------------------

Date	Opening balance	Quantity received	Total	Qty. used in the manufacture of	
				Excisable goods	Other goods
1	2	3	4	5	6

Quantity otherwise disposed of		Qty. wasted or destroyed	Closing balance	Qty. of excisable goods manufactured	Qty of other goods manufactured	Remarks	Signature of the Assessee or his agent.
Nature of the disposal	Quantity						
7	8	9	10	11	12	13	14

Total for the month

[C. No. IV/(8) 1-CE/82]
B.N. ANGWANI, Collector

(भारतीय पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल का कार्यालय)

नई दिल्ली, 15 जून, 1982

का० आ० 446.—भारतीय पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल द्वारा उनके आनकर्ताओं के द्वारा पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के अधीन 31 मार्च, 1982 को धारित पूर्त अक्षय निधि (केन्द्रीय) से संबंधित संपत्तियों और प्रतिभूतियों की सूची तथा 1981-82 के लेखों का सारांश सामान्य जानकारी के लिए नीचे प्रकाशित किया जा रहा है।

भाग 1 : प्रतिभूतियों से भिन्न सम्पत्तियों की सूची

क्रम संख्या	अधिकार में देने के आदेश का ब्यौरा: संख्या	अधिकार में देने के आदेश का ब्यौरा: दिनांक	अक्षय निधि का नाम	सम्पत्ति के प्रशासक	धारित सम्पत्ति: विवरण	धारित सम्पत्ति: मूल्य	धारित सम्पत्ति: वार्षिक आय, यदि मालूम हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत								
						रुपए	रुपए	
	1 स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा० 14-26/61-इंस्टीट्यूट जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० 22020/11/76 एम० सी० (एम० एस०) द्वारा यथा शोधित	31 अगस्त, 1962 31 अगस्त, 1977	पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया	पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रशासक	(1) पेंटरिबेज रिसर्च सेंटर कसौली की इमारतें (2) लेडी लिनलिथगो सैनिटोरियम, कसौली की इमारतें (3) मिल्टन, लाज, कसौली	2,23,200.00 2218.700.00 26,000.00	शून्य	
	2 रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० 250	19 जुलाई, 1960	कर्मोली तथा उदयपुरी स्थित कुमाऊं रेजीमेंटल फारम की फारम निधि	निधि का प्रशासक बोर्ड	कर्मोली महर्मोल कालाढूंगी, जिला नैनीताल 1 औषधालय (30 फीट × 24 फीट) 2 धर्मशाला (30 फीट × 24 फीट) 3 अतिथि-गृह नं० 1 (30 फीट × 35 फीट) 4 अतिथि गृह नं० 2 (28 फीट × 26 फीट)	 4,000.00 4,000.00 5,000.00 3,500.00	शून्य	
महाराष्ट्र :								
	1 जी० आई० एच० डी० शिक्षा, संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंबई का कलेक्टर, श्री नारायण दत्तात्रेय सिरूर और श्री नवल एच० टाटा	"विक्टोरिया बिल्डिंग"—पूर्ण स्वामित्व (फ्री-होल्ड) की वह सारी भूमि जो फोर्ट में पारसी बाजार स्ट्रीट के पूर्व में एल्फिस्टोन सर्किल पर या उसके बराबर में स्थित है। इसमें वाटिका गृह, वास-गृह और इमारतें शामिल हैं जिसे "विक्टोरिया बिल्डिंग" कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 482-3/4 वर्ग गज है अथवा इसके करीब है।	मालूम नहीं	शून्य	

1 2	3	4	5	6	7	8	9
					रुपए	रुपए	
2 और 3	27 मई 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बम्बई का कलक्टर श्री नारायण दत्तात्रेय मिश्र और श्री मसल एच० टाटा	'एल्फियन प्लेस और अलेक्जेंड्रा टेरेस"— भूमि का वह सारा भाग जो परेल रोड के पूर्व में भायखला में स्थित है। इसमें वाटिका-गृह, वास-गृह और इमारतें, अहाते में बने नौकर-चाकरों के मकान और अस्तबल शामिल हैं जिन्हें एल्फियन प्लेस और अलेक्जेंड्रा टेरेस कहा जाता है इसका क्षेत्रफल 11,104 वर्ग गज अथवा इसके करीब है।	मालूम नहीं	शून्य	
3 जी० आई० एच० डी० शिला संख्या 433	वही	वही	वही	भायखला के निकट परेल रोड जिसे अब डा० अम्बेडकर रोड के नाम से पुकारा जाता है के पूर्व और 11,104 वर्गगज अथवा इसके करीब भूमि पर 'होटल हेरिटेज' नामक एक नई इमारत का निर्माण।	19,00,000 00	189,120 00	
4 और 5	वही	वही	वही	'रे हाउस' और सैंडहर्स्ट हाउस' बम्बई द्वीप में अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित भूमि का पट्टे पर मिला हुआ वह टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 2004-8/9 वर्ग गज है और जिस पर 'रे हाउस' और सैंडहर्स्ट हाउस' नामक दो इमारतें बनी हुई हैं।	मालूम नहीं	शून्य	
6 और 7 जी० आई० एच० डी० शिला संख्या 433	वही	वही	वही	'रूजवेल्ट या एजरा हाउस पट्टे पर मिली भूमि का वह सारा टुकड़ा जो अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 533-3/9 वर्ग गज है और जिस पर "रूजवेल्ट हाउस या एजरा हाउस" नामक इमारतें बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 573-3/5 वर्ग गज का पट्टे पर ली गई भूमि का यह टुकड़ा भी जो बम्बई द्वीप में अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित है।	वही	वही	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 और 9		27 मई 1900	भारतीय विज्ञान संस्थान	बम्बई का कलेक्टर श्री नारायण दस-बेस मिस्त्र और श्री नवल एच० टाटा	'मारगेट हाउस" और 'जैम्किन्स हाउस'- बम्बई द्वीप में अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित 3487-2/9 वर्गगज का भूमि का वह टुकड़ा जिस पर मारगेट हाउस और जैम्किन्स हाउस नामक इमारतें स्थित है।	मालूम नहीं	शून्य	
10 जी० आई० एम० ओ० मि० संख्या 433		वही	वही	वही	"न्यूशामजी बिल्डिंग्स' जिसे अब स्टेशन टैरेस स्लीटर रोड' कहा जाता है फोरस इस्टेट की लगभग 2,290 वर्गगज की भूमि जिस पर कई वाटिका गृह, वास गृह या रिहायशी मकान बने हुए हैं, जिन्हें न्यू शामजी बिल्डिंग्स कहा जाता था परन्तु वर्तमान नाम— स्टेशन टैरेस है तथा यह बंबई में स्लीटर रोड के दक्षिण में स्थित है।	वही	वही	
11 वही		वही	वही	वही	"मेडो हाउस" पट्टे पर मिली हुई भूमि का वह टुकड़ा, जो बंबई, द्वीप में अपोलो रिक्ले-मेशन पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लग-भग 529-6/9 वर्ग-गज है और जिसे "मेडो हाउस" कहा जाता है।	वही	वही	
12 और 13 जी० आई० एम० डी० मिला संख्या 433		वही	वही	वही	"एल्बियन प्लेस और अलेक्जेंड्रा टैरेस" के निकट भूमि का वह टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8,570 वर्ग गज है जो बम्बई के कलेक्टर द्वारा बम्बई शहर में परेल रोड पर भायखला में स्थित भूमि खंड के साथ पंजीकृत है इसमें वाटिका गृह वास गृह और रिहायशी मकान शामिल हैं इसे "एल्बियन प्लेस और अलेक्जेंड्रा टैरेस" के निकट का भूमि कहा जाता है।	वही	वही	बम्बई शहर के लिए भूमि अधि-ग्रहण अधिकारी 1078/9 गज भूमि को अधि-गृहीत कर लिया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	सी० आई०एस० बी० जिला नक्शा 433	27 मई 1909	सा लोद विभाग संस्थान	बम्बई का मजदूर "परेल टैंक रोड पर आ नारायण दत्ता- मिश्र, भूमि क्षेत्र मिश्र और श्री नवल रत्न, टाटा	भूमि (1) लगभग 67037 वर्गगज भूमि का टुकड़ा, जिसमें से 7021 वर्गगज सरकारी टोका भूमि और 2189 वर्गगज सरकारी भूमि जिसका भाग श्री में निर्दिष्ट किया गया है, शामिल है और शेष इनाम भूमि है जो परेल में परेल गवर्नमेंट टैंक को जाने वाला मार्ग अलिक सड़क पर किया है जिसे परेल टैंक रोड स्थित भूमि (कार्यक्षेत्र) कहा जाता है। (2) परेल स्थित इनाम भूमि का खाली टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 6005 वर्गगज है। (3) गवर्नमेंट टोका भूमि का खाली टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग 1058 वर्गगज है और जो बम्बई नगर में परेल पर गोमाजी हिल रोड पर और उसके दक्षिण में स्थित है। (4) सरकारी टोका भूमि का खाली टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 569 वर्गगज है और जो बंबई नगर में परेल पर वालाजी हिल रोड पर और उसके दक्षिण में स्थित है।	मकान नहीं	शून्य	74686 वर्गगज भूमि में से 15,575.80 वर्गगज भूमि टाटा हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर गेंड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के लिए प्रेषण लाईनें बिछाने और अन्य निर्माण कार्य करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा अभिगृहीत कर ली गई तथा 37471.52 वर्गगज भूमि बाद में 1922 में भूमि अभिग्रहण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कर ली गई। परेल टैंक रोड भूमि पर स्थित का एक भाग सी० एस० संख्या 1/202 पार्ट जिसका क्षेत्रफल 2043.88 वर्गगज है और सी० एस० संख्या 203 पार्ट जिसका क्षेत्रफल 62.43 वर्ग गज है, बंबई नगर निगम ने भूमि अभिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 का पहला) की धारा 12 (2) के अधीन एक जलाशय के निर्माण के लिए अभिग्रहीत कर लिया था।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	डी० आई० एच० डी० मिसल संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बम्बई का कलेक्टर श्री नारायण दत्तात्रेय सिरूर और श्री नवल एच टाटा	बम्बई नगर और रजिस्ट्रेशन उपजिले में कोलाबा रोड के पश्चिम में स्थित भूमि का वह सारा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग 2020 वर्ग गज अथवा इसके करीब है और जिसकी हदबंदी इस प्रकार है:—उत्तर में या उत्तर की ओर सर करीम भाई इब्राहिम बारोनेतसी न्यास के न्यासियों की संपत्ति, दक्षिण में या दक्षिण की ओर पुलिस चौकी सड़क, पूर्व या पूर्व की ओर कोलाबा रोड, पश्चिम में या पश्चिम की ओर बोटहाउस रोड। यह भूमि बम्बई के कलेक्टर की किताबों में रेट रोल संख्या 8509 पर दर्ज है और उसकी कोलाबा प्रभाग की बन्दोबस्त सर्वेक्षण संख्या 48 है। इसमें भूमि पर बनी इमारतें और अन्य ढांचे शामिल हैं। इसका निर्धारण बम्बई नगर-पालिका द्वारा प्रवार्ड संख्या 213 और 214 और क्रमशः कोलाबा रोड और बोटहाउस रोड की गली संख्या 158 और 125 तथा लोअर कोलाबा रोड की गली संख्या 154 के अन्तर्गत गिनाया है।	18,44,108 28	199,675.08	
16.	जी० आर० ई० डी० संख्या 452	7 मार्च 1906	सर जमशेदजी जेजीभाई पारसी हितकारी संस्थान	सचिव, सर जमशेदजी जेजीभाई पारसी हितकारी संस्थान बम्बई	बम्बई में हार्नबी रोड फोर्ट पर स्थित 1688 वर्गगज भूमि का टुकड़ा और उस पर बने हुए रिहायशी मकान और इमारतें	मालूम नहीं	शून्य	
17	जी० आर० ई० डी० संख्या 1778	10 जुलाई, 1912	तदैव	तदैव	गोवागली, फोर्ट बम्बई में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का सारा टुकड़ा और उस पर, बने हुए वाटिका गृह, वासगृह और अस्तबल जिसका क्षेत्रफल लगभग 173 और 62 वर्गगज है।	तदैव	तदैव	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु:								
1. संख्या 46—शिक्षा तथा संख्या 389—शिक्षा		5 अप्रैल, 1904 तथा 25 जून, 1904	मद्रास सैनिक बालिका अनाथालय निधि स्कूल मद्रास	सचिव तथा कोरसपोंडेंट सेंट जार्ज तथा अनाथालय	मद्रास में स्थित भूमि जिसकी सर्वेक्षण संख्या 232 है और जिस का क्षेत्रफल 15 कानी, 18 ग्राउंड और 1678 वर्ग फुट है और उस पर बनी इमारत जिसका नाम मद्रास सैनिक बालिका अनाथालय (मद्रास मिलिट्री फीमेल आरफन असाईलम) है।	मालूम नहीं	शून्य	इस संपत्ति पर सिविल ओरफन असाईलम का कब्जा है। यह कब्जा इस शर्त पर दिया गया था कि वहां पर अनाथालय की लड़कियों के अलावा मद्रास सैनिक बालिका अनाथालय में पहले भर्ती की गयी 30 अन्य बालिकाओं के भरण-पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
उत्तर प्रदेश:								
1. उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 602/15 301 और, 608 बी/15 619/1923		क्रमश: 2 अप्रैल 1918 29 नवम्बर 1923	गिरोंडी कायस्थ पाठशाला प्रन्यास निधि, मिरजापुर	प्रबन्ध समिति जिसके पदेन अध्यक्ष मिरजापुर के कलेक्टर होंगे और जिसमें स्व० मुंशी बिन्देश्वरी प्रसाद वकील की संपत्ति के निष्पादक सदस्य होगे।	(क) जिला मिरजापुर के मुहल्ला बेलेजलीगंज में स्थित तीन मकान जिनकी हदबंदी इस प्रकार है:— (1) दक्षिण : श्री प्यारे लाल का मकान, उत्तर: मुसम्मात मुन्नी का मकान ; पश्चिम : गवर्नमेंट रोड ; पूर्व : श्री सुमेर कुमार का मकान।	600.00	36.00	
					(2) दक्षिण : मुंशी बिन्देश्वरी प्रसाद वकील का मकान उत्तर : मस्जिद पश्चिम : श्री रामेश्वर तेली का मकान, पूर्व : सड़क ।	600.00	36.00	
					(3) दक्षिण : श्री बुद्ध का मकान ; उत्तर : मुंशी बिन्देश्वरी प्रसाद वकील का मकान : पश्चिम : मुसम्मात उमराव का मकान पूर्व : सड़क	600.00	36.00	
					(ख) मिरजापुर जिले की चुनार तहसील के मौजा गिरौंडी में स्थित बाग।	600.00	15.00	
					(ग) मिरजापुर जिले की चुनार तहसील के मौजा गिरौंडी में उपयुक्त (ख) में बताये गये बाग में स्थित पाठशाला।"	50.00	शून्य	

पंजाब

चूंकि केन्द्रीय पूर्त प्रक्षय निधि से सम्बद्ध संपत्तियों का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा अभी नहीं हुआ है, इसलिए इन संपत्तियों की सूची अभी तैयार नहीं की जा सकी है।

भाग II--प्रतिभूतियों की सूची और लेखा सारांश

मामला संख्या	पूर्त प्रक्षय का नाम	निधि वे व्यक्ति जिनकी ओर से धारित है	प्रतिभूतियों का ब्यौरा	प्रतिभूतियों की कुल रकम	नकद	
						वसूल किया गया ब्याज या लाभांश
1	2	3	4	5	6	
भारत				रुपये	रुपए	रुपए
1.	खण्डपारा राज्य न्यास निधि	खण्डपारा राज्य न्यास निधि का न्यासी बोर्ड	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	30,600.00	30,600 00	3,060.00
2.	सशस्त्र सेना हितकारी निधि	सशस्त्र सेना हितकारी निधि की सामान्य समिति	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	8,00,400.00	8,00,400.00	36,018 00
3.	सेंट डन्सटन्स (इंडिया) फंड	सेंट डन्सटन्स (इंडिया) फंड का नियासी बोर्ड	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	92,900.00		
			4-3-/4 प्रतिशत ऋण 1939	15,000.00	1,07,900.00	48,21.00
4.	थामस रोड बैल स्मारक निधि	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और कालेज, देहरादून	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	3,10,00	3,100,00	139.50
5.	भारतीय पास्चर संस्थान	भारतीय पास्चर संस्थान की संस्था के प्रशासक	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	66,900.00		
			5 वर्षीय डाकघर अवधि जमा	30,750.00	97,650.00	6,323.97
6.	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण निधि	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण निधि की सामान्य समिति	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा —	5,94,47,550.00	5,94,47,550.00	61,47,686.

प्राप्तियां		नकद व्यय		नकद शेष	टिप्पणी	मामला संख्या
अन्य नकद प्राप्तियां	नकद प्राप्तियों की कुल रकम	अदायगियां				
7	8	9		10	11	12
रुपए	रुपए			रुपए		
	3,060.00	दिया गया ब्याज	3,029.40		—	1
		सरकार को दी गई फीस	30.60			
			3,060.00			
.	36,018.00	दिया गया ब्याज	35,657.82			
		सरकार को दी गई फीस	360.18			
			36,018.00			
.	4,821.00	दिया गया ब्याज	4,772.78		कालम संख्या 6 के नीचे दी गयी रकम में स्रोत पर काटे गये आय-कर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	
		सरकार को दी गई फीस	48.22			
			4,821.00			
		दिया गया ब्याज	138.09			
..	139.50	सरकार को दी गई फीस	1.41			
			139.50			
(क) 1,10,900.00	1,17,223.97	दिया गया ब्याज	6,260.72			
		सरकार को दी गई फीस	63.25			
			6,323,97	1,10,900.00	(क) यह राशि 4 प्रतिशत ऋण 1980 की परिशोधन प्राप्ति की द्योतक है जिसके निवेश के संबंध में निधिप्राधिकारियों से हिदायतों की प्रतीक्षा की जा रही है।	
..	61,47,685.90	दिया गया ब्याज	60,86,209.04			
		सरकार को दी गई फीस	61,476.86			
			61,47,685.90			

1 2	3	4	5	6	
			रु०	रु०	रु०
7. पुस्तकालय विज्ञान के लिए शरदा रंगनाथन पूर्त अक्षय निधि	निधि की प्रबन्ध समिति	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	7,00,000.00	7,00,000.00	74,653.00
8. देहरादून स्थित वयस्क अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र का बानुबाई बीरमजी कांगा प्रशिक्षणार्थी कल्याण निधि	अधीक्षक, वयस्क अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 6 प्रतिशत पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड बांड 1982	49,950.00 4,400.00	54,350 00	53,52 77
9 झंडा दिवस निधि	झंडा दिवस निधि की प्रबंध समिति	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	4,20,000.00	4,20,000.00	17,640.00
10. युद्ध पीड़ितों और अपंग सैनिकों के लिए विशेष सहायता निधि	प्रबन्ध समिति, युद्ध पीड़ितो और अपंग सैनिको के लिये विशेष सहायता निधि	5 वर्षी डाकघर सावधि जमा	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00	20,00,000.00
11. महिलाओं व बच्चों के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल, दिल्ली निधि	प्रशासन बोर्ड लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा श्रीमती एस०के० अस्पताल	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,02,650.00	1,02,650.00	10,265.00

7	8		9	10	11	मामला संख्या
रु०			रु०	रु०		
..	74,653.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	73,906.47 746.53 74,653.00	...		
	5,352.77	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	5,299.24 53.53 5,352.77			
					कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	
	17,640.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	17,463.60 176.40 17,640.00			
	20,00,000.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	19,80,000.00 20,000.00 20,00,000.00			
	10,265.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	10,162.35 102.65 10,265.00			

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
12.	राष्ट्रीय बाल निधि	निधि के न्यासियों का बोर्ड	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	26,00,000.00	26,00,000.00	2,79,387.50
13.	भारतीय मकान महामता न्यास	प्रबन्धक बोर्ड, नई दिल्ली	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	32,78,400.00	32,78,400.00	1,42,610.00
14	महुवी पूर्त प्रक्षय निधि	मूसा बोर्ड, कलकत्ता	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	38,000.00		
			5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	59,350.00	97,350.00	3,083.37
15	राष्ट्रीय कर्मचारी राहत निधि	राष्ट्रीय कर्मचारी राहत निधि बोर्ड, चंडीगढ़	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	20,750.00	20,750.00	

7	8	9	10	11		मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
(ख) 24,00,000.00	26,79,387.50	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस अन्य अदायगियां	2,76,593.62 2,793.88 24,00,000.00 26,79,387.50		(ख) यह निधि प्राधिकारियों से प्राप्त हुई राशि की द्योतक है जिसे 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेशित क॰ ।दय. गया है।	
..	1,42,610.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	1,41,183.90 1,426.10 1,42,610.00		* कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	
(ग) 59,394.04	62,477.41	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस अन्य अदायगियां	3,052.54 30.83 59,394.04 62,477.41		.. कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है। (ग) यह राशि 59,700.00 रुपए की 5½ प्रतिशत पश्चिम बंगाल ऋण, 1983 की समय से पूर्व बिक्री प्राप्ति की, जो केवल 59,394.04 रुपए है, की द्योतक है जिसमें से 59,350.00रुपए 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश किए गए हैं और शेष 44.04 रुपए निधि प्राधिकारियों को लौटा दिए गए हैं।	
(घ) 20,775.38	20,775.38	5 वर्षीय डाकघर सावधि खाते में जमा देय राशि निधि प्राधिकारियों को वापस लौटा दी गई है	20,750.00 25.38 20,775.38		(घ) यह राशि भारतीय पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के हिस्से के अंतरण की द्योतक है इसमें से 20,750.00 रुपए 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा में निवेश किए गए हैं और शेष 25.38 रुपए निधि प्राधिकारियों को लौटा दिए गए हैं।	

1	2	3	4	5	6	7
				रु०	रु०	रु०
महाराष्ट्र						
1	भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर की सम्पत्तियां)	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद्	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	2,150.00	2 150.00	231.60
2	भारतीय विज्ञान संस्थान बंबई की सम्पत्तियां	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद्	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946 5½ प्रतिशत ऋण 2,000 पुराना 5¾ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1982 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	10,22,800.00 1,40,300.00 57,800 00 10,700.00	12,31,600.00	38,703.00
3	कराची के फकीर जी कोवासजी की छात्रवृत्ति निधि	कप्तान-अधीक्षक प्रशिक्षण पोत, "राजेन्द्र" न्यू फेरी हार्बर से परे, बम्बई-9	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	60,000 00	60,000.00	1,800 00
4	वैटफील्ड स्मारक पुरस्कार निधि	1 प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय, पूना 2 प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय, धारवाड़ 3 प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय अहमदाबाद	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	200 00	200 00	6 0
5	गणेश बलवन्त लिमये छात्रवृत्ति निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	56,000 00	56,000.00	1,512.00

7	8	9	10	11		मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
	231 60	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	229 28 2 32 231.60			
(क) 27 02	38,730 02	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	38,274 23 428.77 38,703.00	27 02	(क) यह रकम 27 02 अवशेष की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम स्रोत पर काटे गये आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	
	1,800 00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	1,782 00 18.00 1,800.00		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	
59.45	65 45	सरकार को दी गई फीस	0 06 0.06	(ख) 65 39	(ख) यह रकम 65 39 अवशेष की द्योतक है।	
	1 512 00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	1,495.20 16.80 1,512.00		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
6.	सर विलियम मूरे स्मारक निधि	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महाराष्ट्र राज्य, बम्बई	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	1,100.00	1,100.00	29.00
7.	बम्बई प्रेसीडेंसी में मुसलमानों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये काजी शाहबुद्दीन प्रश्रय निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946 5 वर्षीय डाकघर सावधि	1,45,300.00 5,100.00	1,50,400.00	4,054.62
8.	अंग्रेजी में एस०एस०सी० परीक्षा संबंधी पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	400.00 3,000.00	3,400.00	333.25
9.	कृषि और शिक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए सर सेसून डेविड न्यास निधि	कृषि और सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार बम्बई के सचिव के मार्फत निधि का न्यासी बोर्ड	5 3/4 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण, 1983	7,51,100.00	7,51,100.00	38,870.24

7	8	9	10		11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
.	29.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	28.66 0.34 29.00	..	कालम 6 में दिखाई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गये आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	
(ख) 5100.00	9,154.62	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस अन्य अदायगियां	4,009.55 45.07 51,00.00 9,154.62	.	कालम 6 में दिखाई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है (ख) यह राशि $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण, 1981 की परिशोधन–प्राप्तियों को द्योतक है जिसे 5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा में पुन: निवेश कर दिया गया है।	
..	333.25	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	329.90 3.35 333.25	...	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	
.	38,870.24	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	38,438.36 431.88 38,870.24	.	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
10	बम्बई राज्य परिवीक्षा और अनुरक्षण निधि	अध्यक्ष, बम्बई राज्य परिवीक्षा और अनुरक्षण सभा, ओ० आई० टी० ब्लाक संख्या 33, [illegible] मार्ग, बम्बई-19				
			3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	7,000.00		
			5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	14,000 00	21,000 00	1,698.60
11	भारतीय इम्पीरियल सहायता (छात्रवृत्ति) निधि	शिक्षा-निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	25,200 00	25,200 00	680.00
12	सावित्री बाई कृष्णाराव उपलब्ध छात्रवृत्ति निधि	—तदैव—	—तदैव—	12,800.00	12,800 00	346 60
13	बम्बई प्रदेश कृषि प्रदर्शनी निधि	कृषि निदेशक महाराष्ट्र राज्य, पूणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	4,16,000 00	4,18,000 00	11,232 00
			7 वर्षीय अल्प बचत बांड	2,000 00		
14.	डा० रामचन्द्र शिवाजी पोंग्वी छात्रवृत्ति निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य पूणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	11,100.00	11,100 00	299 00

8	8	9	10	11		मामला संख्या
				रुपये	रुपये	
	1 698 60	दिया गया ब्याज	1,681 41		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	10
		सरकार को दी गई फीस	17 19			
			1,698 60			
	680 00	दिया गया ब्याज	672 44		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	11
		सरकार को दी गई फीस	7.56			
			680.00			
	348 00	दिया गया ब्याज	342 16		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	12
		सरकार को दी गई फीस	3 84			
			346 00			
	11,232 00	दिया गया ब्याज	11,107 20		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	13
		सरकार को दी गई फीस	124.80			
			11,232 00			
	299 00	दिया गया ब्याज	295 66		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम मे स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमे शामिल नहीं हैं।	14
		सरकार को दी गई फीस	3 34			
			299.00			

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
15.	सर कुसरो वाडिया न्यास निधि	निधि के शासी निकाय के अध्यक्ष, द्वारा सचिव कृषि और सहकारिता विभाग महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	6 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 1966	12,94,200.00	12,94,200.00	69,886.00
16.	युद्धोपरान्त सैन्य पुनर्निर्माण निधि (राजस्थान अंश)	निधि, सचिव द्वारा महाराष्ट्र राज्य एस० एस० तथा ए० बोर्ड पुणे-1	5½ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1982 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946 6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण, 1984	6,400.00 1,200.00 3,500.00	11,100.00	552.00
17.	भारतीय वाणिज्य नाविकों के लिये युद्ध स्मारक निधि 1947	इंडियन सेलर्स होम सोसाइटी की प्रबन्ध समिति, मस्जिद बन्दर सार्टिंग रोड, बम्बई-9	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	21,32,900.00	21,32,900.00	57,589.00
18.	होमी मेहता विजय धन्य-वाद निधि (राजस्थान अंश)	निधि सचिव, द्वारा महाराष्ट्र राज्य एस० एस० तथा ए० बोर्ड पुणे-1	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946 5½ प्रतिशत ऋण 2003 6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1984	800.00 100 00 400 00	1,300.00	49.74

7	8	9	10	11		मामला संख्या
(ट) 42.00	69,928.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	69,109.48 776.52 69,886.00	42.00	(ट) यह रकम अग्र शेष की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	15
(ठ) 35.00	587.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	545.86 6.14 552.00	35.00	(ठ) यह रकम अग्र शेष की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	16
..	57,589.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	56,949.12 639.88 57,589.00		—तदैव—	17
(ड) 4.00	53.74	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	49.20 0.54 49.74	4.00	(ड) —तदैव—	18

			रु०	रु०	रु०
19. एल०बी० मंडके पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	1,600 00	1,600.00	44 00
20. कुमारी मणिकबाई मिन्दे पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-I	3 प्रतिशत ऋण 1896-97	1,000.00	1,000.00	26.00
21. मराठा युद्ध स्मारक निधि	मराठा युद्ध स्मारक निधि के अवैतनिक सचिव, मराठा लाइट इन्फैंटरी रेजीमेन्टल बेलगांव	5½ प्रतिशत ऋण 2000(पुराना) भारतीय स्टेट बैंक बम्बई के पास मियादी जमा	9,100.00 3,26,225.72	3,35,325.72	29,810.74
22. सर एम०पी० जोशी न्यास निधि	प्रिंसिपल, कृषि कालेज पुणे	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946 5¾ प्रतिशत ऋण 2002	12,800.00 500.00	13,300.00	372.74
23. कुमारी कलार्क स्मारक उपचर्या निधि	भारत की नारियों को स्त्री-रोग चिकित्सा सहायता तथा शिक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय संस्था की बम्बई शाखा के अध्यक्ष द्वारा श्री आर०एन० भाव नगरी एम० बी० बिल्लीमोरिया एण्ड, कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 113, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-I	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	11,000.00	11,000.00	296.00

7	8	9	10		11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
..	44 00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	43.52 0.48 44.00		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	19
	26.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	25.70 0.30 26.00		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	20
	29,810.74	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	29,512.14 298.60 29,810.74		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	21
	372.74	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	368.62 4.12 372.74		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	22
	296.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	292.70 3.30 296.00		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	23

1	2		3	4	5	6
				रु०	रु०	रु०
24.	बरजोरजी मानेकजी सुतारिया पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र राज्य पुणे	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	2,000.00	2,000.00	54.00
25.	कैम्पबैल स्मारक पदक निधि	एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई शाखा की प्रबन्ध समिति, टाउन हाल बम्बई-1	5½ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1984	4,900.00	4,900.00	253.74
26.	सर जमशेदजी जेजी भाई सविध, पारसी हितकारी संस्था	सर जे०जे०पी०बी० संस्था 209, डा० दादा भाई, नैरोजी रोड, फोर्ट, बम्बई-1	13 स्टेट बैंक के शेयर	1,300.00		
			3 प्रतिशत ऋण 1896-97	6,900.00		
			4½ प्रतिशत ऋण 1989	500.00		
			6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1984	3000.00		
			5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	11,43,550.00		
			5½ प्रतिशत ऋण 2001	8,80,800.00		
			5½ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1982	11,400.00		
			6 प्रतिशत बम्बई नगरपालिका के ऋण पत्र 1983	20,500.00		

7	9	9	10		11	मामला सं०
रु०	रु०		रु०	रु०		
..	54.00	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	53.40 0.60 54.00	.	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	24
..	253.74	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	250.92 2.82 253.74	..	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	25
(ज) 3,54,600.25	5,00,823.31	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस अन्य अदायगियां	1,38,983.82 1462.24 3,54,600.00 4,95,046.06	0.25	(ज) यह राशि निम्नलिखित की द्योतक है:— अथ शेष 0.25 6 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड बांड, 1981 की परिशोधन प्राप्तियां 3,36,200.00 4 प्रतिशत ऋण, 1981 की परिशोधन प्राप्तियां 500.00 5 3/4 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण, 1981 8,900.00 10 प्रतिशत 5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा 9,000.00 3,54,600.25 कालम (6) में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आय कर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं है।	26

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
		$5\frac{1}{8}$ प्रतिशत ऋण 1999	10,500.00		
		$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ऋण 2002	3,400.00		
		6 प्रतिशत ऋण 1998	11,300.00		
		$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2003	15,200.00		
		$6\frac{1}{4}$ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1985	500.00		
		6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण. 1985	500.00	21,09,350.00	1,46,223.06
27. भारत की नारियों को स्त्री रोग चिकित्सा और सहायता तथा शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्रीय संस्था की बम्बई शाखा	राष्ट्रीय संस्था की बम्बई शाखा के कोषाध्यक्ष द्वारा श्री आर०एन० भावनगरी, एस० बी० बिलीमोरिया एंड कम्पनी, 113, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-I	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	2,18,100.00		
			30,000.00	2,48,100.00	6,665.50
		5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा			
28. रुस्तमजी जमशेदजी जेजीभाई गुजराती विद्यालय निधि	सचिव, सर जे०जे० पारसी हितकारी संस्था, 209, डा० दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट बम्बई.	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	72,000.00	72,000.00	1,944.00
29. भूतपूर्व संगली राज्य द्वारा रखी गई किंग एडवर्ड स्मारक निधि -	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	49,100.00	50,300.00	1,357.00
		3 प्रतिशत ऋण-1896-97	1,200.00		

7	8		9	10	1	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
(ख) 30,000.00	36,665.50	दिया गया ब्याज	6,591.43	..	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	27
		सरकार को दी गई फीस	74.07			
		अन्य अदायगियां	30,000.00			
			36,665.50			
					यह राशि $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण, 1981 की परिशोधन प्राप्तियों की द्योतक है जिसे 5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा में पुन: निवेश कर दिया गया है।	
	1,944.00	दिया गया ब्याज	1,922.40	.	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	28
		सरकार को दी गई फीस	2160			
			1,944.00			
.	1,357.00	दिया गया ब्याज	1,341.90	.	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	29
		सरकार को दी गई फीस	15.10			
			1,357.00			

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
30. सी०पी० और बरार किंग एडवर्ड स्मारक समिति निधि	सचिव, शासी निकाय किंग, एडवर्ड स्मारक समिति, नागपुर	3 प्रतिशत ऋण 1896-97 5 3/4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	19,000.00 1,85,900.00 2,42,800.00	4,47,700.00	25,035.89
31. सी०पी० कृषि और उद्योग सुधार निधि	सचिव शासी निकाय कृषि और उद्योग, नागपुर	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,24,000.00 5,900.00	1,29,900.00	5,174.62
32. ए० सन गार्डिनर स्मारक छात्रवृत्ति निधि	नागपुर का बिशप	5 3/4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण 1983 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	3,800.00 400.00	4,200.00	309.75
33. सौभाग्यवती कृष्णाबाई बाल कृष्ण मुले पुरस्कार निधि	प्रशासक की नियुक्ति, शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के पास विचाराधीन है	5 3/4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण 1983	200.00	200.00	9.50
34. रायबहादुर बन्धुजी जनार्दन बोबस पुरस्कार निधि	--तदैव--	5 3/4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण 1983	900.00	900.00	45.74

7	8	9	10		11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
..	25,035.89	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	24,757.73 278.16 25,035.89	..	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	30
(अ) 5,900.00	11,074.62	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस अन्य अदायगियां	5,117.12 57.50 5,900.00 11,074.62	..	--तदैव-- (अ) यह राशि 5 3/4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1979 की परिशोधन प्राप्तियों की द्योतक है जिसे 5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश कर दिया है।	31
	309.75	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	306.30 3.45 309.75		कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	32
15.08	24.58	सरकार को दी गई फीस	0.12	24.46	--तदैव--	
68.86	114.60	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	.. 0.52 0.52	114.08 ..	--तदैव--	34

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
35. भाउनिंग छात्रवृत्ति और भाउनिंग शिक्षा छात्रवृत्ति निधि	कलक्टर नागपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	11,600.00 2,200.00	13,800.00	528.25
तमिलनाडु					
1. विक्टोरिया जयन्ती छात्रवृत्ति प्रक्षय निधि, मंगलौर	एक समिति जिसके सदस्य हैं. 1. दक्षिण कनारा के जिला न्यायाधीश, (अध्यक्ष) 2. दक्षिण कनारा के जिला बोर्ड के अध्यक्ष 3. मंगलौर नगर परिषद के सभापति, और 4. दक्षिण कनारा के जिला शिक्षा अधिकारी	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	35,400.00	35,400.00	1,062 00
2 जानागल्ला रंगैया चेट्टी कालेजिट छात्रवृत्ति निधि मद्रास	कालेज शिक्षा के निदेशक, मद्रास	6 प्रतिशत तमिलनाडु ऋण, 1984 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946 6 3/4 प्रतिशत तमिलनाडु ऋण, 1992 6 1/2 प्रतिशत तमिलनाडु, ऋण 1989 5 3/4 प्रतिशत ऋण, 2001 7 1/2 प्रतिशत भारत सरकार ऋण, 2010	3,000 00 32,400.00 3,200.00 400.00 2,700.00 9,200.00	50,900 00	2,209.24

7	8		9	10	11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
(ट) 2,200.00	2,728.25	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस अन्य अदायगियां	522.40 5.85 2,200.00 2728.25	..	(ट) यह राशि 5 3/4 प्रतिशत मध्य प्रवेश ऋण, 1979 की परिशोधन प्राप्तियों की द्योतक है जिसे 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश कर दिया गया है।	35
(ठ) 871.77	1933.77	दिया गया ब्याज अन्य अदायगियां	1788.00 10.62 1798.62	135.15	(ठ) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है:— अथ शेष 871.77 छात्रवृत्ति की राशि की वापसी .. 871.77	1
(ड) 3,174.93	5,384.17	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	.. 14.47 14.47	53,69.70	(ड) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :— अथ शेष 3,174.93 कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	2

			रु०	रु०	रु०
3 प्रिग स्मारक अक्षय निधि, मद्रास	विद्यालयी शिक्षा निदेशक, मद्रास और मुख्य शारीरिक शिक्षा निदेशक, मद्रास	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	11,500.00	15,200.00	548 62
		5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,100.00		
		7 1/2 प्रतिशत भारत सरकार ऋण, 2010	2,600.00		
4 जे०एम० बोर्न स्मारक अक्षय निधि, मद्रास	दक्षिण रेलवे के मुख्य अभियन्ता, मद्रास	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	300.00	2,800 00	158.74
		5 3/4 प्रतिशत तमिलनाडु, ऋण, 1982	1200.00		
		5 3/4 प्रतिशत तमिलनाडु, ऋण, 1983	100.00		
		7 1/2 प्रतिशत भारत सरकार ऋण, 2010	1200.00		

	7	8		9	10	11	
	रु०	रु०		रु०	रु०		
(ड)	2,05453	2054.13	अन्य प्रदायगियां दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	1100.00 .. 4.08 1,104.08	1,499.07	(ट) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है:— अथ शेष 954.53 5 3/4 प्रतिशत तमिलनाडु ऋण, 1981 की प्रतिशोधन प्राप्तियां 1,100.00 2,054.53 कालम 6 में दी गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आय कर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	3
(ण)	228.46	387.20	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	. 0.84 0.84	386.36	(ण) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है:— अथ शेष 228.46 आयकर और अधिभार की वापसी 228.46 कालम 6 में दी गई रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	4

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	र
मध्य प्रदेश						
1.	नवाब सुल्तान जहां बेगम शिक्षा प्रबन्ध निधि, भोपाल	गवर्नर बोर्ड जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	9,24,400.00		
		(1) महामान्य सिकन्दर सौलत इफ्तिखार-उल मुल्क नवाब मुहम्मद हमीदुल्ला खां; (2) श्री महावीर प्रसाद वर्मा, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय भोपाल; (3) श्री मुहम्मद अहमद अन्सारी, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय भोपाल; (4) कर्नल यामीनुलमुल्क नबावजादा रशीदुज्ज फरखां बहादुर; और (5) मुतमिदुल इंशाअली काबिह, श्री सैयद माशूक अली महामान्य नवाब भोपाल के सर्फेखास विभाग के सचिव।	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1982	4,24,500.00	13,48,900 00	46,926.74
2.	रामचन्द्र ठाकुर पुरस्कार निधि	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश, भोपाल	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	500.00	500 00	13.00

	7	8		9	10	11	मामला संख्या
	रु०	रु०		रु०	रु०		
(त)	89.18	47,015 92	दिया गया ब्याज सरकार को दी गयी फीस	34,065.00 382.74 34,447.74	12,568.18	(त) यह रकम अव शेष की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	1
	..	13 00	दिया गया ब्याज : सरकार को दी गई फीस	6.42 0.08 6.50	6.50	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	2

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
3.	हार्डिंग पदक निधि	शिक्षा निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल	3 प्रतिशत रूपान्तर ऋण 1946	2,100.00	2,100.00	57.00
4.	महमूद और स्पेंस रजत पदक निधि	जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण 1983	500.00	500.00	26.74
5.	पंडित प्रेमशंकर गंगाशंकर ठाकुर छात्रवृत्ति निधि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद, सभा, दमोह	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	7,100.00	7,100.00	191.00
6.	रेवाशंकर पंड्या हाई स्कूल छात्रवृत्ति निधि	मंडल शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	5,000.00	5,000.00	136.00
7.	लक्ष्मीबाई छात्रवृत्ति निधि	जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	2,600.00	2,600.00	70.00
8	मुखर्जी छात्रवृत्ति निधि	प्रिंसिपल, राजकुमार कालेज, रायपुर	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983	2,400.00		
			3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	8,300.00	10,700.00	349.00

7	8	9		10	11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
..	57.00	दिया गया ब्याज	28.18	28.50	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	3
		सरकार को दी गई फीस	0.32			
			28.50			
(ब) 95.72	122.46	दिया गया ब्याज	26.46	95.72	(ब) यह रकम 4 प्रतिशत मध्य-प्रदेश ऋण, 1971 की खर्च न की गई शेष राशि की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	4
		सरकार को दी गई फीस	0.28			
			26.74			
.	191.00	दिया गया ब्याज	94.43	95.50	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	5
		सरकार को दी गई फीस	1.07			
			95.50			
	136.00	दिया गया ब्याज	67.25	68.00	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	6
		सरकार को दी गयी फीस	0.75			
			68.00			
..	70.00	दिया गया ब्याज	34.61	35.00	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	7
		सरकार को दी गई फीस	0.39			
			35.00			
(द) 44.63	393.63	दिया गया ब्याज	233.87	157.13	(द) यह रकम अवशेष की द्योतक है। कालम 6 में यह दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।	8
		सरकार को दी गई फीस	2.63			
			236.50			

1	2	3	4	5	6	7
				रु०	रु०	रु०
बिहार						
1	बुद्धाश्रम स्मारक निधि	कलक्टर भागलपुर	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1 100.00	1 100.00	
2	राजा रघुनंदन प्रसाद न्यास निधि	मनोनीत कोषाध्यक्ष बिहार प्र० प्रा० स० क० सदाकत आश्रम पटना	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	1 600.00	1 600.00	
3	सर फखरुद्दीन स्मारक स्वर्ण पदक निधि	शिक्षा निदेशक बिहार पटना	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	1 100.00	1 100.00	
उत्तर प्रदेश						
अलीगढ़						
1	तसद्दुक रसूल खां छात्रवृत्ति अक्षय निधि-न्यास	कोषाध्यक्ष मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	20 200.00	20 200.00	3 030.00
*2	सर सैयद अहमद स्मारक न्यास निधि	रजिस्ट्रार मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	1 16 000.00	1 16 000.00	17 400.00
3	सर विलियम मैरिस छात्रवृत्ति अक्षय निधि-न्यास	कुलपति मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	6 400.00	6 400.00	960.00

7	8	9	10	11	मामला संख्या
रु०	रु०	रु०	रु०		
	3 030.00	दिया गया ब्याज 2 999.70 सरकार को दी गई फीस 30.30 3 030.00			
	17 400.00	दिया गया ब्याज 17 226.00 सरकार को दी गई फीस 174.00 17 400.00			
	960.00	दिया गया ब्याज 950.40 सरकार को दी गई फीस 9.60 960.00			

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
इलाहाबाद					
4 रीवा छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट इंटर कालेज इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	4,100 00	4,100 00	..
5 पन्ना छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	5,200 00	5,200 00	..
6 विजयनगरम् छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	प्रधानाचार्य गवर्नमेंट इंटर कालेज, इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	14,800 00	14,800.00	2220.00
7 विजयनगरम् छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	26,000 00	26,000 00	3900 00
वाराणसी					
8 गाधोलाल छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	उपकुलपति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	45 000 00	45,000 00	6750 00
9 काठियावाड़ संस्कृत छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	---तदैव-	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	9 100 00	9,100 00	1365 00

7	8	9		10	11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
	615 00	दिया गया ब्याज	608.80			4
		सरकार को दी गई फीस	6.20			
			615 00			
	780 00	दिया गया ब्याज	772.20			5
		सरकार को दी गई फीस	7.80			
			780 00			
	2,220 00	दिया गया ब्याज	2,197 80			6
		सरकार को दी गई फीस	22.20			
			2,220.00			
	3,900 00	दिया गया ब्याज	3,861 00	..		7
		सरकार को दी गई फीस	39 00			
			3 900 00			
	6,750 00	दिया गया ब्याज	6,682.50	..		8
		सरकार को दी गई फीस	67 50			
			6,750.00			
	1,365 00	दिया गया ब्याज	1,351 30			9
		सरकार को दी गई फीस	13 70			
			1 365 00			

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
10. रीवा छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	5,800.00	5,800.00	870.00
11. नागरी प्रचारिणी सभा अक्षय निधि न्यास	सचिव, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	1,63,100.00	1,63,100.00	24051.00
12. महाराज कुमार सुधांशु शेखर सिंह देव, सोनपुर संपदा के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी उड़ीसा भवन अक्षय निधिन्यास	कुलपति बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	1,600.00	1,500.00	225.00
13. बस्ती की रानी भुवन राज लक्ष्मी देवी अक्षय निधि न्यास	रजिस्ट्रार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	7,300.00	7,300.00	1095.00
पौड़ी गढ़वाल					
14. गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षान्यास निधि	सचिव, गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि, पौड़ी गढ़वाल	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	51,800.00	51,900.00	7,770.00
लखनऊ					
15. नगर शिक्षा अक्षय निधि न्यास' अपर इंडिया, लखनऊ	सचिव, नगर शिक्षा अक्षय निधिन्यास, अपर इंडिया लखनऊ	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	16,600.00	36,000.00	2,490.00
		7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (तीसरा निर्गम)	19,400.00		

7	8	9	10	11	मामले संख्या
रु०	रु०	रु०	रु०		
..	870.00 दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	861.30 81.70 870.00	..		10
..	24,051.00 दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	23,806.30 244.70 24,051.00	..	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गए आय कर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।	11
..	225.00 दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	222.70 2.30 225.05	..		12
..	1,095.00 दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	1,084.00 11.00 1,095.00	..		13
..	7,770.00 दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	7,692.30 77.70 7,770.00	..		14
..	2,490.00 दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	2,465.10 24.90 2,490.00	..		15

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
16 कप्तान कु० इन्द्रजीत सिंह, एम० सी० आई० एम० एस०, स्मारक अनुसंधान छात्रवृत्ति अक्षय निधि	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	1,06,060.00	1,06,0000.00	15,990.00
मिर्जापुर					
17. गिरोही कायस्थ पाठशाला अक्षय निधि न्यास	प्रबन्धक समिति, जिसके मिर्जापुर के कलक्टर पदेन सभापति हैं और स्व० मुन्शी बिन्देश्वरी प्रसाद प्लीडर के संपदा के निष्पादक जिसके सदस्य हैं।	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	1,600.00	9,150.00	240.00
		7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरा निर्गम)	7,550.00		
पांडिचेरी		एन०एस०ए०आर०सी०			
1. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये विशेष निधि	सचिव, राज्य और सैनिक बोर्ड, पांडिचेरी	5½ प्रतिशत करमुक्त ब्याज वाले कृषि पुनर्वित्त ब.पत्र	1,000.00	1,000.00	
2 डा.टर एम० के० ए.स-मायन स्मारक पुरस्कार निधि	प्रधानाचार्य, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान, पांडिचेरी	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,000.00	1,000.00	
3. श्रीमती सुशीला सलवा-राजमनी मावनार निधि	—तदैव	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,000.00	1,000.00	
4 श्री एम० मल्लारावअनो चेट्टियार स्मारक पदक निधि	तदैव	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,000.00	1,000.00	

7	8	9		10	11	मामला संख्या
रु०	रु०		रु०	रु०		
..	15,990.00	दिया गया ब्याज	15,830.10	.		16
		सरकार को दी गई फीस	159.30			
			15,990.00			
..	240.00	दिया गया ब्याज	237.60			17
		सरकार को दी गई फीस	2.40	—		
			240.00			
..	.			--	ब्याज की वसूली के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।	1
..	..			..	—तदैव—	2
..	..	..		..	—तदैव—	3
..	..	..		.	—तदैव—	4

बयान

भारत और पाकिस्तान के बीच केन्द्रीय पूर्त अक्षय निधियों से संबंधित प्रतिभूतियों का विभाजन न हो सकने के कारण प्रतिभूतियों की सूची तैयार नहीं की जा सकी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण के भाग II में प्रदर्शित बकाया रकमें; भारतीय पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल के पास धारित संबंधित पूर्त अक्षय निधियों के ब्योरेवार आंकड़ों से मेल खाती हैं।

[सं० एफ 1/1/82 टी ओ ई०]

मंगलदास पाल,

कोषपाल, भारतीय पूर्त अक्षय निधि

(Office of the Treasurer of Charitable Endowments for India)

New Delhi, the 15th June, 1982

S.O. 446.—The following list of properties and of securities as on the 31st March, 1982 and abstract of accounts of interest for the year 1981-82 in respect of Charitable Endowments (Central) held by the Treasurer of Charitable Endowments for India or his agents under the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), are published for general information.

Part I.—List of properties other than Securities

Sl. No.	Particulars of Vesting order No	Particulars of Vesting order Date	Name of Endowment	Administrators of Property	Property held Description	Property held Value	Property held Annual Income, if known	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIA								
						Rs.	Rs.	
1.	Ministry of Health Notification No. F. 14-26/61-Instt. as amended by the Ministry of Health & Family Welfare Notification No. S. 22020/11/76-MC(MS)	31-8-1962 31-8-1977	Pasteur Institute of India	Administrator of the Pasteur Institute of India.	1. Anti-Rabies Research Centre Building, Kasauli	2,23,200.00	Nil	
					2. Lady Linlithgo Sanatorium Building, Kasauli.	22,18,700.00		
					3. Shelton Lodge, Kasauli.	26,000.00		
2.	Ministry of Defence Notification No S.R.O. 250	19th July, 1960	Farm Fund of the Kumaon Regimental Farm at Kamola and Udaipuri.	Board of Administration of the Fund.	Kamola Tehsil Kaladhugi, District Nainital,			
					1. Dispensary (30 ft.x24 ft.)	4,000.00	Nil	
					2. Thimayya Lodge (30 ft.x24 ft.)	4,000.00		
					3. Guest House No. 1 (30 ft.x35 ft.)	5,000.00		
					4. Guest House No. 2 (28 ft x26 ft.)	3,500.00		
MAHARASHTRA								
1.	G.I.H.D. Education No. 433	27th May, 1909	The Indian Institute of Science.	The Collector of Bombay, Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H Tata.	"Victoria Buildings"—All that piece of freehold, situated in the Fort on the eastern side of Parsi Bazar Street, at or near the Elphinstone Circle with the messuages, tenements and buildings thereon known as "Victoria Buildings" containing by admeasurement 482-3/4 sq. yards or thereabouts.	Not known	Nil	
2 & 3	Do	Do	Do.	Do.	"Albion Place and Alexandra Terrace"—All that piece of land, situated at Byculla on the eastern side of Parel Road with the messuages, tenements and buildings thereon, with their out-houses and stables known as "Albion Place and Alexandra Terrace" containing by admeasurement 11,101 sq. yards or thereabouts	Do.	Do.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
3A.	G.I.H.D. Education No. 433.	27th May, 1909	The Indian Institute of Science.	The Collector of Bombay, Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H Tata.'	New Construction being a building now known as "Hotel Heritage" built on portion of land admeasuring 11,104 sq. yards or thereabouts situated at Byculla on the eastern side of Parel Road now known as Dr Ambedkar Road	19,00,000.00	1,89,120.00	
4 & 5.	Do.	Do	Do.	Do.	"Reay House" and "Sandhurst House" —All that piece or parcel of leasehold land, situated on the Apollo Reclamation, in the Island of Bombay; containing by admeasurement 2,004-8/9 square yards with the two buildings thereon, known as 'Reay House" and 'Sandhurst House".	Not known	Nil	
6 & 7	Do.	Do	Do.	Do	"Rosevelt House or Ezra House"—All that piece or parcel of leasehold land, situated on the Apollo Reclamation, containing by admeasurement 533 square yards and 3/9 of another square yard , with the buildings thereon, known as the "Rosevelt House or Ezra House" and secondly all that piece of leasehold land also situated on the Apollo Reclamation, in the Island of Bombay containing by admeasurement 573 square yards and 3/5 of another square yard.	Do.	Do.	
8 & 9.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Sargent House" and "Jenkins House"—All that piece or parcel of land, situated on the Apollo Reclamation in the Island of Bombay containing by admeasurement 3487-2/9 square yards with the buildings thereon known as "Sargent House" and "Jenkins House".	Do.	Do.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
10.	G.I.H.D. Education No. 433	27th May, 1909	The Indian Institute of Science	The Collector of Bombay, Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H. Tata.	"New Shamji Buildings" now known as "Station Terraces." Sleater Road. All that piece of land of Foras tenure admeasuring 2,290 square yards or thereabouts with the several messuages, tenements or dwelling houses, known as "New Shamji Buildings Extension" now known as the "Station Terraces" situated on the South side of the Sleater Road, Bombay.	Not known.	Nil	
11.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Candy House"—All that piece of leasehold land, situated on the Apollo Reclamation, in the Island of Bombay, containing by admeasurement 529-6/9 square yards known as 'Candy House	Do.	Do.	
12 & 13.	Do.	Do	Do.	Do.	"Land near Albion Place and Alexandra Terrace"—All that piece of land containing by admeasurement 8,570 square yards or thereabouts, registered by the Collector of Bombay with other land situated at Byculla on the eastern side of Parel Road in the city of Bombay together with messuages, tenements and dwelling houses standing thereon known as "Land near Albion Place and Alexandra Terrace."	Do.	Do.	107-8/9) square yards acquired by the Land Acquisition Officer for the City of Bombay.
14.	G.I.H.D. Education No. 433	27th May, 1909	The Indian Institute of Science	The Collector of Bombay Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H. Tata	"Land at Parel Tank Road" Firstly—All that piece of land admeasuring 67,057 Square yards or thereabouts whereof 7,021 sq. yards is Government Toka land and 2,189 sq. yards is recently assessed	Not known	Nil	Out of 74,686 square yards 15,575.80 square yards acquired by Government under Land Acquisition Act for the construction of the work of the Tata Hydro-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
					Government land and remaining is Inam land situated at Parel on the Public road leading to Parel Government Tank known as "Land at Parel Tank Road" Wageshri Hill. Secondly—All that piece of vacant Inam land admeasuring 6,005 square yards or thereabouts situated at Parel. Thirdly—All that piece of vacant land of the Government Toka Tenure containing by admeasurement 1,058 square yards or thereabouts situated at and on the south side of Golangi Hill Road at Parel in the city of Bombay. Fourthly—All that piece of vacant Government Toka land containing by admeasurement 566 square yards or thereabouts situated at and on the south side of Golangi Hill Road at Parel in the City of Bombay.			Electric Power Supply Co. Ltd. in connection with its transmission lines and 37,471.52 square yards subsequently acquired in 1922 by the Land Acquisition Officer. A portion of the land at Parel Tank Road admeasuring 2,043.88 square yards of C/S No. 1/202 part and 623.33 square yards of C.S. No. 203 part has been acquired by the Bombay Municipal Corporation for the purpose of construction of Water Reservoir under Section 12(2) of the Land Acquisition Act 1 of 1894.
15.	Do.	Do.	Do.	Do.	All that piece of land situated on the West side of the Colaba Road at Colaba within the city and Registration Sub-district of Bombay containing by admeasurement 2,020 sq. yards or thereabouts and bounded as follows: that is to say on or towards the North by the Property of the Trustees of Sir Currimbhoy Ebrahim Baronetcy Trust, on or towards the South by the Road of Police Chowkey on or towards the East by Colaba Road and on or to-	18,44,103.28	1,99,675.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
					wards the West by Wodehouse Road, and which said piece of Land is registered in the books of the collector of Bombay under Rent Roll No. 8509 and bears Cadestal Survey No. 48 of Colaba Division together with the buildings and erections standing thereon assessed by the Municipality of Bombay under Award Nos. 213, 214 and Street Nos. 158 and 125 of Colaba Road and Wodehouse Road and Street No. 154 of Lower Colaba Road respectively.			
16	G.R.E.D. No. 452	7th March, 1906	Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution	The Secretary, Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.	A piece of land with dwelling house and building situated at Hornby Road, Fort, Bombay, admeasuring 1,698 square yards.	Not known	Nil	
17.	G.R.E.D. No. 1778	10th July, 1912	Do.	Do.	All that piece or parcel of freehold land with messuage, tenement or stables standing thereon, situated at Gola Lane, Fort, Bombay admeasuring 173 and 62 square yards or thereabouts.	Do.	Do.	
TAMIL NADU								
1.	No. 46-Education and No 389-Education	5th April, 1904 and 25th June, 1904	Endowment of the Madras Military Female Orphan Asylum.	Secretary and Correspondent, St. George School and Orphanage, Madras.	Land in Madras bearing Survey No. 232 and measuring 15 cawnies 18 grounds and 1678 sq ft. with the buildings thereon known as "Madras Military Female Orphan Asylum"	Do.	Do.	The property is in the occupation of the Civil Orphan Asylum in consideration of the maintaining and educating 30 additional girls in addition to the girls of the Asylum such as were formerly admitted to the Madras Military Female Orphan Asylum.

1	2	3	4	5	6	7	8
UTTAR PRADESH						Rs.	Rs.
1.	Government of UP Education Deptt. Notification Nos. 602/XV-301 808-G/XV/619/1923	2nd April, 1918 and 29th November, 1923 respectively	Giraundi Kayastha Pathshala Endowment Trust, Mirzapur	A Committee of Management consisting of the Collector, Mirzapur as *Ex-Officio* Chairman and Executors of the Estate of the late Munshi Bindeshwari Prasad, Pleader	(a) Three houses situated in Mohalla Welleslygunj, Distt. Mirzapur bounded as follows:—		
					(1) South—House of Sri Piyare Lal North—House of Musammat Jhunna, West—Government Road, East—House of Sri Sumer Sonar.	600.00	36.00
					(2) South—House of Munshi Bindeswari Prasad, Vakil, North—Mosque, West—House of Shri Rameshwar Teli, East—Road.	600.00	36.00
					(3) South —House of Sri Budhu, North—House of Munshi Bindeshwari Prasad Vakil, West—House of Musammat Umrao, East—Road.	600.00	36.00
					(b) A grove situated in Mauza Giraundi, Tehsil Chunar, District Mirzapur.	600.00	15 00
					(c) Pathshala in Mauza Giraundi, Tehsil Chunar, District Mirzapur situated in the grove mentioned in (b) above.	50.00	Nil

PUNJAB

Pending apportionment of properties relating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan the list of properties could not be prepared.

PART II—*List and abstract*

Case No.	Name of endowment	Persons in whose behalf held	Particulars of Securities		Total of Securities	Cash: Interest or dividend realised
1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
INDIA						
1.	Khandpara State Trust Fund	Board of Trustees, Khandpara State Trust Fund	5-Year Post Office Time Deposit	30,600 00	30,600.00	3,060.00

Account of Securities

Receipts: Other Cash receipts	Receipts: Total Cash receipts	Cash Expenditure: Payments		Balance in Cash	Remarks	Case No.
7	8	9		10	11	12
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
..	3,060.00	Interest remitted	3,029.40	..	..	1.
		Fee paid to Govt.	30.60			
			3,060.00			

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
2. Armed Forces Benevolent Fund	Armed Forces Benevolent Fund General Committee	3% Conversion Loan, 1946	8,00,400.00	8,00,400.00	36,018.00
3. St. Dunstan's (India) Fund.	Board of Trustees, St. Dunstan's (India) Fund.	3% Conversion Loan, 1946 4¾% Loan, 1989	92,900.00 15,000.00	1,07,900.00	4,821.00
4. Thomas Reed Bell Memorial Fund.	The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.	3% Conversion Loan, 1946	3,100.00	3,100.00	139.50
5. Pasteur Institute of India	Administrator of the Pasteur Institute of India.	3% Conversion Loan 1946 5 Year Post Office Time Deposit.	66,900.00 30,750.00	97,650.00	6,323.97
6. National Foundation for Teachers' Welfare.	General Committee National Foundation for Teachers' Welfare	5 Year Post Office Time Deposit	594,47,550.00	594,47,550.00	61,47,685.90
7. Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.	Committee of Management of the Fund.	5 Year Post Office Time Deposit	7,00,000.00	7,00,000.00	74,653.00

7	8	9	10		11	12
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
..	36,018.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	35,657.82 360.18 36,018.00	..	..	2.
..	4,821.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	4,772.78 48.22 4,821.00	..	The interest show (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	3.
..	139.50	Interest remitted Fee paid to Govt.	138.09 1.41 139.50	..	..	4.
(a)1,10,900.00	1,17,223.97	Interest remitted Fee paid to Govt.	6,260.72 63.25 6,323.97	1,10,900.00	(a) Represents redemption proceeds of 4% Loan, 1980 in respect of which the instructions for reinvestment are still awaited from the Fund authorities.	5.
..	61,47,685.90	Interest remitted Fee paid to Govt.	60,86,209.04 61,476.86 61,47,685.90	..	..	6.
..	74,653.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	73,906.47 746.53 74,653.00	..	..	7.

2	3	4	5		6
			Rs.	Rs.	Rs.
8. Banubai Byramji Kanga Trainees' Welfare Fund of the Training Centre for the Adult Blind, Dehra Dun.	The Superintendent Training Centre for the Adult Blind, Dehra Dun.	5-Year Post Office Time Deposit. 6% West Bengal State Electricity Board Bonds, 1982.	49,950.00 4,400.00	54,350.00	5,352.77
9. Flag Day Fund	Managing Committee, Flag Day Fund	3% Conversion Loan, 1946	4,20,000.00	4,20,000 00	17,640.00
10. War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund.	Managing Committee, War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund.	5-Year Post Office Time Deposit.	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00	20,00,000.00
11. Lady Hardinge Hospital for Women and Children, Delhi, Fund.	Board of Administration, Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital.	5-Year Post Office Time Deposit.	1,02,650.00	1,02,650.00	10,265.00
12. National Children's Fund	Board of Trustees of the Fund.	5-Year Post Office Time Deposit.	26,00,000.00	26,00,000.00	2,79,387.50
13. The Indian People's Famine Trust.	Board of Management, New Delhi.	3% Conversion Loan, 1946	32,78,400.00	32,78,400.00	1,42,610.00

7	8	9		10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
..	5,352.77	Interest remitted Fee paid to Govt.	5,299.24 53.53 5,352.77	..		8
..	17,640.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	17,463.60 176.40 17,640.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	9
..	20,00,000.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	19,80,000.00 20,000.00 20,00,000.00	..		
..	10,265.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	10,162.35 102.65 10,265.00	..		
(b)24,00,000.00	26,79,387.50	Interest remitted Fee paid to Govt. Other payments	2,76,593.62 2,793.88 24,00,000.00 26,79,387.50	..	(b) Reparesents : amount received from Fund authorities since invested in 5-Year Post office Time Deposit.	
..	1,42,610.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	1,41,183.90 1,426.10 1,42,610.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
14.	The Jewish Charitable Endowment Fund.	Mussa Board, Calcutta.	3% Conversion Loan, 1946 5-Year Post Office Time Deposit	38,000.00 59,350.00	97,350.00	3,083.37
15.	National Workers' Relief Fund.	National Workers, Relief Fund Board, Chandigarh.	5-Year Post Office Time Deposit	20,750 00	20,750 00	.
MAHARASHTRA						
1.	Indian Institute of Science (Bangalore Properties).	The Council of the Indian Institute of Science, Bangalore.	5-Year Post Office Time Deposit.	2,150.00	2,150.00	231.60
2.	Indian Institute of Science (Bombay Properties).	The Council of the Indian Institute of Science, Bangalore.	3% Conversion Loan 1946 5½% Loan, 2000. (Old) 5¾% Maharasstra Loan 1982. 5-Year Post Office Time Deposit.	10,22,800 00 1,40,300.00 57,800.00 10,700.00	12,31,600 00	38,703.00
3.	Fakirjee Cowasjee of Karachi Scholarship Fund.	Captain Superintendent, Trainingship 'Rajendra" off New Ferry Wharf, Bombay-9.	3% Conversion Loan, 1946	60,000.00	60,000.00	1,800.00

7	8	9		10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
(c)59,394.04	62,477.41	Interest remitted Fee pid to Govt. Other payments	3,052.54 30.83 59,394.04 62,477.41	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source. (c) Represents : pre-mature sale proceeds of 5 3/4%. West Bengal Loan 1983 for Rs. 59,700.00, received only Rs. 59,394.04 out of which Rs. 59,350.00 since re-inserted in 5-year P.O.T.D. and balance of Rs. 44.04 remitted to the Fund authorities.	14
(d)20,775.38	20,775.38	Deposit in 5-Year P.O.T.D. Balance remitted to Fund authorities	20,750.00 25.38 20,775.38	..	(d) Represents : Transfer of Share of Union Territory, Chandigarh to the Treasurer of Charitable Endowments for India out of which Rs. 20,750.00 invested in 5-year P.O. T.D. and balance of Rs. 25.38 remitted to the Fund authorities.	15
..	231.60	Interest remitted Fee paid to Govt.	229.28 2.32 231.60	..		1
27.02	38,730.02	Interest remitted Fee paid to Govt.	38,274.23 428.77 38,703.00	27 02	(e) Represents 27.02 Opening Balance The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	2
..	1,800.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	1,782.00 18.00 1,800.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at source.	3

1	2	3	4	5		6
				Rs	Rs.	Rs.
4.	Chatfield Memorial Prize Fund.	1. Principal, Training College for Men, Poona. 2. Principal Training, College for Men, Dharwar. 3. Principal, Training College for Men, Ahmedabad.	3% Conversion Loan, 1946	200 00	200.00	6 00
5.	Ganesh Balwant Limaye Scholarship Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Pune.	3% Conversion Loan, 1946	56,000.00	56,000.00	1,512.00
6.	Sir William Moore Memorial Fund.	Director of Health Services, Maharashtra, State Bombay.	3% Conversion Loan, 1946	1,100.00	1,100.00	29.00
7.	Kazi Shahabudin Endowment for the encouragement of Education among Mohamedans in the Bombay Presidency.	Director of Education, Maharashtra State, Pune.	3% Conversion Loan, 1946 5-Year Post Office Time Deposit	1,45,300.00 5,100.00	1,50,400.00	4,054.62
8.	Fund for Prizes in English in connection with the S.S.C. Examination.	Director of Education, Maharshtra State, Pune.	3% Conversion Loan, 1946 5-Year Post Office Time Deposit.	400.00 3,000 00	3,400.00	333.25
9.	Sir Sassoon David Trust Fund for Agriculture and Educational purposes.	Board of Trustees of the Fund C/o Secy. to Govt. of Maharashtrra, Agriculture and Cooperation Deptt. Bombay.	5 3/4% Mahahrastra Loan, 1983	7,51,100.00	7,51,100 00	38,870.24

7	8	9	10		11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
59.45	65 45	Fee paid to Govt.	0.06 0 06	(f)65.39	(f) Represents 65.39 Opening balance	4
..	1,512.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	1,495.20 16.80 1,512.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at source.	5
..	29.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	28.66 0.34 29.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at source.	6
(g) 5,100 00	9,154 62	Interest remitted Fee paid to Govt. other payments	4,009. 55 45. 07 5,100.00 9,154.62	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source. (g) Represents : Redemption proceeds of 5¾% Maharashtra loan 1981 since re-invested in 5-Year P.O. T.D.	7
..	333 25	Interest remitted Fee paid to Govt.	329.90 3.35 333.25		The interest shoWn (under cloumn 6) is exclusive fo Incom e-Tax and Surcharge deducted at source.	8
..	38,870.24	Interest remitted Feed paid to Govt.	38,438.36 431.88 38,870.24	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surchrge deducted at source.	9

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
10. After-care Fund in connection with the Bombay State Probation and After-care Association.	President Maharashtra State Probation and After Care Association, B.I.T. Block No. 33 King's Circle, Matunga, Bombay-19.	3% Conversion Loan, 1946. 5-Year Post Office Time Deposit.	7,000.00 14,000.00	21,000.00	1,698.60
11. Imperial Indian Relief (Scholarship) Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Pune.	3% Conversion Loan, 1946.	25,200.00	25,200.00	680.00
12. Savitribai Krishnarao Uplap Scholrship Fund.	Do.	3% Conversion Loan, 1946	12,800.00	12,800.00	346.00
13. Bombay Province Agricultural Show Fund.	Director of Agriculture, Maharashtra State, Pune.	3% Conversion Loan 1946. 7-Year Small Savings Bond.	4,16,000.00 2,000.00	4,18,000.00	11,232.00
14. Dr. Ramachandra Shivaji Pordi Scholarship Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Pune,	3% Conversion Loan 1946.	11,100.00	11,100.00	299.00
15. Sir Cusrow Wadia Trust Fund.	Chairman of the Governing Body of the Fund C/o Secy. to Govt. of Maharashtra, Agriculture & Co-operation Deptt. Bombay.	6% Maharashtra State Development Loan 1986.	12,94,200.00	12,94,200.00	69,886.00

7	8	9		10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
..	1,698.60	Interest remitted Fee paid to Govt.	1,681.41 17.19 1,698.60	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and Surcharge deducted at source.	10
..	680.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	672.44 7.56 680.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and Surcharge deducted at source.	11
..	346.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	342.16 3.84 346.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and surcharge deducted at source.	12
..	11,232.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	11,107.20 124.80 11,232.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	13
..	299.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	295.66 3.34 299.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	14
(h)42.00	69,928.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	69,109.48 776.52 69,886.00	42.00	(h) Represents opening balance. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	15

1	2	3	4	5		6
				Rs.	Rs.	Rs.
16.	Post-War Services Reconstruction Fund (Rajasthan Share).	Secretary of the Fund C/o Maharashtra State S.S. & A. Board, Pune-1.	5 3/4 Maharashtra Loan, 1982. 3% Conversion Loan 1946. 6% Maharashtra Loan 1984.	6,400.00 1,200.00 3,500.00	11,100.00	552.00
17.	War Memorial Fund for Indian Merchant Seamen 1947.	Committee of Management of the Indian Sailors' Home Society, Masjid Bunder, Siding Road, Bombay-9.	3% Conversion Loan 1946.	21,32,900.00	21,32,900.00	57,589.00
18.	Home Mehta Victory Thanks giving Fund (Rajasthan Share).	Secretary of the Fund C/o Maharashtra State S.S. & A. Board, Pune-1.	3% Conversion Loan 1946. 5 3/4% Loan 2003. 6% Maharashtra Loan 1984.	800.00 100.00 400.00	1,300.00	49.47
19.	L. V. Mandke Prize Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Pune.	3% Conversion Loan 1946.	1,600.00	1,600.00	44.00
20.	Miss Manikbai Shinde Prize Fund.	Do.	3% Loan 1896-97	1,000.00	1,000.00	26.00
21.	Maratha War Memorial Fund.	Hony. Secretary, Maratha War Memorial Fund The Maratha Light Infantry Regimental Centre, Belgaum.	5 1/2% Loan. 2000. (Old) Fixed Deposit with State Bank of India, Bombay.	9,100.00 3,26,225.72	3,35,325.72	29,810.74
22.	Sh. M. V. Joshi Trust Fund.	Principal, Agricultural College, Pune.	3% Conversion Loan 1946. 5 3/4% Loan 2002.	12,800.00 500.00	13,300.00	372.74

7	8	9		10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
(I)35.00	587.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	545.86 6.14 552.00	35.00	(I) Represents opening balance. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	16
.	57,589.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	56,949.12 639.88 57,589.00	..	The interest show (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	17
(J)4.00	53.74	Interest remitted Fee paid to Govt.	49.20 0.54 49.74	4.00	(J) Represents opening balance The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	18
..	44.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	43.52 0.48 44.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	19
..	26.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	25.70 0.30 26.00	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	20
..	29,810.74	Interest remitted Fee paid to Govt.	29,512.14 298.60 29,810.74	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	21
..	372.74	Interest remitted Fee paid to Govt.	368.62 4.12 372.74	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	22

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
23.	Miss Clarke Memorial Nursing Fund.	Chairman, Bombay Branch of the National Association for supplying Female Medical Aid and Instruction s to the Women of India, C/o. Shri R. N. Bhavnagri, S. Billimoria & Co. Chartered Accountants 113, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.	3% Conversion Loan 1946. 11,000.00	11,000.00	296.00
24.	Barjorji Maneckji Sutaria Prize Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Pund.	3% Conversion Loan 1946. 2,000.00	2,000.00	54.00
25.	Campbell Memorial Medal Fund.	Committee of Management of the Asiatic Society of Bombay Town Hall, Bombay-1.	5 3/4% Maharashtra Loan 1984. 4,900.00	4,900.00	253.74
26.	Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution.	Secretary, Sir, J.J.P.B. Institution, 209 Dr. Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Bombay.	13 State Bank Shares. 1,300.00 3% Loan 1896-97. 6,900.00 4 3/4% Loan 1989. 500.00 6% Maharashtra Loan 1984. 3,000.00 5 Year Post Office Time Deposit. 11,43,550.00 5 3/4% Loan 2001. 8,80,800.00 5 3/4% Maharashtra Loan 1982. 11,400.00 6% Bombay Municipal Debentures 1983. 20,500.00 5 1/2% Loan 1999. 10,500.00 5 3/4% Loan 2002. 3,400.00 6% Loan 1998. 11,300.00 5 3/4% Loan 2003. 15,200.00 5 3/4% Maharashtra Loan 1985. 500.00 6% Maharashtra Loan 1985 500.00	21,09,350.00	1,46,223.06

7	8	9	10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
..	296.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	292.70 3.30 296.00	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Incometax and S Surcharge deducted at source.	23
..	54.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	53.40 0.60 54.00	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	24
..	253.74	Interest remitted Fee paid to Govt.	250.92 2.82 253.74	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.	25
(K) 3,54,600.25	5,00,823.31	Interest remitted Fee paid to Govt. Other payments 10% Income-tax deduction at Source	1,38,983.82 1,462.24 3,54,600.00 5,777.00 5,00,823.06	0.25 (K) Represents 0.25 Opening Balance 3,36,200.00 Redemption proceeds of 6% M.S.E.B. Bonds 1981 500.00 Redemption proceeds 4% Loan 1981 8,900.00 5 3/4% Maharashtra loan 1981 9,000.00 10% 5 year P.O.T.D. 3,54,600.25	26

1	2	3	4	5		6
				Rs.	Rs.	Rs.
27.	Bombay Branch of the National Association for Supplying Female Medical Aid and Instruction to the Women of India.	Treasurer of the Bombay Branch of the National Association C/o. Shri R.N. Bhavnagri S.B. Billimoria and Co., 113 M.G. Road, Bombay-1.	3% Conversion Loan 1946. 5-year Post Office Time Deposit	2,18,100.00 30,000.00	2,48,100.00	6,665.50
28.	Rustomji Jamsetjee Jejeebhoy Gujarati School Fund.	Secretary, Sir J.J. Parsee Benevolent Institution, 209, Dr. D. N. Road, Fort, Bombay.	3% Conversion Loan 1946.	72,000.00	72,000.00	1,944.00
29	King Edward Memorial Fund maintained by Ex-Sangli State.	Director of Education, Maharashtra State, Pune.	3% Conversion Loan 1946. 3% Loan 1896-97.	49,100.00 1,200.00	50,300.00	1,357.00
30.	C.P. & Berar King Edward Memorial Society Fund.	Secretary to the Governing Body of the King Edward Memorial Society Nagpur.	3% Loan 1896-97. 5¾% M.P. Loan 1983. 3% Conversion Loan 1946.	19,000.00 1,85,900.00 2,42,800 00	4,47,700.00	25,035.89
31.	C. P. Agriculture and Industries Improvement Fund.	Secretary to the Governing Body of the Society of Agriculture and Industries Nagpur.	3% Conversion Loan 1946. 5-year Post-office Deposit Deposit	1,24,000.00 5,900.00	1,29,900.00	5,174.62

7	8	9	10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
(L) 30,000.00	36,665.50	Interest remitted Fee paid to Govt. Other payments	6,591.43 74.07 30,000.00 36,665.50	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at source. (l) Represents: Redemption proceeds of 5-3/4% Maharashtra loan 1981 Since re invested in 5-year P.O.T.D.	27
.	1,944 00	Interest remitted Fee paid to Govt.	1,922.40 21.60 1,944.00	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and Surcharge deducted at source.	28
..	1,357.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	1,341.90 15.10 1,357.00	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and Surcharge deducted at source.	29
..	25,035.89	Interest remitted Fee paid to Govt.	24,757.73 278.16 25,035.89	.. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and Surcharge deducted at source.	30
(m) 5,900.00	11,074.62	Interest remitted Fee paid to Govt. Other payments	5,117.12 57.50 5,900.00 11,074.62	.. (m) Represents: Redemption proceeds of 5-3/4% M.P. Loan 1979 Since re-invested in 5-year P.O.T.D.	

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
32.	Anson Gardiner Memorial Scholarship Fund.	Bishop of Nagpur	5¾% M.P. Loan 1983. 3% Conversion Loan 1946.	3,800.00 400.00	4,200.00	309.75
33.	Saubhagyawati Krishnabai Bal Krishna Sule Prize Fund.	Appointment of the Administrator is under consideration of Education Department Madhya Pradesh.	5¾% M.P. Loan 1983	200.00	200.00	9.50
34.	R.B. Bhanduji Janardhan Chaubol Prize Fund.	Appointment of the Administrator is under consideration of Education Department, Madhya Pradesh.	5-¾% M.P. Loan 1983.	900.00	900.00	45.74
35.	Browning Scholarship and Browning Teachers Scholarship Fund.	Collector, Nagpur.	3% Conversion Loan 1946. 5-Year Post office Time-Deposit.	11,600.00 2,200.00	13,800.00	528.25
TAMIL NADU						
1.	Victoria Jubilee Scholarship Endowment Fund at Mangalore.	A Committee consisting of (1) Dt. Judge, South Kanara, (2) President, District Board, S. Kanara (3) The Chairman, Municipal Council, Managalore and (4) District Educational Officer, South Kanara with the District Judge, South Kanara as President.	3% Conversation Loan 1946	35,400.00	35,400.00	1,062.00
2.	Jonnagadla Rangiah Chetty Collegiate Scholarship Endowment, Fund at Madras.	The Director of Collegiate Education, Madras.	6% Tamilnadu Loan 1984. 3% Conversion Loan 1946. 6-¾% T.N. Loan 1992. 6-1/2% Tamilnadu Loan 1989. 5-3/4% Loan 2001. 7-1/2% Govt. of India Loan, 2010.	3,000.00 32,400.00 3,200.00 400.00 2,700.00 9,200.00	50,900.00	2,209.24

7	8	9		10	11	Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.		
..	309.75	Interest remitted Fee paid to Govt.	306.30 3.45 309.75	..	The interest shown (under Col. 6) is exclusive of Income-Tax and surcharge deducted at source.	
15.08	24.58	Fee paid to Govt.	0.12	24.46	Do.	
68.86 ..	114.60	Interest remitted Fee paid to Govt.	.. 0.52 0.42	114.08	The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax surcharge deducted at source.	34
(n) 2,200.00	2,728.25	Interest remitted Fee paid to Govt. Other payments	522.40 5.85 2,200.00 2,728.25	..	(n) Represents : Redemption proceeds of 5¾% M.P. Loan 1979 Since re-interested in 5-Year P.O.T.D.	35
(o) 871.77	1,933.77	Interest remitted Other payments	1,788.00 10.62 1,798.62	135.15	(o) Represents. 871.77 Opening balance .. Refund of Scholarship amount 871.77	1
(p) 3,174.93	5,384.17	Interest remitted Fee paid to Govt.	.. 14.47 14.47	5,369.70	(p) Represents. 3,174.93 Opening balance. The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-Tax and Surcharge deducted at source.	2

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
3.	Grigg Memorial Endowment Fund at Madras.	The Director of School Education, Madras & the Chief Inspector of of Physical Education, Madras.	3 % Conversion Loan 1946. 5-Year Post office Time-Deposit 7-1/2% Govt. of India Loan, 2010.	11,500.00 1,100.00 2,600.00	15,200.00	548.62
4.	J.M. Bourne Memorial Endowment Fund at Madras.	The Chief Engineer of the Southern Railway, Madras	3% Conversion Loan 1946. 5-3/4% Tamilnadu Loan 1982. 5-3/4% Tamilnadu Loan, 1983. 7-1/2% Govt. of India Loan 2010.	300.00 1,200.00 100.00 1,200.00	2,800.00	158.74
	MADHYA PRADESH					
1.	Nawab Sultan Jahan Begum Education Endowment, Bhopal	Board of Governors consisting of the following:— (1) His Highness Sikander Saulat Iftikhar-ul-Mulk Nawab Mohammad Hamidullah Khan, (2) Shri Mahabir Praasad Verma formerly Judge of the Bhopal High Court, (3) Shri Mohammed Ahmed Ansari formerly Judge of the Bhopal High Court. (4) Colonel, Yameenul Mulk Nawabazada Rashiduz-Zafar Khan Bahadur, and (5) Mutamidul-Insha Aali Quadar Shri Syed Mashuq Ali, Secretary Sarf-e-Khas of His Highness the Nawab of Bhopal.	3% Conversion Loan 1946 5-3/4% M.P. Loan 1982	9,24,400.00 4,24,500.00	13,48,900.00	46,926.74

7	8	9		10	11		Case No.
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.			
(q) 2,054.53	2,603.15	Other Payments Interested remitted Fee paid to Govt.	1,100.00 .. 4.08 ——— 1,104.08	1,499 07	(q) Represents 954.53 1,100.00 ——— 2,054.53 The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at source.	 Opening balance. Redemption proceeds of 5¾% T.N. Loan 1981	3
(r) 228.46	387.20	Interest remitted Fee paid to Govt.	.. 0.84 ——— 0.84	386 36	(r) Represents 228.46 ——— 228.46 The interest shown (under column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at source.	 Openinse balance.	4
(s) 89.18	47,015.92	Interest remitted. Fee paid to Govt.	34,065.00 382.74 ——— 34,447.74	12,568.18	(s) Represents Opening Balance. The interest shown (under Column 6) is exclusive of Income-tax and Surcharge deducted at sources.		1

1	2	3	4	5	6	
				Rs.	Rs.	Rs.
2.	Ram Chandra Thakur Prize Fund.	Secretary, Board of Secondary Education, M.P., Bhopal.	3% Conversion Loan 1946	500.00	500.00	13.00
3.	Hardinge Medal Fund	Director of Public Instructions, M.P. Bhopal.	3% Conversion Loan 1946	2,100.00	2,100.00	57.00
4.	Meyhew and Spence Silver Medal Fund.	District Educational Officer Bilaspur.	5¾% M.P. Loan 1983	500.00	500.00	26.74
5.	Pandit Prem Shankar Ganga Shankar Thaker Scholarship Fund.	Chief Executive Officer, Janapada Sabha, Damoh.	3% Conversion Loan 1946	7,100.00	7,100.00	191.00
6.	Rewa Shankar Pandya High School Scholarship Fund.	Divisional Superintendent of Education, Jabalpur.	3% Conversion Loan 1946	5,000.00	5,000.00	136.00
7.	Laxmibai Scholarship Fund.	District Educational Officer, Jabalpur.	3% Conversion Loan 1946	2,600.00	2,600.00	70.00
8.	Woodburn Scholarship Fund.	Principal, Rajkumar College, Raipur.	5-3/4% M.P. Loan 1983 3% Conversion Loan 1946	2,400.00 8,300.00	10,700.00	349.00

7	8	9	10		11	Case No.
			Rs.	Rs.		
..	13.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	6.42 0.08 6.50	6.50	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	2
..	57.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	28.18 0.32 28.50	28.50	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	3
(t) 95.72	122.46	Interest remitted. Fee paid to Govt.	26.46 0.28 26.74	95.72	(t) Represents unspent balance of 4% MP Loan 1971 The interest shown (under column is 6) exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	4
..	191.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	94.43 1.07 95.50	95.50	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	5
..	136.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	67.25 0.75 68.00	68.00	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	6
..	70.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	34.61 0.39 35.00	35.00	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source	7
(u) 44.63	393.63	Interest remitted. Fee paid to Govt.	233.87 2.63 236.50	157.13	(u) Represents opening balance. The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	8

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
BIHAR						
1.	The Woodhouse Memorial Fund.	The Collector, Bhagalpur	5 Years Post Office Time Deposit.	1,100.00	1,100.00	..
2.	The Raja Raghunandan Prasad Trust Fund.	The Honorary Treasurer, Bihar SPCA, Sadaquat Ashram, Patna	3% Conversion Loan 1946	1,600.00	1,600.00	..
3.	The Sir Fakhruddin Memorial Gold Medal Fund.	The Director of Education, Secondary Education, Bihar, Patna.	3% Conversion Loan 1946	1,100.00	1,100.00	..
UTTAR PRADESH						
Aligarh						
1.	Tassadduque Rasul Arabic Scholarship Endowment Trust.	Treasurer, Muslim University, Aligarh.	3% Conversion Loan 1946	20,200.00	20,200.00	3,030.00
2.	Sir Syed Ahmad Memorial Trust Fund.	Registrar, Muslim University, Aligarh.	3% Conversion Loan 1946	1,16,000.00	1,16,000.00	17,400.00
3.	Sir William Marris Scholarship Endowment Trust.	Vice-Chancellor, Muslim University, Aligarh.	3% Conversion Loan 1946	6,400.00	6,400.00	960.00
Allahabad						
4.	Rewa Scholarship Endowment Trust.	Principal Government Inter College, Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	4,100.00	4,100.00	615.00
5.	Panna Scholarship Endowment Trust.	Director of Education, U.P. Allahabad.	3 % Conversion Loan 1946	5,[illegible]00.00	5,200.00	780.00

7	8	9	10	11	Case No.
			Rs.		
..	..	..	..	..	1 (Bihar)
			..		
..	..	..	..	..	2
			..		
			..		3
..	..	..	..	..	
			..		
			..		
..	..	..	..	..	(U.P.)
..	3,030.00	Interest remitted.	2,999.70	..	1
		Fee paid to Govt.	30.30		
			3,030.00		
..	17,400.00	Interest remitted.	17,226.00	..	2
		Free paid to Govt.	174.00		
			17,400.00		
..	960.00	Interest remitted.	950.40	..	3
		Fee paid to Govt.	9.60		
			960.00		
..	615.00	Interest remitted.	608.00	..	
		Fee paid to Govt.	6.20		4
			615.00		
..	780.00	Interest remitted.	772.00	..	
		Fee paid to Govt.	7.80		5
			780.00		

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
6.	Vizianagram Scholarship Endowment Trust.	Principal, Govt. Inter College, Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	14,800.00	14,800 000	2,220.00
7.	Vizianagram Scholarship Endowment Trust.	Registrar, Allahabad University, Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	26,000.00	26,000.00	3,900.00
	Varanasi					
8	Sadholal Scholarship Endowment Trust.	Up-Kulpati, Varanaseya Sanskrit Vishwavidyala-Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	45,000 00	45,000.00	6,750.00
9.	Kathiawad Sanskrit Scholarship Endowment Trust.	Do.	3% Conversion Loan, 1946	9,100 00	9,100.00	1,365.00
10.	Rewa Scholarship Endowment Trust.	Principal Government Higher Secondary School, Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	5,800 00	5,800.00	870.00
11.	Nagri Pracharini Sabha Endowment Trust.	Secretary, Nagri Pracharini Sabha, Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	1,63,100.00	1,63,100.00	24,051.00
12	Maharaj Kumar Sri Sudhansu Sekhar Singh Deo their apparent of Sonepur Estate Orissa Medal Endowment Trust.	Vice-Chancellor, Varanasi Hindu University, Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	1,500.00	1,500.00	225.00
13.	Rani Bhuwan Raj Lakshmi Devi of Basti Endowment Trust.	Registrar, Banaras Hindu University, Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	7,300.00	7,300.00	1,095.00

7	8	9	10	11	Case No.
..	2,220.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	2,197.80 22.20 2,220.00	..	6
..	3,900.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	3,861.00 39.00 3,900.00		7
..	6,750.00	Interest remitted. Fee paid to Govt	6,682.50 67.50 6,750.00	..	8
..	1,365.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	1,351.00 13.70 1,365.00	..	9
..	870.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	861.30 8.70 870.00	..	10
..	24,051.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	23,806.30 244.70 24051.00	interest shown (under Col. 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.	11
..	225 00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	222.70 2.30 225.00	..	12
..	1,095.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	1,084.00 11.00 1,095.00	..	13

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	
Pauri Garhwal						
14.	Garhwal Kshattriya Education Trust Fund.	Secretary, Garhwal Kshattriya Education Trust Fund, Pauri Garhwal	3% Conversion Loan, 1946	51,800.00	51,800.00	7,770.00
Lucknow						
15.	Nagar Education Endowment Trust, Upper India, Lucknow.	Secretary, Nagar Education Endowment Trust, Lucknow.	3% Conversion Loan, 1946 7-Year National Savings Certificates (III Issue)	16,600.00 19,400.00	36,000.00	2,490.00
16.	Captain Kr. Indrajit Singh, M.C.I.M.S. Memorial Research Scholarship Endowment Fund.	Principal, Medical College, Lucknow.	3% Conversion Loan, 1946	1,06,600.00	1,06,600.00	15,990.00
Mirzapur						
17.	Giraundi Kayashta Pathshala Endowment Trust.	A Committee of Management consisting of the Collector, Mirzapur, as Ex-officio Chairman and Executors of the Estate of the late Munshi Bindeshwari Prasad Pleader.	3% Conversion Loan, 1946 7-Year National Savings Certificates II Issue.	1,600.00 7,550.00	9,150.00	240.00
PONDICHERRY						
1.	Special Fund for Reconstruction & Rehabilitation of Ex-Servicemen.	Secretary, Rajya Sainik Board, Pondicherry.	N.S.A.R.C. 5¾% Agricultural Refinance Bond.	1,000.00	1,000.00	..
2.	Dr. M.K. Ramanathan, Memorial Prize Fund.	Principal Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry.	5-Years Post Office Time Deposit.	1,000.00	1,000.00	..
3.	Smt. Suseela Selvaradjalou Memorial Prize Fund.	Do.	5-Years Post Office Time Deposit.	1,000.00	1,000.00	..
4.	Shri N. Selvaradjalou Chettiar Memorial Prize Fund.	Do.	5-Year Post Office Time Deposit.	1,000.00	1,000.00	..

7	8	9		10	11	Case No.
Rs	Rs.		Rs.	Rs.		
.	7,770.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	7,692.30 77.70 7,770.00	..		14
.	2,490.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	2,465.10 24.90 2,490.00	.		15
..	15,990.00	Interest remitted. Fee paid to Govt.	15,830.10 159.90 15,990.00			16
	240.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	237.60 2.40 240.00	..		17
..	..	..		.	Speedy Action is being taken for realisation of interest.	1
..	..	.	.	..	Do.	2
..	..	..		.	Do.	3
..	..	..	..	..	Do.	4

PUNJAB

Pending apportionment of Securities relating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan the list of securities could not be prepared.

Certified that the balances exhibited in Part II of the above Statement agree with the detailed records of the respective Endowments maintained by the Treasurer of Charitable Endowments for India.

[No. F. 1/1/82-TCE

M.D. PAL, Treasurer of Charitable Endowments for India.

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

का० आ० 447.—केन्द्रीय सरकार ने, श्री एम० सी० महापात्र, आई० ए० एस० को 24 नवम्बर, 1982 से तम्बाकू बोर्ड गुन्तूर का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 5417 तारीख 17 दिसम्बर, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

"1. श्री एम० सी० महापात्र,
तम्बाकू बोर्ड,
गुन्तूर —अध्यक्ष"

[फा० सं० 8/6/82-ई० पी० (एजी०आर०आई०-IV)]
ओ० पी० गुप्ता, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 6th January, 1983

(TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

S.O. 447.—Whereas the Central Government has appointed Shri M. C. Mahapatra, IAS to be the Chairman of the Tobacco Board, Guntur with effect from the 24th November, 1982.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Tobacco Board Act, (4 of 1975), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. SO 5417, dated the 17th December, 1975, namely :—

"1 Shri M. C. Mahapatra, Tobacco Board Guntur,
......Chairman"

[F. No. 8/6/82-EP(AGRI VI)]
O. P. GUPTA, Desk Officer

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

का० आ० 448.—सर्वश्री इन्सट्रूमेन्टेशन लि०, कोटा को, 15,50,200 रुपए (पन्द्रह लाख, पचास हजार, दो सौ रुपए) के लिए आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/2039381 दिनांक 20-4-81 मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात करने के लिए प्रदान किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उनसे खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस तरह सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल का अभी तक बिल्कुल ही उपयोग नहीं हुआ है।

2. अपने इस आशय के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक कोटा के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत शपथ लेकर कि शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/2039381 दिनांक 20-4-81 की मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति फर्म से खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा-9(सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा को जारी लाइसेंस सं० आई/सीजी/2039381 दिनांक 20-4-81 की उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि फर्म को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सीजी/आई० डी० (1) 81-82]
पाल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 5th January, 1983

ORDER

S.O. 448.—M/s Instrumentation Ltd., KOTA were granted and import licence No. I|CG|2039381 dated 20-4-81 for Rs. 15,50,200 (Rupees Fifteen lakhs fifty thousand and two hundred only), for import of Capital goods under free foreign exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate Copy of Ex. Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Exchange Control copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs Purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filled an affidavit on stamped paper duly sworn in before a notary Public Kota, I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of import licence No. I|CG|2039381 dated 20-4-81 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Ex. Control Copy No. I|CG|2039381 dated 20-4-81 issued to M|s Instrumentation Ltd., Kota is hereby cancelled.

3 A duplicate Exchange Control copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/ID(1)/81-82]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का० आ० 449.—डा० (श्रीमती) सतीन्दर कौर सलूजा, 69-70, दस्सेरा मदान, उज्जैन, मध्य प्रदेश को भारत में सदा के लिए लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीय की श्रेणी के अन्तर्गत एक मर्सीडीज 200 डी सेलून, 1979 कार के

आयात के लिए केवल 56,000/- रुपए का एक सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे 0393808 दिनांक 14-10-82 प्रदान किया गया था ।

2. आवेदक ने उपर्युक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट खो गया है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने दिल्ली के नोटरी पब्लिक के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/0393808 दिनांक 14-10-82 आवेदक से खो गया या अस्थानस्थ हो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप खंड 9(सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डा० (श्रीमती) सतीन्दर कौर सलूजा को जारी किया गया उक्त मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/0393808 दिनांक 14-10-82 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

4. विषयाधीन सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति डा० (श्रीमती) सतीन्दर कौर सलूजा को अलग से जारी की जा रही है ।

[मिसिल सं० क-360/82-83/बी एल एस/2998]
एम० ई० थामस, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 449.—Dr. (Mrs.) Satinder Kaur Saluja, 69-70 Dassera Maidan, Ujjain, Madhya Pradesh was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/0393808 dated 14-10-82 for Rs. 56,000 only, for the import of one Mercedes 200D Seloon, 1979 car, under the category of Indian National returning to India for good.

2. The applicant has applied for issue of a Duplicate copy of her above mentioned Custom Clearance Permit on the ground that the original Custom Clearance permit has been lost. It has further been stated that the original Custom Clearance Permit was not registered with any Customs Authority and as such the value of the Custom Clearance Permit has not been utilised at all.

3. In support of her contention, the licensee has filed an affidavit, duly sworn before the Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Clearance Permit No. P/J/0393808 dated 14-10-82 has been lost or misplaced by the applicant. In exercise of powers, conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955, as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/0393808 dated 14-10-82 issued to Dr. (Mrs.) Satinder Kaur Saluja is hereby cancelled.

4. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit, in question, is being issued to Dr. (Mrs.) Satinder Kaur Saluja Separately.

[F. No. A-360/82-83/BLS/2998]
M. L. THOMAS, Jt. Chief Controller of Imports and Exports

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1982

का० आ० 450.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के० दुरैस्वामी, प्रबन्धक (पी० एण्ड ए०), बी०एच०ई०एल०, बंगलौर को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है। वह निम्नलिखित तालिका के कालम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के सम्बन्ध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन करेगा :—

अधिकारी का नाम और पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
प्रबन्धक (पी० एण्ड ए०) बी०एच०ई०एल०, बंगलौर	बी०एच०ई०एल०, कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट डिवीजन, बंगलौर से संबंधित और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर ।

[फा० सं० 14-20/82-एच०ई०एम०]
त्रिलोक चन्द भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 31st December, 1982

S. O. 450 :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971(40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri K. Doraiswamy, Manager(P&A), BHEL Bangalore to be the Estate Officer for the purpose of the said Act. He shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer, by and under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in col. (ii) of the following table:—

Designation of the Officer	Categories of Public Premises & Local limits of Jurisdiction
(i)	(ii)
Manager (P&A) B.H.E.L., Bangalore	Premises belonging to and under the administrative control of BHEL, Control Equipment Division Bangalore.

[File No. 14-20/82-HEM]
T. C. BHATIA, *Under Secy.*

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1983

का०आ० 451.—औ०वि०वि०अ० केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को तेल, साबुन और डिटर्जेंट के विनिर्माण में लगे अनुसूचित उद्योगों के लिए विकास परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :—

तेल, साबुन और डिटर्जेंट उद्योगों के लिए विकास परिषद :—

1. श्री के०के० पटेल, निदेशक, — अध्यक्ष
मै० निरमा प्राइवेट लिमिटेड,
4, सुरेन्द्र मंगलदास प्रोमिसेज,
अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015

2. श्री सी०वी० प्रभाकरन — सदस्य
निवासी प्रतिनिधि,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ए० 1, बाबा खड़ग सिंह मार्ग,,
नई दिल्ली-110001

3. श्री ए न०बी० गोदरेज, निदेशक — सदस्य
मै० गोदरेज सोप्स लिमिटेड,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,
विख्रोली, मुम्बई

4. श्री वी० जयप्पा, कार्यपालक निदेशक, — सदस्य
कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंटस लिमिटेड, बंगलोर।
वि० श्री० पी०के० संभाग, महाप्रबंधक।

5. श्री एन० के० भाडा, कार्यपालक उपप्रधान, — सदस्य
मै० टाटा आयल मिल्स लिमिटेड,
मुम्बई हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट, मुम्बई

6. श्री एम० चक्रवर्ती, मुख्य कार्यपालक, — सदस्य
मै० स्वास्तिक हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स
13/15 बालचन्द हीराचन्द मार्ग,
बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई

7. श्री पी०एम० सिन्हा, निदेशक, — सदस्य
मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
165/166 बैकबे रिकलेमेशन मुम्बई

8. श्री जे० आर० पाटिल, निदेशक (अ० और वि०) — सदस्य
मै० हिको प्राडक्ट्स लिमिटेड,
771 ,मोगल लेन, महीम, मुम्बई

9. श्री सुधीर जालान, — सदस्य
इंडियन सोप एण्ड टायलेटरीज,
मेकर्स एसोसिएशन, मुम्बई
मै० एशिआटिक सोप कंपनी,
8, बी०बी०डी० बाग स्टेट, कलकत्ता

10. श्री पी०आर० मल्हन, निदेशक (रसा०) — सदस्य
डी०सी० (एम०एस०आई०), नई दिल्ली

11. श्री एस०के० माथुर, हेड केमिकल डिपार्टमेंट — सदस्य
भारतीय मानक संस्थान भवन,
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

12. श्री एम० आर० कुलकर्णी, सं० सलाहकार — सदस्य
योजना आयोग, नई दिल्ली

13. श्री संतोष कुमार, अवैतनिक सचिव, — सदस्य
फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ
एम०एस० सोप एन्ड डिटर्जेंट,
मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया,
ए-3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिआ,
दिल्ली

14. डा० वी०एम० लाम्बा, — सदस्य
विपणन कार्यपालक (रसा०)
म० आई०पी०सी०एल० बड़ौदा

15. डा० एम०के० कुन्दू,
निदेशक वी०वी०ओ० एण्ड ई०, फैट्स
निदेशालय, नागरिक पूर्ति मंत्रालय,
90 नेहरू प्लेस नई दिल्ली

16. श्री डी०एस० चड्ढा, — सदस्य
सहायक महानिदेशक (पी०एफ०ए०)
डी०जी०एच०एस०, नई दिल्ली

17. श्री गिरधारी लाल बागड़िया, सचिव — सदस्य
राजस्थान साबुन निर्माता संघ,
मार्फत अखाद्य तेल साबुन उत्पादक सहकारी संघ लि०
चुरु, राजस्थान

18. श्री रमन बडीलाल साह, अध्यक्ष — सदस्य
गुजरात साबुन उत्पादक महामंडल,
परसी अगियारी के सामने,
खमसा गेट के समीप, अहमदाबाद

19. श्री पी०बी० रमेय। — सदस्य
नेशनल केमिकल कंपनी,
एडुकोचिन, कोचिन-682006

20. श्रम संघ का एक प्रतिनिधि — सदस्य
जो श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के परामर्श से होगा।

21. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य

22. नेशनल कंज्यूमर्स फ्रंट बी-12, पंडारा रोड, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि — सदस्य

23. डा० ए०पी० सिंह, निदेशक मै० कैम्फर एण्ड एलाइड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, बरेली — सदस्य

24. उद्योग सलाहकार (साबुन और सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट निदेशालय) डी०जी०डी०टी०, नई दिल्ली — सदस्य सचिव

[एफ० सं० 14(15)/81-डी०पी०आर०/ई०जी०जी०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd January, 1983

S.O. 451 IDRA.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of this order, the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture of Oils, Soaps and Detergents:—

Development Council for Oils, Soaps and Detergents Industries

1. Shri K. K. Patel, Director, M/s. Nirma Private Ltd., 4, Surendra Mangaldas Premises, Ambawadi, Ahmedabad-380015. — Chairman
2. Shri C. V. Prabhakaran, Resident Representative, Khadi and Village Industries Commission, A-1, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001. — Member
3. Shri N. B. Godrej, Director M/s. Godrej Soaps Limited, Eastern Express Highway, Vikhroli, Bombay — "
4. Shri V. Jayappa, Executive Director, Karnataka Soap and Detergents Ltd., Bangalore, Altn : Shri P. K. Shambhag General Manager. — "
5. Shri N. K. Bhada, Executive Vice-President, M/s. Tata Oil Mills Ltd., Bombay House, Homi Mody Street, Bombay — "
6. Shri M. Chakravarty, Chief Executive, M/s. Swastik Household and Industrial Products, 13/15 Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay — "
7. Shri P. M. Sinha, Director M/s. Hindustan Lever Ltd., 165/166, Backbay Reclamation Bombay. — "
8. Shri J. R. Patil, Director (R and D) M/s. Hico Products Ltd., 771, Mogal Lane, Mahim, Bombay. — "
9. Shri Sudhir Jalan, Indian Soap and Toiletries Makers Association, Bombay. M/s. Asiatic Soap Co., 8 BBD Baug East, Calcutta. — Member
10. Shri P. R. Malhan, Director (Chem) DC(SSI), New Delhi. — "
11. Shri S. K. Mathur, Head Chem. Deptt ISI Manak Bhavan, Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi. — "
12. Shri M. R. Kulkarni, Jt. Adv. Planning Commission, New Delhi — "
13. Shri Santosh Kumar Hony. Secretary, Federation of Association of S. S. Soap and Detergent, Mfrs. of India, A-3, Wazirpur Industrial Area, Delhi. — "
14. Dr. C. M. Lamba, Marketing Executive (Chem.) M/s. IPCL., Baroda. — "
15. Dr. M. K. Kundu, Director Dte. of V VO&E, Fats, Min of Civil Supplies, 90, Nehru Place, New Delhi. — "
16. Shri D. S. Chadha, Asstt. Director General (PFA) DGHS, New Delhi.
17. Shri Girdhari Lal Bagaria, Secretary, Rajasthan Sabun Nirmata Sangh, C/o Akhadhya Tel Sabun Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Churu, Rajasthan. — "
18. Shri Raman Vadilal Shah, Chairman, Gujarat Sabu Utapadak, Mahamandal, Opp. Parsi Agiyari, Near Khamsa Gate, Ahmedabad.
19. Shri P. V. Ramaniah National Chemical Co., Educochin, Cochin-682006 — "
20. A representative of the Labour, Union in consultation with the Ministry of Labour, New Delhi. — "
21. A representative of Ministry, of Commerce, New Delhi. — "
22. A representative of the National, Consumers' Front, B-12 Pandara Road, New Delhi. — "
23. Dr. A. P. Singh, Director, M/s. Campher and Allied Products Ltd., Bareilly. — "
24. Industrial Adviser (Soaps and Synthetic Detergents Dte.) DGTD New Delhi. — Member Secretary.

[F. No. 14(15)81-DPR/EGG]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd January 1983

S.O. 452 :—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Coal) No S.O. 1785, dated, the 28th April, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th May, 1982,—

(1) at page 1970, in column 2, in line 30, for "Kokebisaudi" read "Kekobisaudi"

(2) at page 1971

(a) In column 1,

(i) in line 4,	for	"number"
	read	"numbers";
(ii) in line 12,	for	"599"
	read	"599(part)",
(iii) in line 16,	for	"923 (part)"
	read	"1923 (part)";
(iv) in line 18,	for	"1977 (part)"
	read	"1997 (part)";
(v) in line 22,	for	"2135, 2136"
	read	"3135, 3136";
(vi) in line 27,	for	"3202(part), 3202(part), 3225"
	read	"3202 (part), 3203(part), 3235"
(vii) in line 30,	for	"120, 0 171"
	read	"120 to 171";
(viii) in lines 33 & 34	for	"269, 270(part), 279"
	read	"269, 270(part), 271(part)279",
(ix) in line 62	for	"At point (B)"
	read	"At point 'B'".

(b) in column 2,

(i) in line 4,	for	"At point 'B' "
	read	"At point 'B1' ";
(ii) in line 6,	for	"villages Rauta and Basantpur, Rauta" and Barisum";
	read	"Villages Rauta and Barisum"'
(iii) in line 18,	for	"5C"
	read	"50"
(iv) in line 24,	for	"250 and 266 of"
	read	"250, 266 and 268 of";
(v) in line 35,	for	"Plot no. 171 of village"
	read	"Plot no. 170 of village";
(vi) in line 39,	for	"lines passes through"
	read	"lines pass through";
(vii) in line 61,	for	"Gharnara"
	read	"Charnara";

(3) at page 1972,—

(a) in column 1,—

(i) in line 26,	for	"village"
	read	"villages";
(ii) in line 29	for	"Chutua Madi"
	read	"Chutua Nadi";

(b) in Column 2,—

(i) in line 21	for	"arsabera"
	read	"Parsabera"
(ii) in line 36	for	"passes"
	read	"pass".

[No. 19/85/82-CL]
P. SARKAR, Director

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1982

का०आ० 453 —यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य है।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयो, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयो मे कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियो ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की उपधारा 12ए के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नही दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है:—

क्रम सं०	अधिकारी कर्मचारियों का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री यू० आर० काम्बले	.	गोदाम लिपिक	1-3-69

[संख्या 52/1/82-एफ० सी० III]
आर० के० सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 21st December, 1982

S.O. 453 :—Whereas the Central Government has ceased to perform the function of purchase, storage, movement

transport, distribution & sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement directors and the Pay & Accounts Office of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in performance of the functions mentioned above have not, in response to the circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India, as required by the provision to Sub-Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following employee to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against him :—

Sl. No.	Name of the Officer/employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to FCI
1	2	3	4	5
1.	Shri U.R. Kamble	—	Godown Clerk	1-3-69

[No. 52/1/82-FC. III]

R. K. SINGH, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

(पुरातत्व)

का०आ० 454.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व है।

अतः केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर प्राचीन संस्मारकों में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले सर्वेक्षण प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
राजस्थान	भरतपुर	डीग	रामबाग	नीचे पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लाट सं० 376, 377, 382, 383 और 53 तथा सर्वेक्षण सं० 378, 379, 380 और 381 के भाग में समाविष्ट पार्श्वस्थ क्षेत्र सहित राम बाग महल।	नीचे पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लाट सं० 376, 377, 382, 383 और 59 तथा सर्वेक्षण प्लाट सं० 377, 379 380 और 381 के भाग

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
7	8	9	10
2.76 हैक्टर	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं० 16, 17, 27, 28, 29 और 52 पूर्व : सर्वेक्षण सं० 375 गांव की सड़क दक्षिण : सर्वेक्षण सं० 375 और सर्वेक्षण सं० 378, 379 और 380 के शेष भाग। पश्चिम : सर्वेक्षण सं० 384 और 385 और सर्वेक्षण सं० 380 और 381 के शेष भाग।	सर्वेक्षण सं० 53, 381 और 382 से भिन्न जो प्राइवेट स्वामित्व में है सरकार	

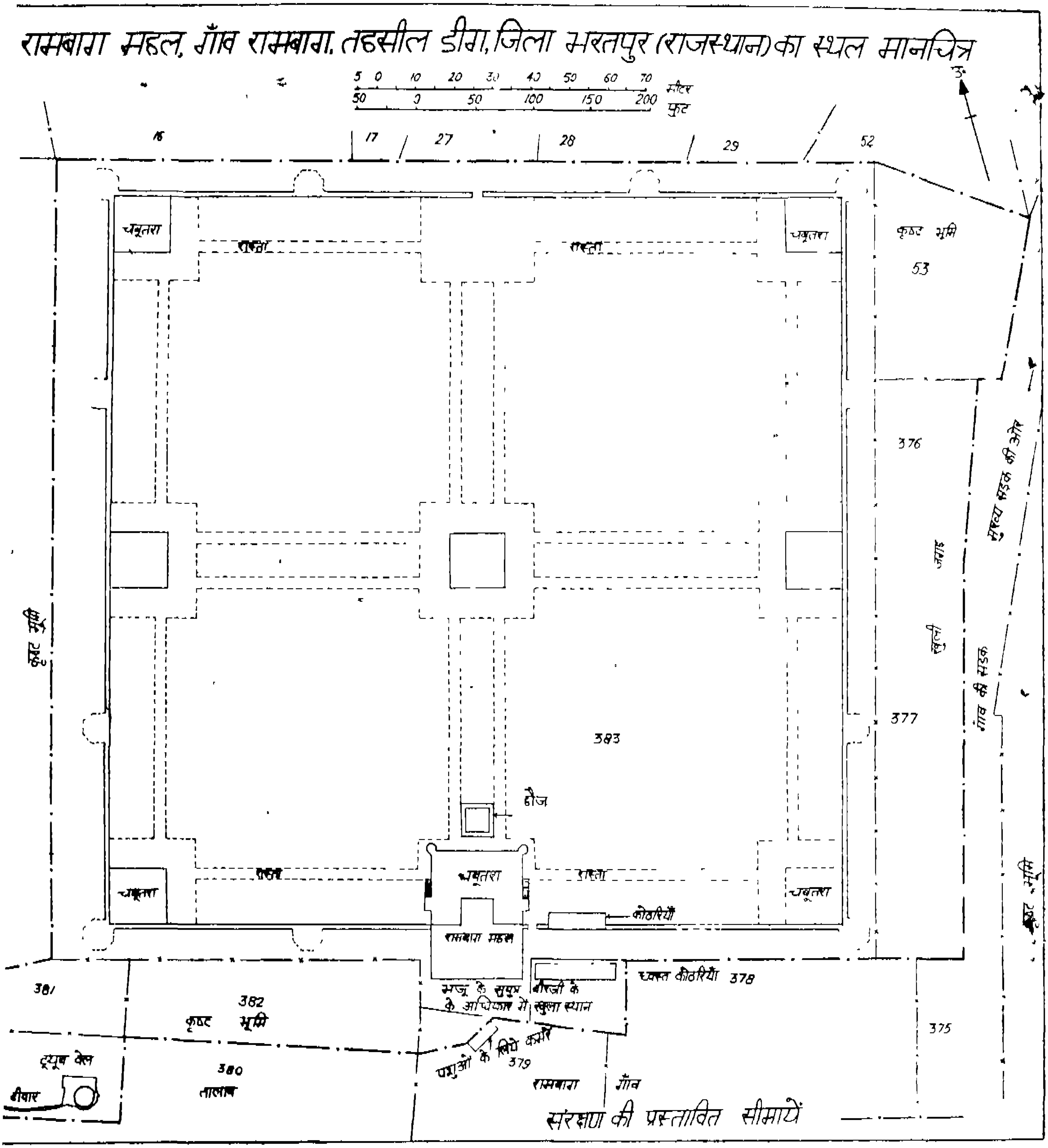
रामबाग महल, गाँव रामबाग, तहसील डीग, जिला भरतपुर (राजस्थान) का स्थल मानचित्र
5 0 10 20 30 40 50 60 70 मीटर
50 0 50 100 150 200 फुट
16
17
27
28
29
52
चबूतरा
रास्ता
कृष्ट भूमि
53
376
मुख्य सड़क की ओर
377
गाँव की सड़क
383
हौज
कोठरियाँ
रामबाग महल
ध्वस्त कोठरियाँ 378
381
382
कृष्ट भूमि
380
तालाब
ट्यूब वेल
दीवार
375
पशुओं के लिये कमरे
379
रामबाग गाँव
संरक्षण की प्रस्तावित सीमायें

[सं० 2/68/78-मा०]

DEPARTMENT OF CULTURE

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O.454:—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of Monument
1	2	3	4	5
Rajasthan	Bharatpur	Deeg	Rambagh	Rambagh Mahal together with adjacent area comprised in survey plot numbers 376, 377, 382, 383 and 53 and part of survey plot numbers 378, 379, 380 and 381 as shown in site plan reproduced below.

Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9	10
Survey plot Nos. 376, 377, 382, 383 and 53 and parts of survey plot Nos. 378, 379, 380 and 381 as shown in the site plan reproduced below.	2.76 hectares	North : Survey Nos. 16, 17, 27, 28, 29 and 52 East : Survey No. 375 village road South : Survey No. 375 and remaining portion of survey Nos. 378, 379 and 380 West : Survey Nos. 384 and 385 and remaining portions of survey Nos. 380 and 381.	Govt., except survey Nos. 53, 381 and 382, which are under private ownership.	—

SITE PLAN OF RAMBAGH MAHAL, VILL:- RAMBAGH, TEH:- DEEG, DISTT:- BHARATPUR (RAJASTHA

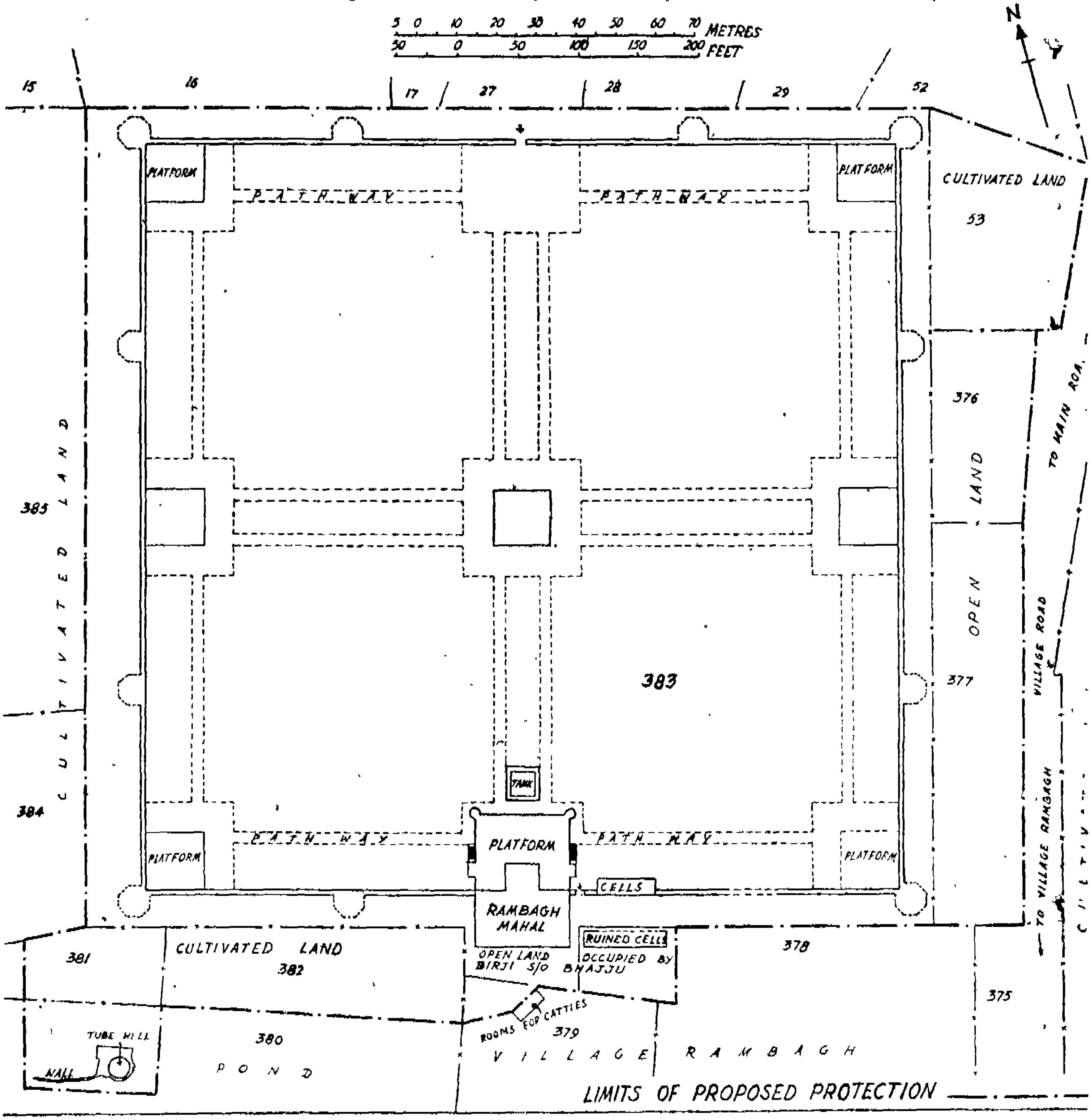

LIMITS OF PROPOSED PROTECTION

[No. 2/68/76-M]

का० आ० 455.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है,

अतः केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो माह की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले सर्वेक्षण प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
दिल्ली	दिल्ली	तीसहजारी	शालीमार गार्डन ग्राम हैदरपुर	नीचे दिए गए स्थल नक्शे में यथा-वर्णित, सर्वेक्षण प्लाट सं० 898/250 और 899/250 में समाविष्ट साथ लगे हुए क्षेत्र तथा सर्वेक्षण प्लाट सं० 249, 251, 252, 253, 256, 288, 296 और 900/289 के भाग सहित शीश महल।	सर्वेक्षण प्लाट सं० 298/250 और 299/250 तथा नीचे दिए गए स्थल नक्शे में यथावर्णित सर्वेक्षण प्लाट सं० 249/251, 252, 253, 256, 288, 296 और 900/289 के भाग।

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
7	8	9	10
209 हेक्टर	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं० 259 और 287 तथा सर्वेक्षण प्लाट सं० 252 और 253 के शेष भाग। पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट सं० 251, 288, 296 और 900/289 के शेष भाग। दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं० 249 और 295 के शेष भाग। पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं० 249 और 296 के शेष भाग।	प्राइवेट	--

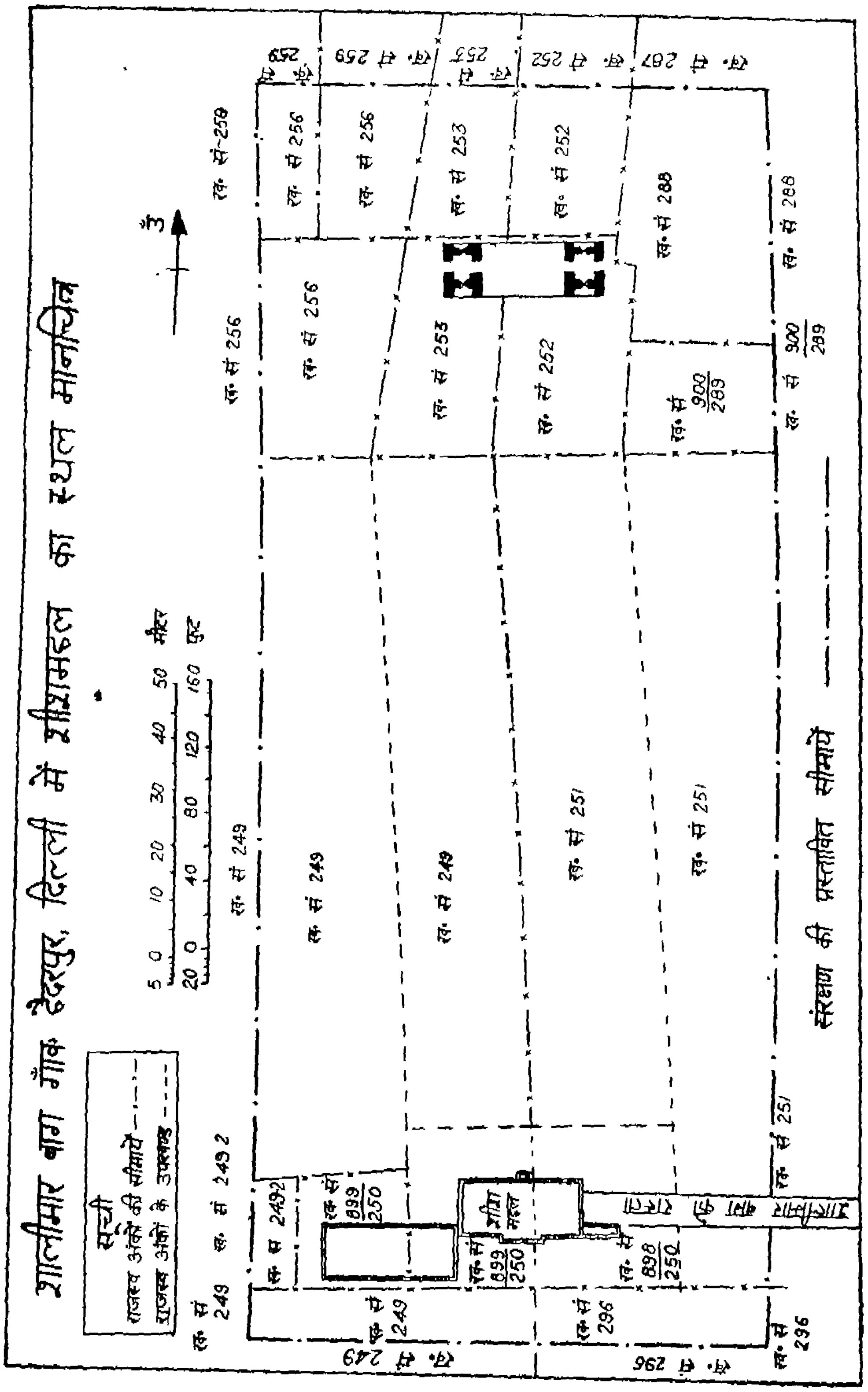
शालीमार बाग गाँव हैदरपुर, दिल्ली में शीशमहल का स्थल मानचित्र
सूची
संरक्षण की प्रस्तावित सीमायें
शीश महल

[सं० 2/24/72-स्मा०]

S.O. 455.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

Union Territory	District	Tehsil	Locality	Name of Monument
1	2	3	4	5
Delhi	Delhi	Tishazari	Shalimar Garden Village Hyderpur	Sheesh Mahal together with adjacent area comprised in survey plot Nos. 898/250 and 899/250 and parts of survey plot Nos. 249, 251, 252, 253, 256, 288, 296 and 900/289 as shown in the site plan reproduced below

Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9	10
Survey plot Nos. 898/250 and 899/250 and parts of survey plot Nos. 249, 251, 252, 253, 256, 288, 296 and 900/289 as shown in the site plan re-produced below.	2.09 Hectares	North :—Survey plot Nos. 259 and 287 and remaining portions of survey plot Nos. 252 and 253. East :—Remaining portions of survey plot Nos. 251, 288, 296, and 900/289. South :—Remaining portions of survey plot Nos. 249 and 296. West :—Remaining portions of survey plot Nos. 249 and 256.	Private	—

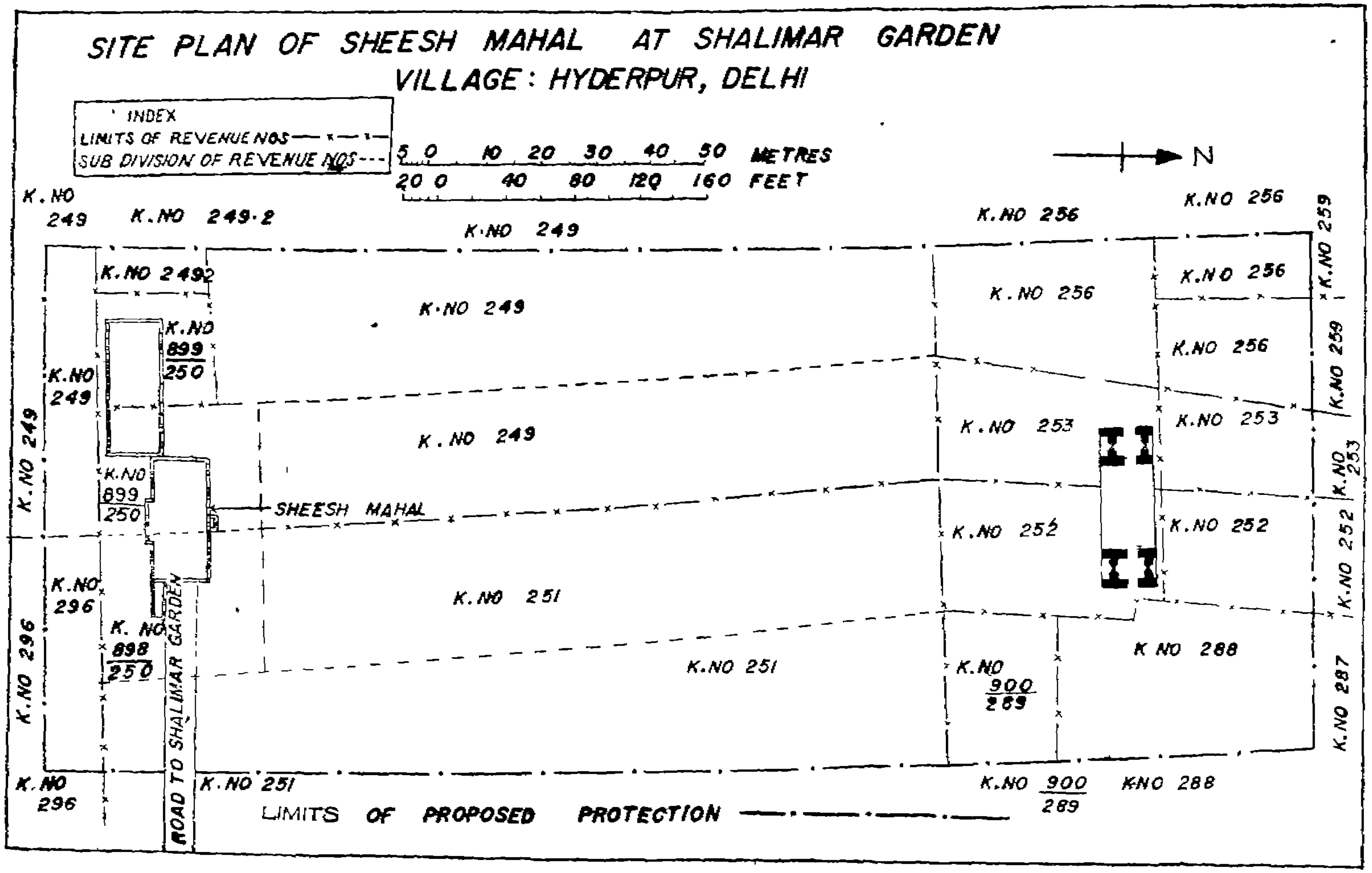
SITE PLAN OF SHEESH MAHAL AT SHALIMAR GARDEN
VILLAGE : HYDERPUR, DELHI
INDEX
LIMITS OF REVENUE NOS
SUB DIVISION OF REVENUE NOS
5 0 10 20 30 40 50 METRES
20 0 40 80 120 160 FEET
N
K.NO 249
K.NO 249·2
K.NO 256
K.NO 259
K.NO 899/250
K.NO 898/250
K.NO 253
K.NO 252
K.NO 251
K.NO 296
K.NO 288
K.NO 287
K.NO 900/289
SHEESH MAHAL
ROAD TO SHALIMAR GARDEN
LIMITS OF PROPOSED PROTECTION

[No.2/24/72-M]

का०आ० 456.—केन्द्रीय सरकार की राय यह है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन/संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
केरल	त्रिचूर	तालापिल्ली	वाडक्कान चेरी	शिव मन्दिर काम्पलेक्स, पल्ली मन्ना में लगे हुए क्षेत्र सहित, जो सर्वेक्षण प्लाट सं० 450, 451 में और सर्वेक्षण प्लाट सं० 449 452/3, 443 और 1671 के भागों में, जैसा नीचे उद्धृत स्थल प्लान में दर्शित है, अन्तर्विष्ट है।	सर्वेक्षण प्लाट सं० 450, 451 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 4149 452/3, 443 और 1671 के भाग जैसा नीचे उद्धृत स्थल प्लान में दर्शित है।

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
0.58 हैक्टर	उत्तर सर्वेक्षण प्लाट सं० 449 का शेष भाग पूर्व सर्वेक्षण प्लाट सं० 443 (अ.ला) शेष भाग दक्षिण सर्वेक्षण प्लाट सं० 452/2 और पश्चिम . सर्वेक्षण प्लाट सं० 452/2 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 449, 452/3 और 1671 का शेष भाग।	(1) सर्वेक्षण प्लाट सं० 449 450, 451 और 452/3 पल्ली मन्ना देवास्वम्। (2) सर्वेक्षण प्लाट सं० 1671 और 443 पोराम्बोके	राजस्व अभिलेखों में प्लाट सं० 432/3 पल्लीमन्ना देवास्वम् के नाम से दिखाया गया है किन्तु वह प्राइवेट अधिभोग में है। मन्दिर में, देवास्वम्, बोर्ड कानून द्वारा उपासना की जाती है और उसका प्रबन्ध बोर्ड करता है मंदिर की आकाइन की दीवारें के भित्त चित्र पहले से ही संरक्षित है।

ल्लीमन्ना, गाँव वादक्कानचेरी, जिला-त्रिचूर, राज्य-केरल में स्थित शिव-मन्दिर
म्पलेक्स का स्थल मानचित्र

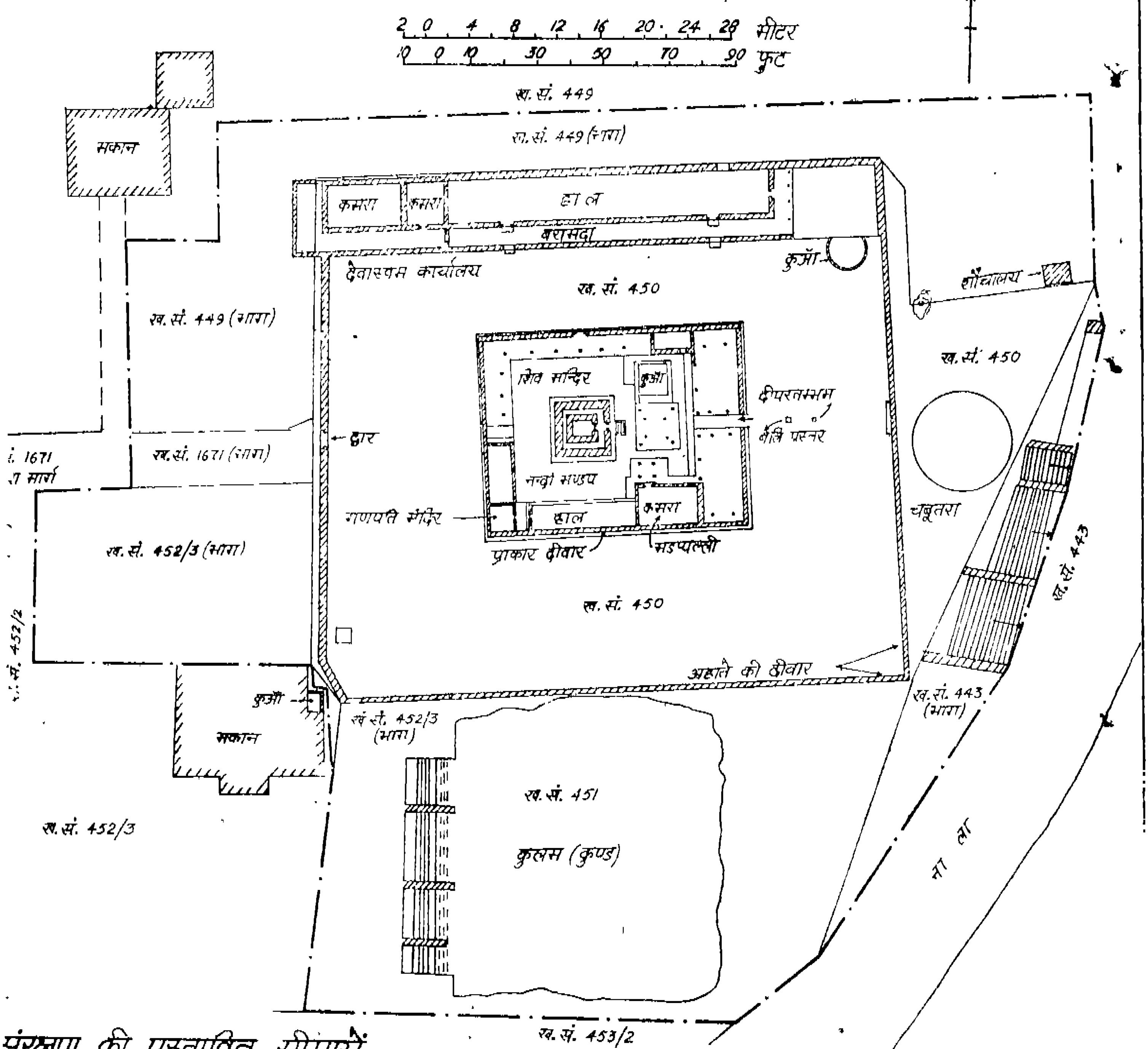

संरक्षण की प्रस्तावित सीमायें

[सं० 2क/2/79-स्मा०)]

डा० (श्रीमती) देबला मित्र, महानिदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

S. O. 455:—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument
1	2	3	4	5
Kerala	Trichur	Talappilly	Vadakkancheri	Siva temple complex, Pallimanna, together with adjacent area comprised in survey plot Nos. 450, 451 and parts of survey plot Nos. 449, 452/3, 443 and 1671 as shown on site plan reproduced below.

Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9	10
Survey plot Nos. 450 451 and parts of survey plot Nos. 449, 452/3, 443 and 1671 as shown on the site plan reproduced below.	0.58 Hectares	North :—Remaining portion of survey plot No. 449 East :—Remaining portion of survey plot No. 443 (Nala) South :—Survey plot No. 452/2 West :—Survey plot No. 452/2 and remaining portion of survey plot Nos. 449, 452/3 and 1671.	(i) Survey plot Nos. 449, 450, 451 and 452/3 : Palimanna Dewaswom (ii) Survey Nos. 1671 and 443 : Poramboke	The Revenue records show plot No. 452/3 in the name of Palimanna Dewaswom but this is under private occupation. The temple is under worship and managed by the Devaswom Board Cochin. The mural paintings on the walls of the Srikoil of the temple are already protected.

SITE PLAN OF SIVA TEMPLE COMPLEX AT PALLIMANNA, VILLAGE: VADAKKANCHERY, DISTRICT: TRICHUR, STATE: KERALA

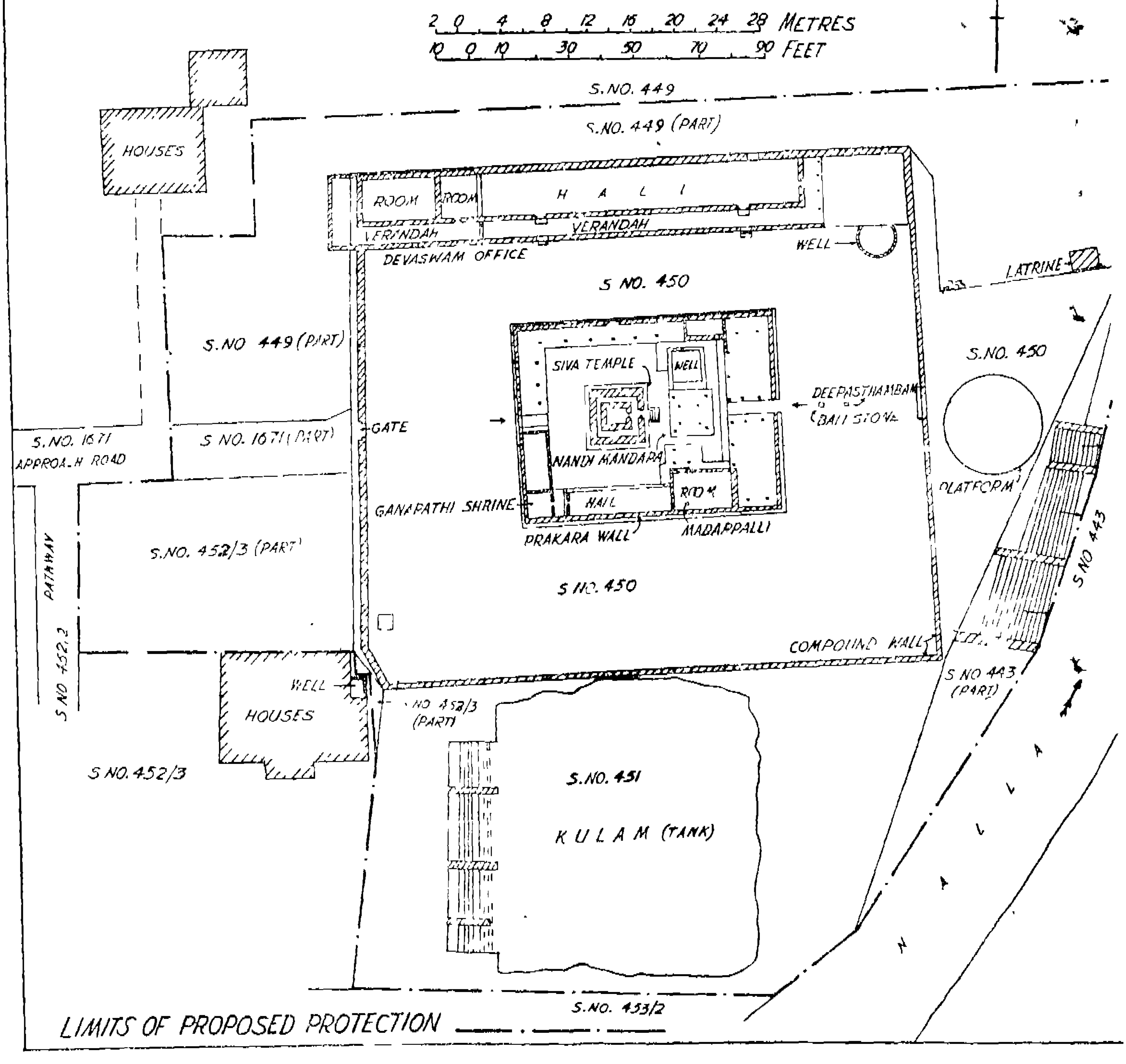

LIMITS OF PROPOSED PROTECTION

[No. 2A/2/79-M]

D. MITRA, Director General and Ex Officio Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

का० आ० 457.—कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 का संशोधन करने के लिए, प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 1789 तारीख 27 अप्रैल, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 अप्रैल, 182 के पृष्ठ—पर प्रकाशित की गई थी जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र 1 जून, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त प्रारूप स्कीम पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1983 है;

(2) ये, राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

(3) कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1970 की अनुसूची VI में मद सं० 4 के नीचे आने वाले टिप्पण (1) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) एकल पैकेज, जो 60 टन से अधिक भार के कालानुपाती दर वाले होंगे, परन्तु यह कि आधानों पर माल की लदाई और उतराई चाहे उनका तन भार कुछ भी हो, केवल कालानुपाती दर पर होगी।"

[फा० सं० एल डी सी/93/81-एल०IV]
वी० शंकरलिंगम, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Labour Division)

New Delhi, the 1st January, 1983

S.O. 457.—Whereas certain draft scheme to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 27th April, 1982 at page 1970 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1739 dated the 27th April 1982, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification in he Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 1st June, 1982;

And whereas objection and suggestions received from the public on the said draft scheme have been considered by the Government of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. Short title and commencement—(1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1983.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, in Schedule VI, for Note (1) occurring, under Item No. 4 the following Note shall be substituted, namely :—

"(1) Individual packages, weighing over 60 tonnes, shall be time-rated; Provided that loading and unloading of containers, irrespective of their tonnage, shall be only time-rated."

(F. No. LDC|93|81-LIV)
V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 4 जनवरी 1983

का० आ० 458.—यत: श्री टी० राघवन ने, जिन्हें भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 2073 दि० 4 अगस्त, 1980 द्वारा कांडला डॉक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है;

और उक्त डॉक लेबर बोर्ड में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अब, अत: गोदी कर्मकार (नियोजन का विनिमन) नियम, 1962 के नियम 4 के अनुबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा० सं० एल० डी० के०/6/80-एल-III]

TRANSPORT WING

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 458.—Whereas Shri T. Raghavan, who was appointed as a member of the Kandla Dock Labour Board by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 2073, dated the 4th August, 1980, has resigned from his post;

And whereas a vacancy has occured in the said Dock Labour Board;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

(File No. LDK|6|80-L.III)

का०आ० 459.—गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (1) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उप धारा (3) द्वारा श्री टी राघवन के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर श्री महेश जे० मेहता को कांडला डाक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 2073 दिनांक 4 अगस्त, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: उक्त अधिसूचना में "गोदी कर्मकारों और नौवहन कम्पनियों के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत, मद सं० 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "श्री महेश जे० मेहता" रखा जाए।

[फा० सं० एल डी के/6/80एल-III]
थामस मैथ्यू, अवर सचिव

S.O. 459.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock workers (Regulation of Employment) Rules 1962, the Central Government hereby appoints Shri Mahesh J. Mehta as a member of the Kandla Dock Labour Board vice Shri T. Raghvan, who has resigned, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. SO 2073, dated the 4th August, 1980, namely:—

In the said notification under the heading "Members representing the employers of dock workers and shipping companies" for the entry against item No. 2 the entry "Shri Mahesh J. Mehta" shall be substituted.

[F. No. LDK/6/80-L III]
THOMAS MATHEW, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1982

(व्यापार नौवहन)

का० आ० 460.—पाल जहाजों को लागू व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार परिवहन और संचार मंत्रालय, परिवहन विभाग, (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 3142 दिनांक 17-12-1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, बुलसर, उम्बेरगांव और थाना के पत्तनों संबंधी स्तम्भ 2 की प्रविष्टियां रखी जाएं :—

--"निरीक्षक, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बुलसर,

--निरीक्षक, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, उम्बेरगांव,

—निरीक्षक, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, थाना।"

[सं० एस०डबल्यु०/5-एम०एस०आर०(15)/82-एम०ए०]
अनुराग भटनागर, अवर सचिव

नोट:— भारत सरकार, परिवहन और संचार मंत्रालय, परिवहन विभाग, (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 3142 दिनांक 17 दिसम्बर, 1960 में इस प्रकार संशोधन किया गया था: —

1. सं० 39-एमडी (22)/63 दिनांक 16-10-63
2. सा० आ० सं० 451 दिनांक 1-2-1978
3. सा० आ० सं० 2581 दिनांक 17-9-80.

New Delhi, the 30th December, 1982

MERCHANT SHIPPING

S.O. 460.—In exercise of the powers conferred by section 23 and 24 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) as applied to sailing vessels, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Transport and Communication, Department of Transport (Transport Wing), No. S.O. 3142, dated the 17th December, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification for the entries in column 2 relating to the ports of Bulsar, Umbergaon and Thana, the following entries shall, respectively, be substituted:—

"Inspector, Customs and Central Excise Bulsel,
Inspector Customs and Central Excise Umbergaon.
Inspector, Customs and Central Excise Thana".

[No. SW/5-MSR(15)/82-MA]
A. BHATNAGAR, Under Secy.

Note.—The Government of India, Ministry of Transport and Communication, Department of Transport (Transport Wing) notification No. S.O. 3142 dated the 17th December, 1960 was amended as follows :—

1 No. 39-MD(22)|63, dated 16-10-63
2. S.O No 451 dated 1-2-1978
3. S.O. No. 2581 dated 17-9-1980.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एण्ड सैटलमेंट यूनिट-1)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1982

का०आ० 431—दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के

अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे नर्सरी स्कूल व रिक्रिएशन सैन्टर के निर्माण हेतु राष्ट्रीय नेत्रहीन समिति को हस्तान्तरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है।

अनुसूची

लगभग 0.497 एकड़ माप का भूमिखण्ड जो रामकृष्णपुरम सैक्टर-5, नई दिल्ली में स्थित है जिसका स्थल संख्या 66 है और जो अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4719 दिनांक 21-8-75 का आंशिक भाग है।

उपर्युक्त भूमिखण्ड की सीमाएं निम्नलिखित हैं:—

उत्तर में :	सड़क
दक्षिण में:	सड़क
पूर्व में:	सरकारी भूमि
पश्चिम में:	सड़क

[सं०एस०एण्ड एस० 33(13)/81-ए०ई०-I/1416]

ह० अपठनीय

सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey and settlement Unit. I)

New Delhi, the 27th December, 1982

S.O. 461.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority replaces at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below which that Government required for further transfer to the National Association for the Blind for construction of Nursery School-cum-Recreation Centre.

SCHEDULE

All that piece of land measuring about 0.497 acres situated in R. K. Puram Sector-V, New Delhi bearing site No. 66 partly of notification No. SO 4719 dated 21-8-1975

The above piece of land is bounded as follows:—

North : Road
South : Road
East : Govt. land
West : Road

Illegible

[No. S and S 33(13)/81-A.E.(I)/1416]

Secretary
Delhi Development Authority

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

का० आ० 462.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस० 11017/2/81—डी० 1-ए०]

एल० के० नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 1st January, 1983

S.O. 462.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Cement Industry, which are covered by entry 3 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017(2)/81-DJA]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 31st December, 1982

S.O. 463.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Hurriladih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 74 of 1981

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Hurriladih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. Post Office : Jharia, Distt. Dhanbad

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate

On behalf of the workmen—Shri S. P. Singh, General Secretary, Khan Mazdoor Congress, Dhanbad.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, 20th December, 1982

AWARD

This is a reference under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. L-20012(218)/81-D.III(A), dated 23rd October, 1981 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Hurriladih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Post Office Jharia, District Dhanbad in superannuating

Shri Suresh Ahir, Loader from service with effect from 20th July, 1980 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The concerned workman Shri Suresh Ahir was served an office letter No. HRP|PA|80|F-PO/1080, dated 3/-6-80 to retire from 20-7-80 on the ground that he has completed 60 years of age on 20-7-80. He was thereafter stopped from work, with effect from 20-7-80. The concerned workman challenged through his union this stoppage of work on the ground that he was about 45 years of age and had not completed the age of superannuation which is 60 years. It was further contended that in the standing order applicable to the colliery there was no provision for retirement. The management paid no attention to the union's contention and so the union took up the matter in industrial dispute, before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad. The conciliation ended in failure leading to this reference.

3. The management contended that the date of birth of the concerned workman as recorded in Form B register is 16-7-1920. He therefore attained the age of 60 on 16-7-79 and therefore he should have superannuated on 16-7-79 on completing the age of 60 years. The concerned workman was paid one month's pay and gratutity which were due to him under the payment of Gratuity Act, 1972. The concerned workman was accordingly superannuated from 20th July, 1980. The management's case is that the date of birth of the concerned workman is not only recorded in Form B register but also in the identity card register, and on both these documents the concerned workman give his thumb impression. The management has further contended that at no time the concerned workman protected against the accuracy of the entries of age mentioned in these two documents. On the above ground it has been contended that the management's action in superannuating him w.e.f. 20-7-80 was justified, and the concerned workman was not entitled to any relief.

4. In this court the concerned workman, Shri Suresh Ahir has been examined as WW. 1. According to his evidence he was appointed for the first time in Borragarh Colliery during the time of the private owners of the colliery. He is illeterate and did not produce any certificate of age at the time of appointment. The company which appointed him did not get him medically examined for assessment of his age. The colliery was nationalised and B.C.C.L. became the owner of the colliery. The scheme of issuing identity card was taken up by the BCCL and he was issued identity card on which his photograph has been affixed. After nationalisation BCCL transferred him from Borragarh to Hurrilldih colliery. He got the letter of retirement, Ext. W. 1 and he met the colliery manager and told him that he was fit to work and also requested him to have his medical examination done for assessment of his age. The manager directed the Labour Officer to get him medically examined, but no arrangement was made. The Labour Officer directed him to obtain a certificate of his age. He then went to his village home and the police officer of the local police station granted him an age certificate. Since it was not proved it was marked 'Y' for identification. He has estimated his age to be 46 years. In cross-examination he has admitted that he cannot say in which year he was born. Before his employment in the colliery, he used to tend cattle, such as cows, buffalows in his village home. He has no appointment letter or any other paper of the time of his first appointment. He has admitted that management retires its workers on the basis of documents, such as Form B register and identity card register. He has admitted that after his appointment he gave particulars/such as, father's name, village, etc. and the same had been entered in management's papers over which he put LTIs. According to him there was system of assessment of age by medical examination at the time of his appointment. The age was entered in the register on the basis of declaration of age by the workman. The witness has said that whatever registers were prepared by the BCCL, he put his LTIs on the same and the other workers also did similarly. The BCCL prepared the registers on the basis of old registers of the private owners. At the time when the identity cards were issued he had put his LTI on the identity card and the identity card register. He never complained before the management prior to his retirement that his age as recorded was wrong. The witness produced in the court his identity card which was marked 'X' for identification Within 15 days of his retirement he gave his identity card to his union. He denied that the identity card had been bleached and subsequently the entries had been made thereon.

5. The management examined Shri S. K. Banerjee, MW. 1. He is P.F. Incharge of Hurrahdih colliery from the year 1975. He has proved the Form B register of the colliery written in the pen of Shri Sadhu Charan Prasad. The photostate copy relating to the entry in Form B register was replaced in place of the original Ex. M1. Similarly, he has proved Ext. M2 the Identity Card register written in the pen of Shri S. N. Singh. This again has been replaced by photostate copy. He has said that in both these documents the date of birth of Shri Suresh Ahir has been mentioned to be 16-7-1920. In his cross-examination he has said that Exts. M1 and M2 are of Borragarh colliery where the concerned workman was previously working. He has further said that the identity card (X) for identification there is a photograph of the concerned workman and the date of birth shown in this document is 14-2-26.

6. It will appear from the above that the documentary evidence is in favour of the management in which the date of birth has been shown to be 16-7-1920. On behalf of the concerned workman only one document has been proved which is the notice of retirement, Ext. W. 1. Identity Card marked 'X' for identification has not been proved according to law. The contention of the management is that this document cannot be relied upon because it had not been proved according to law and the management do not consider this document to be genuine. Shri Joshi has further agreed that apparently the original identity card has been bleached and thereafter entries have been filled up showing the date of birth to be 14-2-26. I am not in position to give a categorical finding that the identity card had been bleached but this is correct to say that it has not been proved according to law, and we cannot place reliance on this document for the purpose of holding that the date of birth of the concerned workman is 14-2-26. Similarly, a document marked 'Y' for identification has also not been proved according to law. This is an extract from Family register concerning Shri Suresh son of Tulshi of village Mokarpur, district Balia. The date of birth is shown to be 1-1-1937. This has been certified by Sambhu Nath Singh, Panchayat Savek and is dated 16-2-81. It also bears the endorsement of Vikash Adhikary dated 17-2-81. Apart from the fact that this document has not been proved it will appear that the date of birth is 1-1-1937 and is not consistent with the date if birth shown in the identity card. In fact there is a gap of 11 years between the two dates. It will appear that the concerned workman has no idea about his age. He has in his evidence practically admitted the case of the management that he gave certain age at the time of his appointment which entered in Form B register. He admits to have put it his thumb impression on the document. Furthermore, when his identity card was being prepared he put his thumb impression in the identity card register against the entry of his name. He further never raised any objection about entries in Form B Register and Identity Card register. It is after his retirement that he has started raising objection. He has even wanted to get himself medically examined for the purpose of ascertaining his age. The management did not do so far the simple reason that prior to his retirement be never challenged the entry of his date of birth in the Form B register and Identity Card Register. The management was perfectly justified to reject his prayer.

8. Thus having considered all aspects of the case I hold that the action of the management of Hurrlidih colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad in superannuating, Shri Suresh Ahir.loader from service with effect from the 20th July, 1980 is justified. Consequently, the concerned workman is not entitled to any relief.

This is my award

J. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012|218|81-D.III(A)]

S.O. 464.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the manage-

ment of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Karmik Bhawan, Post Office Saraidhela, District Dhanbad, and their workman, which was received by the Central Government on the 27th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947
Reference No. 26 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Karmik Bhawan, Post Office Saraidhella, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen—Shri B. B. Pandey, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, dated, the 21st December, 1982

AWARD

By Order No. L-20012|222|80-E.III(A) dated, the 20th May, 1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of the workmen of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Karmik Bhawan, Post Office Saraidhella, District Dhanbad for restoration of basic pay, fixation of pay scale, protection of other benefits such as leave, train fare, and reimbursement of medical expenses, etc. with effect from the 1st May, 1972 to Shri Dharam Singh, Stowing Supervisor of Jealgora Colliery, at present working as Supervisor Internal Audit, is justified ? If so, to what relief is the said workmen entitled ?"

2. The parties have filed their written statements and rejoinders. But it is not necessary to state their respective cases in any detail. Suffice to say that the management in its written statement has taken a preliminary legal objection to the validity of the reference on the ground that Dharam Singh, Stowing Supervisor of Jealgora Colliery, at present working as Supervisor Internal Audit, whose case been referred to this Tribunal for adjudication, is not a "workman" within the meaning of section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, and hence no reference could be made regarding his case by the Central Government in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Act. Though, in his rejoinder, Dharam Singh had initially disputed the aforesaid legal stand of the management, he, subsequently, in his petition dated 20-12-82, concerned and admitted that he is not a 'workman' within the meaning of section 2(s) of the Act, and further stated that he is desirous of seeking remedy in proper forum. Now that it is the admitted case of both the parties that Dharam Singh is not a 'workman' within the meaning of section 2(s) of the Act, the present reference by the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Act, is wholly incompetent, and, in that view of the matter, he is not entitled to get any relief from this Tribunal. In the circumstance of the case there shall be no order as to cost.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer
[No. L-20012(222)|80-D.III(A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1982

का०आ० 465.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबन्द्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक बैंक लिमिटेड, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०एच० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलौर के प्रबन्धतंत्र की श्री के०बी० प्रसन्न कुमार, अटेन्डर, होसानगर, शाखा को 22-7-1981 से सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[सं. एल०-12012(14)/82 डी/IV-ए]

ORDER

New Delhi, the 30th October, 1982

S.O. 465.—Whereas the Central Government is of opinion that on industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karnataka Bank Limited, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhyaya shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karnataka Bank Ltd., Mangalore in dismissing from service, Shri K. B. Prasarna Kumar, Attender, Hosenagar Branch, with effect from 22-7-1981 is justified ?If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

[No. L-12012(14)|82-D.IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1982

का०आ० 466.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय

जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुलराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र की उनके दक्षिण जोनल कार्यालय, मद्रास के संबन्ध में तारीख 8-5-81 को सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना के अनुसार इंजीनियरी विभाग (श्रेणी-III और श्रेणी IV) के 18 तकनीकी कर्मचारियों के काम के घंटे 8.30 से 12.30 तथा 13.30 से 17.30 तक (12.30 से 13.30 तक मध्याह्न भोजन की छुट्टी सहित) करके उनमें परिवर्तन करने की कार्यवाही न्यायोचित है। कर्मचारियों के कार्यघंटों में परिवर्तन करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है।

[संख्या एल-17011/8/81-डी IV(ए०)]
टी०बी० सीतारामन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th September, 1982

ORDER

S.O. 466.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise, of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of Section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri .T Arulraj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.
Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India in relation to its Southern Zonal Office, Madras, in changing the hours of work of 18 technical employees of the Engineering Department (Class-III and Class-IV) to 8.30 to 12.30 hours and 13.30 to 17.30 hours (with lunch break from 12.30 to 13.30 hours) as per the notice of change of service condition dated 8-5-81 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

[No. L-17011/8/81/D-IV(A)]
T. B. SITARAMAN, Desk Officer

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 467.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chanda Rayatwari Colliery of Western Coalfields Limited, Post Office Chanda Rayatwari, District Chandrapur (MS) and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Justice M. D. Kambli Esqr., Presiding Officer.

Reference No. CGIT-1 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to Chanda Rayatwari Colliery of Western Coalfields Limited.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer—Mr. L. S. Singh, Advocate.

For Lalzhanda Coalmines Mazdoor Union, Chandrapur—Mr. S. R. Pendre, General Secretary.

STATE : Maharashtra INDUSTRY : Coal & Mines

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-18012(14)81-D.IV(B) dated 29th January, 1982, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Chanda Rayatwari Colliery of Western Coalfields Limited and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Chanda Rayatwari Colliery of Western Coalfields Limited P.O. Chanda Rayatwari, Dist. Chandrapur in dismissing Shri Sudhakar Laxman Nandurkar, Ex-Security Guard from service with effect from 11-2-1981 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. Chanda Rayatwari Colliery is one of the Collieries under the Wardha Valley Area. Wardha Valley area itself is one of the areas under the Eastern Coalfields Limited, which is a company registered under the Companies' Act with its headquarters at Nagpur. It has collieries in various States like Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa. It is engaged in coal production which is said to be a basic industry.

3. The workman, Sudhakar Laxman Nandurkar, was working in this colliery since 21-1-1976. He was appointed as a Security Guard in or about year 1978. The incident which gave rise to his dismissal is dated 28-11-1980. On the sight of that day he was on duty on back siding. While he was on duty as a Security Guard, a cable valued at about Rs. 12,000 according to the employer, was stolen. This fact of theft is admitted by the workman. The departmental proceedings were started against him. A charge-sheet was issued to him on 29-11-1980. The workman gave a reply on 1-12-1980 stating that the theft occurred when he had gone out to drink water. The reply being not satisfactory the employer preceeded with the departmental inquiry. The Manager, Mr. N. P. Bhati, said himself held the depart-

mental inquiry. The inquiry was started on 13-12-1980. The employer was represented by one Mr. Gawande. One Mr. B. M. Bhadke acted as co-worker. The employer examined three witnesses, MW-1, MW-2 and MW-3. They were cross-examined on behalf of the workman. The workman examined himself. He did not examine any witnesses.

4. On the basis of the inquiry, the Enquiry Officer found that the theft of the cable had taken place in the third shift on 28-11-1980 from the back siding where the workman was supposed to be on duty. The factum of theft is not disputed on behalf of the workman. His explanation was that he had gone for drinking water and in the meantime the cable had been stolen by somebody. The Enquiry Officer observed that there was no pro of that the workman was directly involved in the theft, but it was proved beyond doubt that he was negligent in his duty. He further observed that had the workman been cautious and alert the theft of the cable would not have been there or the culprit would have been caught very easily. The Enquiry Officer submitted the papers to the Superintendent of Mines along with the proceedings in the departmental inquiry. The Superintendent of Mines submitted the papers to the Sub-Area Manager for his approval to the proposed action. The Sub-Area Manager by his letter dated 5-2-1981 after considering the papers gave his approval, to dismiss the workman from the service. The Superintendent of Mines by his letter dated 9/11-2-1981 dismissed the workman from the service, taking the view that the misconduct attributed to the workman was of serious nature.

5. Lalzhanda Coalmines Mazdoor Union, Chandrapur (hereinafter referred to as the "Union") filed the statement of claim on 12-3-1982. It was alleged that the departmental inquiry was not conduct in a fair and proper manner. It was admitted that the workman was on duty on the night of 28-11-1980 when the theft of the cable took place. However, it was alleged that the back siding area where he was on night duty was of the area of 900 metres and it was without a compound. It was further alleged that it took about half-an-hour to 45 minutes for taking one round in that area. It was also stated that the workman reported the fact of theft immediately on that very night to the patrolling gang and that efforts were made to trace the stolen property. The same, however, could not be traced. It was alleged that the inquiry held against the workman was not fair and proper and that therefore he should be reinstated in service with back wages.

6. The employer filed its written statement contending, inter alia, that the inquiry held against the workman was perfectly fair and proper and that he was given full chance to defend himself. It was stated that the workman was negligent in his duty and permitted the theft of property worth Rs. 12,000. No confidence, therefore, could be placed on the workman who was expected to guard the property. It was stated that his previous record was also bad and he was punished earlier also.

7. The charges framed against the workman was as follows :—

> "It is reported that a strailing cable of about 500 ft. which was kept with the welding set near the Rly. siding where new belt construction is going on, was stolen in the third shift of 28-11-80 while you were working as guard incharge of that area. This has caused a loss of nearly Rs. 12,000. to the company. It means that either you are involved in the theft or you must have been negligent in your duty.
>
> Your above acts are treated as misconduct under Standing Order No. 13(B) 1, 6 and 9."

The explanation given by the workman by his letter dated 10-12-1980 was that he had taken charges of the cable at 11.30 P.M. He had taken rounds in the area under his charge upto 2.30 A.M. The cable was there till that time. He get thirsty and, therefore, he want to drink water. He returned after drinking water. He than found that the cable was not there. He reported the matter immediately to Mr. Udairaj Shukla, who was a member of the petrolling staffff. A earch was made for the cable. A few pieces of the cable were thereafter found near the bridge. The workman concluded his explanation by saying that he always co-operated with the management and will do so in future.

8. Being not satisfied with this explanation the departmental inquiry was held against the workman. A preliminary point was raised that this inquiry was not fair and proper. An inquiry into the preliminary point whether the domestic inquiry conducted against the workman was fair and proper and in accordance with the principles of natural justice was held by me. By my order dated 13th September, 1982. I held that there was fair and proper inquiry in the matter. The main point argued by the Union at that stage was that the inquiry was held by the Manager, who was also the disciplinary authority and that, therefore, the inquiry was vitiated. I repelled the contention pointing out that clause 17 of the Standing Orders applicable to this establishment provided that the Manager may himself institute and conduct the domestic inquiry and punish the workman for any misconduct. I had been observed that it was not pointed out or established on behalf of the workman that the Manager had any special reason to have a grudge against the workman. I pointed out in my order that there was no any violation of the rules of natural justice or fair play if the disciplinary authority himself held the inquiry.

9. Now, the question is whether the charge framed against the workman has been proved. The employer examined three witnesses by name, (i) Mr. Udairaj Shukla, (ii) Mr. Sukhram Shimangal and (iii) Mr. Datta Sahare. The workman examined himself. He did not examine any witness. On the evidence adduced before him, the Inquiry Officer found that it was not proved that the workman was directly involved in the theft, but it was proved beyond doubt that he was negligent in his duty. The Enquiry Officer recorded his finding as follows :—

> "11. Shri Sudhakar Laxman has been found negligant in duty on 28-11-80 in the third shift and has not been proved to be directly involved in the theft case.
>
> 2. Had he been cautious and alert the cable theft would not have been thorn or the culprit would have been caught very easily ?"

10. The question for consideration that arises is whether the theft of the cable occurred due to the negligance of the workman. Having considered the evidence I hold that the workman was negligent and theft occurred due to his negligance. On the day in question the workman was working as a Security Guard in the third shift. This is not in dispute. One Mr. S. Shivmangal (MW-2) was on night duty as Chowkidar in the second shift. At about 11.30 p.m. he gave charge to this workman He stated in his statement that when he handed-over the charge to the workman he told him to take charge of the cable which was laid towards the mango tree. The workman than told him that there was darkness and lot the cable lying in the darkness go to hall. Mr. Shivmanagal stated that he reported about this matter to the Guard who allocated duties. Mr. Udairaj Shukla (MW-1) stated that Mr. Shivmanagal (MW-2) had complained to him that the workman had refused to take charge of the cable Immediately, he (Mr. Udairaj Shukla) went there and talked to the workman who stated to him that he had taken charge of the cable. The workman in his explanation dated 10-12-1980 and in his statement before the Inquiry Officer admitted that he had taken of the cable. He stated that the statement of Mr. Shivmangal that he had refused to take charge was not correct. His version was :—

> "Upto 2.30 a.m. I was taking rounds on petrolling the area, but when I felt thirsty, I thought to go near to Dubey Babu's house to drink water. I want towards Shri Dubey's house. I washed my face and hands and drank water and I reached on the same way where the cable was lying, but I did not find the cable. I reported this fact to the patrolling gang. Myself, Shri Sukla, Shri Ganesh and Shri Daniel were searching for the cable upto 5.30 A.M. but we did not succeed."

It is thus clear that the theft of the cable valued at Rs. 12 000 occurred while the workman was working as the Security

Guard in the third shift. His explanation was rejected by the Inquiry Officer with the following observations :—

"He may have gone for taking water but the length of the cable which has gone right from the well illuminated area starting from the siding side to the conveyor structure and it cannot be a job of one man which can be done within 3-4 minutes time."

The Inquiry Officer further observed that there had been a case of cable theft on 5-1-1979 in the 'A' type colony and incidentally it was a shift of this workman only. It appears that a register was produced before the Inquiry Officer on behalf of the management giving particulars about this theft on 5-1-1979. There is reference to the production of the register in the minutes of the Inquiry proceeding. I find that the theft of the cable took place because of the negligence of the workman. He is responsible for the loss caused to the establishment. I do not find sufficient reasons to interfere with the finding of the Inquiry Officer.

11. The question, however, is whether the workman is guilty of any misconduct as defined in the Standing Orders of the establishment. A copy of the Standing Orders has been placed on record. Clause 13(B) defines what acts or omissions can be treated as misconducts. In the charge framed by the Manager it is stated that the acts referred to in the charge are treated as misconduct under Standing Order No. 13(B)(1), (6) and (9). Item No. (1) of sub-clause (B) speaks of "theft, fraud or dishonesty in connection with the employer's business or property". Item No. (6) refers to "habitual neglect of work". Item No. (9) refers to "causing demage to work in progress or to the property of the employer". Obviously, this is not a case of damaging to the property of the employer. This is a case where it can be said that the workman had allowed the property to be taken away by some mis-creants, and thereby caused loss of the property of the employer. There is no charge of habitual neglect nor habitual neglect is prove. It is not proved that the workman himself committed the theft of the cable. The inquiry Officer has exhonorated him of that charge. Item No. (1) of sub-clause (B) is also, therefore, not attracted. Even though this point was not raised on behalf of the Union while arguing the case of the workman, the learned counsel for the employer was asked by me whether the workman can be punished for some act or omission which is not defined as a misconduct under the Standing Orders. It is argued for the employer that the Standing Orders of the establishment only describe certain cases of misconduct and the same cannot be exhaustive of all the species of misconduct which a workman may commit. Even though the given conduct may not come within the specific terms of misconduct described in the Standing Orders, it may still be a misconduct in the special circumstances of the case. Reliance is placed on behalf of the employer upon certain observations of the Supreme Court in the case of Mahendra Singh Dantwal v. Hindustan Motors Limited (1976 II L.L.J. 259). It is observed in para 22 :—

"Standing Orders of a company only describe certain cases of misconduct and the same cannot be exhaustive of all the species of misconduct which a workman may commit. Even though a given conduct may not come within the specific terms of misconduct described in the standing orders, it may still be a misconduct, in the special facts of a case, which it may not be possible to condone and for which the employer may take appropriate motion ordinarily, the standing orders may limit the concept but not invariably so."

12. Now, in the charge, after stating the facts it has been alleged that the act of the workman has caused a loss of nearly Rs. 12,000 to the company. It is further alleged that it meant that either the workman was involved in the theft or he must have been negligent in his duty. It is true that in the charge it has been stated that these acts are treated as misconduct under Standing Order No. 13(B)(1), (6) and (9). As I have pointed out the acts attributed to the workman do not fall under any of the said items of clause 13(B). Still certain acts as described in the earlier part of the charge have been attributed to the workman. Even though they do not come within the four corners of the Standing Orders, they, in my opinion, certainly be treated as misconduct. I, therefore, find that the workman is guilty of the misconduct attributed to him though it may not strictly fall within the four corners of the Standing Orders.

13. It appears that the Manager submitted the inquiry papers to the Sub Area Manager, Sub Area No. 3, who appears to be superior officer. The Sub Area Manager accepted the finding of the Manager. He also concerned the past record of the workman and observed that even if it has been clean there would still be justification to order the dismissal of the workman on the basis of the serious charge proved against him. It appears that the Sub Area Manager did not take into consideration the fact of previous theft on 5-1-1979 while the same workman was working as a Security Guard while dtermining the punishment of dismissal. It, however, appears that the Sub Area Manager wanted to say in his order that even if the past record had been clean there is still justification to order the dismissal of the workman. The question for consideration is whether the punishment of dismissal is proper. In the case of Ford Motor Company of India Ltd. and S. K. Naik (1952 I LLJ. 355) the Labour Appellate Tribunal of India observed that it was a serious dereliection of duty on the part of a workman to sleep while on duty and it is no mitigation to say that it is the only offence committed in the course of years. In the case of Jawahar Mills v. Raja Manickam (1954 I LLJ. 733) the Labour Appellate Tribunal of India held in the similar circumstances that the management was justified in taking the extreme action against the watchman as the theft was found to be due either to connivance of gross negligence of the three watchmen. When a watchman is entrusted with a vary valuable property for the purposes of the watch duty and where it is his duty to keep awake and to take rounds, regularly it would be a serious break of duty if he is found to be negligent, in the performance of his duty. I am, therefore, not inclined to interfare with the punishment of dismissal.

14. In the result, I find that the action of the management of Chanda Rayatwari Colliery of Western Coalfields Limited in dismissing the workman, Sudhakar Laxman Nandurkar from service with effect from 11-2-1981 is justified. The workman is not entitled to any relief.

15. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer.
[No. L-18012(IV)/81-D.IV(B)]

S.O. 468.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Parbelia Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Neturia, District Purulia, West Bengal and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No 25/82

PRESENT :

Shri J. N. SINGH, Presiding Officer

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parbelia Colliery of Messrs Eastern Coalfields Ltd., P.O. Neeturia, District Purulia.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. N Lala, Advocate.

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 22nd December, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d)

of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(71)/81-D.IV(B) dated the 25th March, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the Agent, Parbelia Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Neeturia, District Purulia, West Bengal, in terminating the employment of Sri Jageshpati Tripathi and 14 others w.e.f. 14th August, 1981 is justified? If not, to what relief they are entitled?"

2. On 15th December, 1982 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workmen.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

I. N. SINGH, Presiding Officer

Enc : Settlement.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 3, DHANBAD

Reference No. 25 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parbelia Colliery of Eastern Coalfields Ltd.,

AND

Their Workmen.

Joint petition of both the parties herein concerned

Both the parties submit and state as follows :—

1. That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal and the matter has not been heard as yet.

2. That soon after the failure of conciliation in the above matter on the 23rd October, 1981 and before the date of order of reference made on the 25th March, 1982 both the parties herein concerned after discussion of the aforesaid matter mutually arrived at a bi-partite settlement on 2nd January, 1982 whereby all the workmen herein concerned resumed their duties as from 1st February, 1982 and wherein the claim for any back wages was given up by the Union.

3. That in view of the circumstances stated in the foregoing paragraph there is no longer any dispute existing between the parties in respect of any matter within the purview of the instant order of reference and, therefore, both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass a 'No dispute' award in the instant matter.

4. That the petition has been made bonafide and for ends of justice.

PRAYER

Both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass a 'no dispute' award in the aforesaid matter.

And for this act of kindness, both the parties, as in duty bound, shall ever pray.

Dated this the 17th November, 1982.

Sd/- Illegible

For and on behalf of the workmen.

Sd/- Illegible

For and on behalf of the employers.

I. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-18012(71)/81-D.IVB]

S. S. MEHTA, Desk Officer,

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

का०आ० 469.—केन्द्रीय सरकार, धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के विनियम 16 के उपविनियम (1) के परन्तुक के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2793, तारीख 23 सितम्बर, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में "पश्चिमी जर्मनी" शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"पूर्वी जर्मनी (केवल विवृत खानों के लिए निर्बन्धित प्रबन्धक के प्रमाणपत्रों के प्रयोजनार्थ)

1. डाई बर्गाकाडेमिक फ्रेइबर्ग इन सेक्सन	इंजीनियरी में उपाधि (विवृत खनन)"

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं० का०आ० 2793 तारीख 23 सितम्बर, 1963 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 28 सितम्बर, 1963 के पृष्ठ 3582 पर प्रकाशित किया गया था।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:—

(1) अधिसूचना सं० का०आ० 2163 तारीख 11-6-1964
(2) अधिसूचना सं० का०आ० 4154 तारीख 27-11-1964
(3) अधिसूचना सं० का०आ० 1678 तारीख 30-5-1966
(4) अधिसूचना सं० का०आ० 1935 तारीख 21-5-1968
(5) अधिसूचना सं० का०आ० 4507 तारीख 10-12-1968
(6) अधिसूचना सं० का०आ० 4405 तारीख 22-10-1969
(7) अधिसूचना सं० का०आ० 1672 तारीख 25-4-1970
(8) अधिसूचना सं० का०आ० 3904 तारीख 18-9-1971
(9) अधिसूचना सं० का०आ० 3749 तारीख 30-10-1979

[सं० एस०-66025/3/82-एम० आई०]

आर० पी० नरूला, उप सचिव

New Delhi, the 5th January, 1983

S.O. 469.—In pursuance of clause (a) of proviso to sub-regulation (1) of regulation 16 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2793 dated the 23rd September, 1963 namely:—

In the Table appended to the said notification after the heading "West Germany" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"East Germany (Only for the purpose of Manager's Certificates restricted to opencast mines).

1. Die Bergakademie Freiberg in Sachsen	Degree in Engineering (Mining—Opencast)".

Note : Principal order was published vide Notification No. S.O. 2793 dated the 23rd September, 1963 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the

28th September, 1963 at page 3582.

Subsequently amended by—

(i) Notification No. S.O. 2163 dated 11-6-1964
(ii) Notification No. S.O. 04154 dated 27-11-1964
(iii) Notification No. S.O. 1678 dated 30-5-1966
(iv) Notification No. S.O. 1935 dated 21-5-1968
(v) Notification No. S.O. 4507 dated 10-12-1968
(vi) Notification No. S.O. 4405 dated 22-10-1969
(vii) Notification No. S.O. 1672 dated 25-4-1970
(viii) Notification No. S.O. 3904 dated 18-9-1971
(ix) Notification No. S.O. 3749 dated 30-10-1979

R. P. NARULA, Dy. Secy.
[No. S-66025/3/82-MI]

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

का०आ० 470.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2 जनवरी, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

1. निम्नलिखित राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र:—

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना का नाम	राजस्व थाना संख्या	जिला
1	2	3	4	5
1	फतेहपुर	झरिया (अधिसूचित क्षेत्र समिति)	130	धनबाद
2	लोदना	झरिया (पंचायत)	125	धनबाद
3	झरिया	झरिया (अधिसूचित क्षेत्र समिति)	131	धनबाद
4	बरताकोला	झरिया (पंचायत)	140	धनबाद
5	भेराकाता	झरिया (अधिसूचित क्षेत्र समिति)	141	धनबाद
6	झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्राम		..	धनबाद
II	टीपूदाना :			
	पुगडू	हटिया	250	रांची

[संख्या एस-38013/40/82-एच०आई०]

New Delhi, the 1st January, 1983.

S. O. 470.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 2nd January, 1983 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar, namely:—

I. The areas within the following revenue villages:—

Name of the Revenue Village	Name of Revenue Thana	No. of Revenue Thana	District
1. Fatehpur—	Jharia (Notified area Committee)	130	Dhanbad
2. Lodna	Jharia (Panchayat)	125	Dhanabad
3. Jharia	Jharia (Notified area Committee)	131	Dhanbad
4. Bartacola	Jharia (Panchayat)	140	Dhanbad
5. Bherakata	Jharia (Notified area Committee)	141	Dhanbad
6. All the revenue villages within Jharia Notified area Committee.		..	Dhanbad
II. Tipudana :			
Pugdu	Hatia	250	Ranchi

[No. S-38013/40/82-HI]

का०आ० 471 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम०बी० इंजीनियर्स वर्क्स, 313/46बी, इन्द्र लोक (जखीरा के नजदीक) देहली 110035 अपने कारखाने जो ए 57/1, जी०टी०, करनाल रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, देहली 110033 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्य, इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस–35019/499/82 पी०एफ०–2]

S.O. 471.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relataion to the establishment known as Messrs M. B. Engineering Works, 33/46-B, Inder Lok (Near Jakhira) Delhi-35 including its factory at A-57/1, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-33, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S. 35019(499)/82-PF-II]

का०आ० 472 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुजरात स्टेट कोपरेटिव फ्रूट एण्ड विजीटेबल मार्किटिंग फैडरेशन लि०, पो०बा० बाक्स नं० 172, सरदार बाग, बारदोली 394602 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/500/82-पी०एफ०–2]

S.O. 472.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relataion to the establishmen known as Messrs Gujarat State Co-operative Fruit and Vegetable Marketing Federation Limited, Post Office Box No. 172, Sardar Gaug, Bardoli-394602, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S. 35019(500)/82-PF. II]

का०आ० 473 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टूल होल्डर्स प्रा०लि०, एन 15 इंडस्ट्रीयल इस्टेट, उद्यमबाग बेलगाम-590008, कर्नाटक अपने रजिस्टर्ड आफिस जो अपनी ही फैक्टरी के परिवार में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/508/82–पी०एफ०–2]

S.O. 473.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tool Holders (Private) Limited, N-15, Industrial Estate, Udyambag, Belgaum-590008, Karnataka including its Registered Office at the Factory Premises itself, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(508)/82-PF-II]

का० आ० 474.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आई० टी० टी० फार ईस्ट एण्ड पेसीफिक इन्क, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस–35019/509/82 पी० एफ०-2]

S.O. 474.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs I.T.T. Far East and Pacific Inc., Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(509)/82-F-II]

का० आ० 475.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नंगलूर कोपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, पहला मेन रोड, नंगलूर मद्रास-61 अपनी शाखाओं जो (1) तीसरा मेन रोड, नंगलूर, मद्रास 61 और (2) एम० जी० आर० रोड, 61, स्टेट बैंक कालोनी, नंगलूर, मद्रास-61 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/435/82-पी० एफ०-2]

S.O. 475.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nanganallur Co-operative Stores Limited, 1st Main Road, Nanganallur, Madras-61 including its branchbtes at (1) 3rd Main Road Nanganallur, Madras-61 and (2) M.G.R. Road, 61, State Bank Colony, Nanganallur, Madras-61, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said estabilshment.

[No. S-35019(435)/82-PF. II]

का० आ० 476.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैक्सला प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, यूनिट नं० 38, तीसरी मंजिल, कामत इंडस्ट्रीयल इस्टेट, 396, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/113/82-पी०-एफ०-2]

S.O. 476.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Taxeela Printers and Stationers, Unit No. 38, 3rd Floor, Kamat Industrial Estate, 396, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-25, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act the said establishment.

[No. S-35018(113)/82-PF. II]

का० आ० 477.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डैवी हिल्सन, 17-सी, इंडियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता 13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35017/271/82-पी० एफ०-2]

S.O. 477.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Davy Hilson, 17-C, Indian Mirror Street, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(271)/82-PF. II]

का० आ० 478.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सर एक्सटिंग्वीशर्स (प्रा०) लि०, 163, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता 700014 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/272/82 पी० एफ० 2]

S.O. 478.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sur Extinguishers (Private) Limited, 163, Acharyya Jagadish Bose Road, Calcutta-14, have argeed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35017(272)/82-PF-II]

का० आ० 479.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० सी० ई० इंजीनियरिंग वर्क्स, 10/3, तालबागान लेन, कलकत्ता-17 अपने कार्यालय जो 2-ए और

2-बी, "आपानघर" 7, ब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता-700019 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/273/82-पी० एफ०-2]

S.O. 479.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A.C.E. Engineering Works, 10/3, Talbagan Lane, Calcutta-17 including its Office at 2-A and 2-B. "Aapanghar" 7, Bright Street, Calcutta-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S. 35017(273)/82-PF-II]

का०आ० 480.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिन्हा कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाऊस कम्पनी लि०, आलमपुर, एच० एन० 6, पो० आ० मशीला, जिला हावड़ा अपने रजि० मुख्य कार्यालय जो 55, भूपेन्द्र बोस एवन्यू, कलकत्ता-700004 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/274/82-पी० एफ०-2]

S.O. 480.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sinha Cold Storage and Warehouse Company (Private) Limited, Alampur, N.H. 6, Post Office Mashila, District Howrah including its Registered/Head Office at 55, Bhupnedra Bose Avenue, Calcutta-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(274)/82-PF-II]

का० आ० 481.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेतफेब इंडस्ट्रीज, 163, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-700014 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/275/82-पी० एफ०-2]

S.O. 481.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Metfab Industries, 163, Acharyya Jagadish Bose Road, Calcutta-14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(275)/82-PF-II]

का०आ० 482.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एसोसिएट इंजीनियर्स, 19-बी, ब्राड स्ट्रीट, कलकत्ता-700019 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/276/82-पी०एफ०-2]

S.O. 482.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Associate Engineers, 19-B, Broad Street, Calcutta-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(276)/82-PF-II]

का०आ० 483.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राज कुमार एण्ड प्रिंटिंग वर्कस, 11, उपेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, गेदा (24 परगनास) कलकत्ता-700057 अपने कार्यालय जो पी-2 कलकर स्ट्रीट, कलकत्ता-700070 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/277/82-पी०एफ०-2]

S.O. 483.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raj Kumar Dyeing & Printing Works, 11, Upendra Nath Mukherjee Road, Aiada (24-Parganas) Calcutta-57, including its Office at P-2, Kalakar Street, Calcutta-70, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(277)/82-PF-II]

का० आ० 484.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुडविल रबड़ इडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, 36, स्ट्रेन्ड रोड, कलकत्ता-700001 अपने कारखाने जो 23, कुमारपारा रोड, लिलुहा, हावड़ा में स्थित है के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उक्त उपबंध स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा, 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/278/82-पी०एफ०-2]

S.O. 484.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Goodwill Rubber Industries (Private) Limited, 36, Strand Road, Calcutta-1 including its Factory at 23, Kumarpara Road, Liluah, Howrah, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(278)/82-PF-II]

का० आ० 485.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैक्नोजेन्सीज, 209, पिकनिक गार्डन रोड, कलकत्ता 700039 अपने कार्यालय जो 9, राइफल रेंज रोड, कलकत्ता-700019 में स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/279/82-पी०एफ०-2]

S.O. 485.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Technogenics, 209, Picnic Garden Road, Calcutta-39 including its office at 9, Rifle Range Road, Calcutta-19 have agreed that the Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be mode applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(279)/82-PF-II]

का० आ० 486.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हो-वैक (इंडिया) प्रा० लि०, 101, बेलियाघाटा मेन रोड, कलकत्ता-700010 अपने रजिस्टर्ड कार्यालय जो उसी परिसर में है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/281/82-पी०एफ०-2]

S.O. 486.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hi-Vac (India) (Private) Limited, 101, Belliaghata Main Road, Calcutta-10 including its Registered Office in the same premises, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(281)/82-PF-II]

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1983

का० आ० 487.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान वर्क्स, 919, जैसोर रोड, कलकत्ता 55, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/68/82-पी०एफ० 2]

S.O. 487.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan Metal Works, 919, Jessore Road, Calcutta-55, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No. S-35017(68)/82-PF. II]

का० आ० 488:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पोद्दार आटोमोबाइल्स लिमिटेड, 36, चोरिंघी रोड, कलकत्ता-71, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35017/72/82-पी० एफ० 2]

S.O. 488.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Poddar Automobiles Limited, 36, Chowringhee Road, Calcutta-71, have agreed that the provisions of the Employes Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(72)/82-PF. II]

का०आ० 489:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिटको फैब्रिकेशन कन्सल्टेंटस (प्राइवेट) लिमिटेड, चटर्जी इन्टरनैशनल सेन्टर (19 वीं० मंजिल) 33-ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-71, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं०एस०-35017/73/82-पी०एफ०-2]

S.O. 489.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mitco Fabrication Consultants (Private) Limited, Chattarjee International Centre (19th Floor), 33-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta71, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No. S-35017(73)/82-PF. II]

का० आ० 490:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेस्टर्न कोरियर्स, 67/28, स्ट्रेन्ड रोड, कलकत्ता-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस० 35017/129/82-पी०एफ० 2]

S.O. 490.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Western Carriers, 67/28, Strand Road, Calcutta-6, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(129)/82-PF. II]

का० आ० 491:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स न्यू विस्टा स्कूल, 3, लाउडन स्ट्रीट, कलकत्ता 16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35017/131/82-पी०एफ० 2]

S.O. 491.—Whereas it appeals to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs New Vista School, 3, Loudon Street, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(131)/82-PF. II]

का० आ० 492:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फैबको एसोसिएट्स, 38/ए, पुलिन खटिक रोड, कलकत्ता 15 अंतर्गत 75, गणेश चन्द्र एवेन्यु, कलकत्ता 13 स्थित उसका कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/139/82 पी० एफ०-2]

S.O. 492.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fabco Associates, 38/A, Pulin Khatik Road, Calcutta-15 including its Office at 75, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No S-35017(139)/82-PF II]

का० आ० 493.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स टापर्स, 6/1, सरत बोस रोड, कलकत्ता-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/140/82-पी० एफ०-2]

S.O. 493.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Toppers, 6/1, Sarat Bose Road, Calcutta-20, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No S 35017(140)/82-PF II]

का० आ० 494.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, 188, गिरिश घोष रोड डाकघर बेलूरमठ, हावड़ा जिसके अंतर्गत 2, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13, स्थित उसका कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/141/82-पी०-एफ०-2]

S.O. 494—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Everest Engineering Works, 188, Girish Ghosh Road, Post Office Belurmath, Howrah including its Office at 2, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No. S 35017(141)/82-PF.II]

का० आ० 495.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड, 49 स्टीफन हाउस, 4, बी० बी० डी० बेग, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/142/82-पी०एफ०-2]

S.O. 495.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs East Indian Produce Limited, 49, Stephen House 4, BBD. Bag, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No S-35017(142)/82-PF.II]

का० आ० 496.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेस्क्यूवेयर कारपोरेशन, 38/ए, पुलिन खटिक रोड, कलकत्ता-15 जिसके अंतर्गत 75, गणेश चन्द्र एवेन्यू कलकत्ता-13, स्थित उसका कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनिम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/143/82-पी० एफ० 2]

S.O. 496.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rescuwear Corporation, 38/A, Pulin Khatic Road, Calcutta-15 including its Office at 75, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

(19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No S-35017(143)/82-PF.II]

का० आ० 497. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रगति इंजीनियरिंग 54, चौरिंघी रोड, कलकत्ता 71, जिसके अंतर्गत 58/8, गौशाला रोड लिलुआ, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल स्थित उसका कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/144/82-पी० एफ० 2]

S.O. 497.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pragati Engineering, 54, Chowringhee Road, Calcutta-71 including its factory at 58/8, Gaushala Road, Liluah, Howrah, West Bengal, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No S-35017(144)/82-PF.II]

का० आ० 498.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जी० एम० सी० इंडस्ट्रीज 57/4 बी० टी० रोड कलकत्ता-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/145/82-पी० एफ०-2]

S.O. 498.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs G.M.C. Industries, 57/4, B.T. Road, Calcutta-2, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No S-35017(145)/82-PF.II]

का० आ० 499.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ड्यूक्स फार्मेस्यूटिकल्स, 40-ए, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता 1, जिसके अंतर्गत 27/3, एस० एन० बनर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 36, स्थित उसकी प्रयोगशाला भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/149/82-पी० एफ०-2]

S.O. 499.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ducks Pharmaceuticals, 40-A, Strand Road, Calcutta-1 including its Laboratory at 27/3, S. N. Banerjee Street, Calcutta-36, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(149)/82-PF.II]

का० आ० 500.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंजीनियर्स एंटरप्राइसेस, 92, जी० सी० घोष रोड, कलकत्ता-48 जिसके अंतर्गत 2 चर्च लेन, कलकत्ता-1 स्थित उसका कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/150/82-पी० एफ०-2]

S.O. 500.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Engineers Enterprises, 92, G. C. Ghosh Road, Calcutta-48 including its Office at 2, Church Lane, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment

[No S-35017(150)/82-PF.II]

का० ग्रा० 501.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारतीय भाषा परिषद, 36-ए, शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता-17, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/226/82-पी०एफ०-2]

S.O. 501.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as **Messrs** Bhartiya Bhasha Parishad, 36-A, Shakespear Sarani, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(226)|82-PF.II]

का० ग्रा० 502.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स करोदा कैमिकल्स, पोस्ट बैग नं० 6733, 4/3, सिंघी बागान लेन, कलकत्ता-7, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/228/82-पी०एफ०-2]

S.O. 502.—Wheres it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as **Messrs** Kroda Chemicals, Post Bag No. 6733, 4/5, Singhee Bagan Lane, Calcutta-7, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(228)|82-PF.II]

का० ग्रा० 503.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मोडर्न इन्टरप्राइजिंग 121, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 अपने कारखाने जो पिर्गचा बबु, बरसात, 24, परगना और ब्रांच आफिस जो 14 बी, महर्षि देवेन्द्रा रोड, कलकत्ता-7 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/262/82-पी०एफ०-2]

S.O. 503.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Modern Enterprises, 121, Netaji Subhash Road, Calcutta-1 including its factory at Pirgacha, Babu, Barasat, 24-Parganas and Branch Office at 14-B, Maharshi Debendra Road, Calcutta-7, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(262)|82-PF.II]

का० ग्रा० 504.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रताप सिंह एण्ड कम्पनी, 26-बी, आर० जी० कार रोड, कलकत्ता-700004, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०/35017/263/82-पी० एफ०-2]

S.O. 504.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as **Messrs** Partap Singh and Company, 26-B, R. G. Kar Road, Calcutta-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(263)|82-PF.II]

का० ग्रा० 505.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्लापक्न एण्ड एसोसिएट्स 261/276/277/2, जी० टी० रोड, (एन), सलकिया (हावड़ा) अपने हैड आफिस जो 33/1, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/264/82-पी० एफ०-2]

S.O. 505.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Klipcon and Associates, 261|276|277|2, G.T. Road (N), Silkia (Howrah) including its Head Office at 33|1, Netaji Subhash Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(264)|82-PF.II]

का० आ० 506.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फ्रैंको सीमेन्ट वर्कस (कन्सट्रक्शन) 31, सलीमपुर रोड, कलकत्ता 700031 अपने गोदाम रजिस्टर्ड आफिस जो 1/2बी, हजरा रोड, कलकत्ता-700026 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/265/82-पी०एफ०-2]

S.O. 506.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Frenco Cement Works (Construction), 31, Salimpur Road, Calcutta-31 including its Godown|Registered Office at 1|2-B, Hazra Road, Calcutta-26, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(265)|82-PF.II]

का० आ० 507.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुभरा रबड़ कम्पनी, 12/1, एस० के० देब रोड, कलकत्ता-48 अपने कारखाना जो 10, एस० के० देब रोड, कलकत्ता-700048 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/266/82-पी० एफ०-2]

S.O. 507.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Subhra Rubber Company, 12|1, S. K. Deb Road, Calcutta-48 including its factory at 10, S. K. Deb Road, Calcutta-48, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No S-35017(266)|82-PF.II]

का० आ० 508.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल फूड प्रोडक्टस, 120, कोलिन स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/267/82-पी०एफ०-2]

S.O. 508.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Food Products, 120, Collin Street, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017(267)|82-PF.II]

का० आ० 509.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एलाइड फैबरीकेशन एण्ड मशीनिंग कार्पोरेशन, 8, कनाल स्ट्रीट, एन्टली, कलकत्ता-700014 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं०एस-35017/268/82-पी०एफ०-2]

S.O. 509.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Allied Fabrication and Machining Corporation, 8, Canal Street, Entally Calcutta-14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-3501/(268)|82-PF.II]

का० आ० 510.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डाटा मैनेजमेंट सेन्टर, 26, शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता-700017 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं०एस-35017/269/82-पी०एफ०-2]

S.O. 510.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Data Management Center 26, Shakespeare Sarani, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No S-35017(269)|82-PF II]

का० आ० 511.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सारकर एण्ड कम्पनी, 121, बेलियाघाटा मेन रोड, कलकत्ता-10 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35017/270/82-पी० एफ०-2]

S.O. 511.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sarker and Company 121, Beliaghata Main Road, Calcutta-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35017 (270)/82-PF.II]

का० आ० 512.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धन्ना सिंघा फिनिशर्स, गली वजीर ग्लास वर्क्स, जे०बी० नगर अंधेरी कुर्ला रोड, मुम्बई-59 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/29/82-पी० एफ०-2]

S.O. 512.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dhana Singhu Finishers, Galli, Wazir Glass Works J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Bombay-59 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[F. No. S-35018(29)/82-PF.II]

का० आ० 513.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजय वुडवर्क्स, 122, कैंप कनेरी, डाकघर भिवंडी, जिला ठाने (महाराष्ट्र) जिसके अन्तर्गत गाला इंडस्ट्रियल एस्टेट डंपिंग रोड, मुलंद (पश्चिम) मुम्बई-80 स्थित उसका कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/54/82-पी० एफ०2]

S.O. 513.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vijay Wood Works, 122, Kap Kaneri Post Bhiwandi District Thane (Maharashtra), including its Office at Gala Industrial Estate Dumping Road, Mulund (West), Bombay-80, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(54)/82-PF.II]

का० आ० 514.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स खादिलकर प्रोसेस स्टूडियों, 461/1, सदाशिव पथ, तिलक रोड, पूना-411030 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35018/101/82-पी० एफ० 2]

S.O. 514.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khadikar Process Studio, 461/1, Sadashiv Peth, Tilak Road, Poona-411030, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(101)/82-PF-II]

का० आ० 515.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजेश वायर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, सी-26ए, घटकोपर इंडस्ट्रीयल स्टेट, एल० बी० एस० मार्ग, घटकोपर, बम्बई-400086 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35018/102/82 पी० एफ० 2]

S.O. 515.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajesh Wire Manufacturing Company, C-26/A, Ghatkopar Industrial Estate, L.B.S Marg, Ghatkopar, Bombay-86, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(102)/82-PF II]

का० आ० 516.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उटा एडवर्टाइजिंग एजेन्सी, 12, धर्मपुत्रा, डा० अम्बेदकर रोड, दादर टी० टी० बम्बई-400014 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35018/103/82 पी० एफ०-2]

S.O. 516.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Uta Advertising Agency, 12, Dharamputra, Dr. Ambedakar Road, Dadar T.T. Bombay-14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(103)/82-PF-II]

का० आ० 517.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टेंडर्ड सर्वेयर्स (प्रा०) लि०, रामपार्ट हाउस, 22 के, दुबाष मार्ग, बम्बई 400023 अपने ब्रांच आफिस जो 17,

री लाईन, बीच, मद्रास 600001 में स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस 25018/104/82-पी० एफ०-2]

S.O. 517.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Standard Surveyors (Private) Limited, Rampart House, 22, K. Dubash Marg, Bombay-23 including its branch Office at 17, Second Line, Beach, Madras-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(104)/82-PF-II]

का० आ० 518.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लालफूल इन्वैस्टमैंट लि०, 1111 ए, रहेजा चैम्बर्स, 213, बैकबे रैक्लैमैशन स्कीम, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-21 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस 35018/105/82-पी० एफ०-2]

S.O. 518.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lalphul Investments Limited, 1111-A, Raheja Chambers, 213, Backbay Reclamation Scheme, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(105)/82-PF.II]

का० आ० 519.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स झन्तला इन्वैस्टमैंट लि०, 1111-ए, रहेजा चैम्बर्स, 213, बैकबे रैक्लैमैशन स्कीम, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-21 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35018/106/82-पी० एफ०-2]

S.O. 519.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jhantla Investments Limited, 1111-A, Raheja Chambers, 213, Backbay Reclamation Scheme, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employes' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(106)/82-PF.II]

का० आ० 520.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टैंडर्ड सर्वलैंस कारपोरेशन क्लैम्स रिकवरी एजेन्ट्स, रामपार्ट हाउस, 22, के दुबाष मार्ग, बम्बई-400023 अपने ब्रांच आफिस जो 17, दूसरी लाईन, बीच, मद्रास में स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35018/107/82-पी० एफ०-2]

S.O. 520.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Standard Surreillance Corporation, Claims Recovery Agents, Rampart House, 22, K. Dubash Marg, Bombay-23 including its branch Office at 17, Second Line Beach, Madras, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(107)/82-PF.II]

का० आ० 521—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एजीसीग्रो इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०, 47/19, चिपलूणकर रोड, पूना-411001 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-3501(109)82-पी० एफ०-2]

S.O. 521.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs AJCO Engineering (Private) Limited, 47/19, Chiploonkar Road, Erandavana, Pune-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(109)/82-PF.II]

का० आ० 522.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एन० एम० वादिया चेरिटीज, एन० एम० वादिया बिल्डिंग, 123, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-400023 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35018/108/82-पी०एफ०-2]

S.O. 522.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs N. M. Wadia Charities, N. M. Wadia Building, 123, Mahatma Gandhi Road, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(108)/82-PF.II]

1164 GI/82—12

शुद्धि-पत्र

का० आ० 523.—भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3, उप खण्ड (ii), तारीख 8 मई, 1982 पृष्ठ 1886 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 1690, तारीख 22 अप्रैल, 1982 में, तीसरी पंक्ति में "तालुम" शब्द के स्थान पर "तालुक" पढ़ें ।

[सं० एस-35019/252/81-पी०एफ० 2]

CORRIGENDUM

S.O. 523.—In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour No. S.O. 1690 dated the 22nd April, 1982 published at page 1886 of the Gazette of India, Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the 8th May, 1982 in line 5, for "Mundiayambakkam" read "Munidiyambakkam".

[No. S-35019(252)/81-PF.II]

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1983

का० आ० 524.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डिविजनल कमिश्नर्स आफिस कैंटीन, डी० सी० कम्पाउंड, बेलगांव, कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(112)82-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 524.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Divisional Commissioner's Office Canteen, D.C. Compound, Belgaum, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(112)/82-PF.II]

का० आ० 525.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रोसेस स्पेशलटीस, 103, पेरम्बूर बैरक्स रोड, मद्रास- 7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(121)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 525.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs process Specialities, 103, Perambut Barracks Road, Madras-7, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(121)/82-PF.II]

का० आ० 526.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुरू तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, डी-1/14, माडल टाउन, दिल्ली-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं –

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(116)/82-पी०एफ० 2]

S.O. 526.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Guru Teg Bahadur Public School, D-1/14, Model Town, Delhi-9. have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(116)/82-PF.II]

का० आ० 527.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टेल्को ट्रांस्पोर्ट कान्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन, जिन्दल हाउस, 1/9, बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली जिसके अन्तर्गत जमशेदपुर स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(118)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 527.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Telco Transpor Contractors Association, Jindal House, 1/9-B, Asaf Ali Road, New Delhi including its branch at Jamshedpur, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(118)/82-PF.II]

का० आ० 528.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनैशनल पंप्स एंड प्राजेक्ट (आई) (प्राइवेट) लिमिटेड, 9, रिंग रोड, लाजपतनगर IV, नई दिल्ली-24 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(120)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 528.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Pumps and Project (I) (Private) Limited, 9, Ring Road, Lajpat Nagar IV, New Delhi-24, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(120)/82-PF.II]

का० आ० 529.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कृष्णा राईस एण्ड फ्लोर मिल्स, जेंयपोर, कोरापुट उड़ीसा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(136)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 529.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Krishna Rice and Flour Mills, Jeypore, Koraput, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(136)/82-PF.II]

का० आ० 530.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कृष्णा आटो इंडस्ट्रीज, बी-32, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कटक-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(135)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 530.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Krishna Auto Industries, B-32, Industrial Estate, Cuttack-10, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(135)/82-PF.II]

का० आ० 531.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जगमोहन मैटल इंडस्ट्रीस, रसूलगढ़, भुवनेश्वर, पुरी-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(134)/82-पी० एफ० 2]

S.O. 531.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jagmohan Metal Industries, Rasulgarh, Bhubaneshwar, Puri-1 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(134)/82-PF.II]

का० आ० 532.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स करनावती आटो (प्रा०) लिमिटेड, 371-372, ईसनपुर, पुरुषोत्तम ईस्टेट, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(421)/82-पी० एफ० 2]

S.O. 532.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Karnavati Auto (Private) Limited, 371-372, Isanpur, Purshottam Estate, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(421)/82-PF.II]

का० आ० 533.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भूपति मैच इंडस्ट्रीस, आर० एस० सं० 38/7, आलमट्टी गाव, वृद्धनगर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019(126)/82-पी० एफ० 2]

S.O. 533.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Boopathy Match Industries, R. S. No. 38/7, Allamatti Village, vrudhnagar, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No S-35019(126)/82-PF. II]

का० आ० 534.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रिसिजन इंस्ट्रूमैंटस एंड इलैक्ट्रोनिक्स, (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड, 50, लैटिस ब्रिज रोड, मद्रास-20, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/419/82-पी० एफ०-2]

S.O. 534.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Precision Instruments and Electronics (Madras) Private Limited, 50, Lattice Bridge Road, Madras-20, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(419)/82-PF. II]

का० आ० 535 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैसूर कैमिकल इण्डस्ट्रिज, सी०-21 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, राजाजीनगर, बंगलौर-44, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/420/82- पी० एफ० 2]

S.O. 535.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mysore Chemical Industries, C-21, Industrial Estate, Rajajinagar, Bangalore-44, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(420)/82-PF. II]

का० आ० 536 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरबन कोआपरेटिव सोसाईटीज लिमिटेड, गोपी सर्कल, नेहरु रोड, शिमोगा-577201 (कर्नाटक), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/418/82- पी० एफ० 2]

S.O. 536.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Urban Cooperative Society Limited, Gopi Circle, Nehru Road, Shimoga-577201 (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(418)/82-PF. II]

का० आ० 537 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टी० वी० नरसिम्हम एण्ड कम्पनी, सूर्यबाग, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-350149/10/82- पी० एफ० 2]

S.O. 537.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs T. V. *Narasimham* and Company, *Suryabagh, Visakhapatnam*, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(410)/82-PF. II]

का० आ० 538.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनीवर्सल आटो प्रोडक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड, ए-3, नारायणा इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-28, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/408/82- पी० एफ० 2]

S.O. 538.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Universal Auto Products (Private) Limited, A-3, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-28, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(408)/82-PF.II]

का० आ० 539.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टी० जी० लक्ष्मय्या सेट्टी एजेन्सी डिवीजन, अडोनी, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/386/82-पी०एफ० 2]

S.O. 539.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs T. G. Lakshmayya Setty Agency Division, Adoni, Kurnool District, (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(386)/82-PF. II]

का० आ० 540.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इम्प्रेशन्स इंटरनैशनल, 20/14, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-8, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/247/82-पी०एफ० 2]

S.O. 540.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Impressions International, 20/14, West Patel Nagar, New Delhi-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(247)/82-PF. II]

का० आ० 541.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडस्ट्रियल पंचिस, सं० 29, डाडनेकुंडी औद्योगिक क्षेत्र, II, स्टेज, बोक्स सं० 4816, महादेवपुरा डाकघर, बंगलौर-48, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/244/82-पी०एफ० 2]

S.O. 541.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Industrial Punches, No. 29, Doddanekundi Industrial Area, II Stage, Post Box No. 4816, Mahadevapura Post, Bangalore-48; have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S. 35019(244)/82-PF.II]

का० आ० 542.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टी० पैकिंग, सिण्डिकेट बाजार रोड, मट्टनचेरि गांव, कोचीन-2, केरल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/245/82-पी०एफ०-2]

S.O. 542.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tea Packing, Syndicate Bazar Road, Mattancherry Village, Cochin-2, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(245)/82-PF II]

का० आ० 543.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरके माटूर एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीस, एक्स एल/1148, कालूर, कोचीन-682017, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/242/82-पी०एफ०-2]

S.O. 543.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arkay Motor and Engineering Industries, XL/1148, Kaloor, Cochin-682017, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(242)/82-PF II]

का० आ० 544.—केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि मैसर्स ए-2835, कंडपकोट्टाई मिल्क सप्लाई कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कल्लाकुन्डु डाकघर, मदुरै जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/239/82-पी०एफ०-2]

S.O. 544.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A-2835, Kandappakottai Milk Supply Cooperative Society Limited, Kul alakundu Post, Mudurai District, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(239)/82-PF II]

का० आ० 545.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एजेन्सीस इन्टरनैशनल, वेस्ट एंड होटल, रेसकोर्स रोड, बंगलौर-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/240/82-पी०एफ०-2]

S.O. 545.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Agencies International, West End Hotel, Race Cource Road, Bangalore-1, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(240)/82-PF II]

का० आ० 546 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मदरै रामनाड बस ओनर्स एसोसिएशन, 153, नार्थ वेलि स्ट्रीट, मदरै, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/238/82-पी०एफ० 2]

S.O. 546.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madurai Ramnad Bus Owners Association, 153, North Veli Street, Madurai, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(238)/82-PF. II]

का० आ० 547.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पायनियर डीजल इक्विपमेंट्स, 247, नायकर न्यू स्ट्रीट, मदुरै-1 जिसके अंतर्गत 63, वेस्ट स्ट्रीट रामेश्वरम स्थित उसकी शाखा भी है । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर समहत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/237/82-पी० एफ०-2]

S.O. 547.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pioneer Diesel Equipments, 247, Naicker New Street, Madurai-1 including its branch at 63, West Street, Rameswaram, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(237)/82-PF. II]

का० आ० 548.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डैक्स इलेक्ट्रानिक्स, बी-210, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, नई दिल्ली-20 जिसमें उनका, 7, नेशनल पार्क, नई दिल्ली-24 स्थित कार्यालय भी शामिल है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/184/82-पी० एफ०-2]

S.O. 548.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dax Electrnoics, B-210, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20, including its office at 7, National Park, New Delhi-24, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(184)/82-PF. II]

का० आ० 549.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्टेक्स इंडिया, ए-25, हौज खास, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/181/82-पी० एफ-2]

S.O. 549.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Artex India, A-25, Hauz Khas, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(181)/82-PF. II]

का० आ० 550.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वात्स ट्यूब कारपोरेशन, 29/2, शंभुदास स्ट्रीट, मद्रास-600001 जिसके अंतर्गत सं० 8/2, मेट्टुपालयम रोड, कोयम्बटूर-641041 स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/171/82-पी० एफ० 2]

S.O. 550.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sreevatsa Tube Corporation, 29/2, Sembudoss Street, Madras-600001 including its branch at No. 8/2, Mattupalayam Road, Coimbatore-641011, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35019(171)/82-PF. II]

का० आ० 551.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन (रजिस्टर्ड) 18, कालेज रोड, नंगम्बकम, मद्रास-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/175/82-पी० एफ० 2]

S.O. 551.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Medical Research Foundation (Registered), 18, College Road, Nungambakkam, Madras-6 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(175)/82-PF. II]

का० आ० 552.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हाफेजपेट फेल्सपर एण्ड क्वार्टज माइन्स हाफेजपेट, कुकटपल्ली हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/174/82-पी० एफ-2]

S.O. 552.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Hafezpet Felsper and Quartz Mines, Hefezpet, Kukatpally, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(174)/82-PF.II]

का० आ० 553.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिंगन आटो गैरेज, 231-1, कामराजर रोड मदुरै-625009 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/169/82-पी० एफ० 2]

S.O. 553.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lingan Auto Garage, 231-1, Kamarajar Road, Madurai-625009, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(169)/82-PF.II]

का० आ० 554.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पीटर (एस) सप्लिंटस (प्राइवेट) लिमिटेड, 5/27, औद्योगिक क्षेत्र, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/166/82-पी० एफ० 2]

S.O. 554.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Peter(S) Splints (Private) Limited, 5/27, Indusrial Area, Kirti Nagar, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(166)/82-PF II]

का० आ० 555.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पट्टमदाई फाइन मैट वीवर्स को-आपरेटिव प्रोडक्शन एण्ड सेल्स सोसाइटी लिमिटेड, 0-1773, पट्टमदाई, तिरुनेलवेली जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/168/82-पी० एफ० 2]

S.O. 555.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Pattamadai Fine Mat Weavers' Co-operative Production & Sales Society Limited, 0-1773, Pattamadai, Tirunelveli District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(168)/82-PF II]

का० आ० 556.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिकल्स, 525, सोनारी वेस्ट ले आउट, जमशेदपुर-831011, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/165/82-पी० एफ०-2]

S.O. 556.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan Electricals, 525, Sonari West Layout, Jamshedpur-831011, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscelaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(165)/82-PF.II]

का० आ० 557.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूकेन इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बक्स 41-43, लेवेले रोड, बंगलौर-1 और उसकी शाखाएं (1) मोरल को-आपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट, मुम्बई और (2) 27, थियेटर, रोड, कलकत्ता, और व्हाइट फील्ड रोड, बंगलौर-1 स्थित उसका कारखाना, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/150/82-पी० एफ-2]

S.O. 557.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yuken India Limited, Post Box No. 41-43, Lavelle Road, Bangalore-1 and its branches at (1) Moral Co-operative Industries Estate, Bombay and (2) 27, Theatre Road, Calcutta and its factory at White Field Road, Bangalore-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(150)/82-PF.II]

का० आ० 558.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मदर्न टूल्स सर्विसेस, 14-ए, एस० पी० इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, मद्रास-600032 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/170/82-पी० एफ०-2]

S.O. 558.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Southern Tools Services, 14-A, S.P. Industrial Estate, Guindy, Madras-600032, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(170)/82-PF.II]

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

का० आ० 559.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए-1467 पट्टीविरानपथी कापरेटिव स्टोर्स लि०, पट्टीविरानपथी, नीलाकोटा तालुक, मदुरै डिस्ट्रीक्ट, (तमिलनाडु) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस० 35019/439/82 पी०एफ०-2]

New Delhi, the 5th January, 1983

S.O. 559.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A-1467, Pattiveeranpathi Co-operative Stores Limited, Pattiveeranpathi, Nilakotai Taluk, Madurai District, (Tamil Nadu), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(439)/82-PF.II]

का० आ० 560.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राज कुमार एण्ड कम्पनी, बैरागोड़ा, पोस्ट आफिस रहारगोरा, जमशेद पुर (बिहार) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35019/440/82-पी०एफ०-2]

S.O. 560.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raj Kumar and Company, Bairegora, Post Office Rahargora, Jamshedpur, (Bihar), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(440)/82-PF.II]

का० आ० 561.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निदादावोले कन्जूमर्स कापरेटिव सेन्ट्रल स्टोर्स लि०, न० डब्ल्यू० आर० 92 (जनता सुपर बाजार), निदादावोले, वेस्ट गोदावरी जिला (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[स०एस०-35019/441/82-पी०एफ०-2]

S.O. 561.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nidadavole Consumers Co-operative Central Stores Limited, No. W.R. 92 (Janata Super Bazar) Nidadavole, West Godavari District (Andhra Pradesh) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(441)/82-PF.II]

का० आ० 562.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल अन्ना-पूर्णा (रेस्टोरेंट बोर्डिंग एण्ड लोजिंग) ए०पी०एस०आर०टी० सी० कम्पलैक्स, एलरु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35019/442/82-पी०एफ०-2]

S.O. 562.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Anapurna (Restaurant Boarding and Lodging), A.P.S.R.T.C. Complex, Eluru, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Mescellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35019(442)/82-PF. II]

का० आ० 563.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी पेपर प्रोडक्ट्स लि०, 1-9-1124, आजामाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया, हैदराबाद-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/443/82-पी०एफ०-2]

S.O. 563.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Paper Products Limited, 1-9-1124, Azamabad Industrial Area, Hyderabad-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(443)/82-PF-II]

का० आ० 564.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माक कन्ट्रोलस कारपोरेशन, 8/181-ए, त्रिची रोड, कोयम्बटूर-18 जिसके अन्तर्गत 10/196-सी, डा० नंजाप्पा रोड, कोयम्बटूर-18 में स्थित उसका कार्यालय भी है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35019/448/82पी०एफ०-2]

S.O. 564.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mak Controls Corporation, 8/181-A, Trichy Road, Coimbatore-18 including its Office at Coimbatore, 10/196-C, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore-18, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(448)/82-PF.II]

का० आ० 565.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाथी कोपरेटिव डेरी लिमिटेड, डोडडाबाथी, दावनागर, तालुक । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[सं०एस०-35019/457/82-पी०एफ०-2]

S.O. 565.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bathi Co-operative Dairy Limited, Doddabathi, Davanagere Taluk, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(451)/82-PF.II]

का० आ० 566.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एयरटैक (प्रा०) लिमिटेड, ओल्ड पावर हाउस कम्पाउंड, धारवाड-1 (कर्नाटक) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[सं०एस०-35019/453/82पी०एफ०-2]

S.O. 566.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Airtech (Private) Limited, Old Power House Compound, Dharwad-1, Karnataka, have

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(453)/82-PF.II]

का० आ० 567.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अविनाश इंजीनियरिंग वर्क्स, 982, खानपुर रोड, तिलकवाडी बेगाम, कर्नाटक स्टेट, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/455/82-पी०एफ०-2]

S.O. 567.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mesrs Avinash Engineering Works, 982, Khanapur Road, Tilakwadi, Belgaum, Karnataka State, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(455)/82-PF. II]

का० आ० 568.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंदिरा इंडस्ट्रीज, 3/4, बस्ती हरफूल सिंह, देहली 6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/498/82-पी०एफ०-2]

S.O. 568.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs India Hosiery Industries, 3/4, Basti Harphool Singh, Delhi-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(498)/82-PF-II]

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

का० आ० 569.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आजाद रोलर फ्लोर मिल्स, बी०डी० रोड, चित्रदुर्गा-577501 (कर्नाटक) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/436/82-पी०एफ०-2]

S.O. 569.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Azad Roller Flour Mills, B. D. Road, Chitradurga-577501 (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(436)/82-PF-II]

का०आ० 570.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस०बी० सवर्णा एण्ड कम्पनी, नं० 10, इंडस्ट्रीयल टाउन, राजाजीनगर, बंगलौर-44 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/437/82-पी०एफ०-2]

S.O. 570.—Whereas it appears to the Cental Govenment that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. B. Suvarna and Company, No. 10 Industrial Town, Rajajinagar, Bangalore-44, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(437)/-PF-II]

का०आ० 571.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के०डी० लैम्प इंडस्ट्रीज, 11-एक्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/422/82-पी०एफ-2]

S.O. 571.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kay Dee Lamp Industries, 11-X, Okhala Industrial Area, Phase, II, New Delhi-20, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(422)/82-PF-II]

का० आ० 572.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजेश इंडस्ट्रीज, 56-बी, रामा मार्ग, नई दिल्ली-15 अपने कारखाने जो 62, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/423/82-पी०एफ-2]

S.O. 572.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajesh Industries, 56-B, Rama Marg, New Delhi-15 including its factory at 62, Najafgarh Road, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S. 35019(423)/82-PF-II]

का० आ० 573.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धरीत्री बी/26, इंडस्ट्रियल इस्टेट, भुवनेश्वर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/424/82-पी०एफ-2]

S.O. 573.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dharitri, B/26, Industrial Estate, Bhubaneshwar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(424)/82-PF II]

का० आ० 574.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अहमदाबाद हार्डवेयर स्टोर्स, मेनितहाउस, कादिय कूई, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35019/425/82-पी०एफ०-2]

S.O. 574.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ahmedabad Hardware Stores, Menit House, Kadia Kui, Relief Road, Ahmedabad-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(425)/82-PF-II]

का० आ० 575.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स बिरन मैन्युफैक्चरिंग कं० (केबल्स) प्रा० लि०, 460, सम्भु नाथ कंपाउन्ड, जी०टी० रोड, शाहदरा, देहली-32, अपने कार्यालय जो 7, अंसारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली-6 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(426)82-पी०एफ०-2]

S.O. 575.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Biren Manufacturing Company (Cables) Private Limited, 460, Sambhu Nath Compound, G.T. Road, Shahdara, Delhi-32 including its Office at 7, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(426)/82-PF-II]

का० आ० 576.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरिहर साह कंट्रेक्टर, सेक्टर-2, झुम्पडी मार्किट, राउरकेला-1, सुन्दरगढ़, उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(427)82-पी०एफ०-2]

S.O. 576.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harihar Sah, Contractor, Sector-2, Jhumpdi Market, Rourkela-1, Sundergarh, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(427)/82-PF-II]

का० आ० 577.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कार्थिका फिशरीज, थवपुमपडी, कोचीन-5 (केरल) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(428)82-पी०एफ०-2]

S.O. 577.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Karthika Fisheries, Thoppumpady, Cochin-5, (Kerala), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(428)/82-PF-II]

का० आ० 578.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट रबड़ प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल (वर्कशाप) कोपरेटिव सोसाइटी लि०, नं० एस० आई एन डी (टी) 301, वाल्लाकाडुवा, त्रिवेन्द्रम-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(429)82-पी०एफ०-2]

S.O. 578.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Trivandrum District Rubber Products Industrial (Workshop) Co-operative Society Limited, No. S. IND(T)301, Vallakaduva, Trivandrum-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(429)/82-PF-II]

का० आ० 579.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पन्याम सीमेन्टस कोपरेटिव स्टोर्स लि०, सीमेन्ट नगर, कुरनूल जिला, (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(431)82-पी०एफ०-2]

S.O. 579.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Panyam Cements Co-operative Stores Limited, Cement Nagar, Kurnool District, (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(431)/82-PF-II]

का० आ० 580.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दाढा फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि०, 108, नैनियाप्पा नैकन स्ट्रीट, मद्रास-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(432)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 580.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dadha Finance and Investments Limited, 108, Nyniappa Naicken Street, Madras-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35019(432)/82-PF-II]

का० आ० 581.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जय एजेन्सीज, 38/131-ए, टी० डी० रोड, एरनाकुलम, कोचीन-II नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(433)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 581.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jai Agencies 38/131-A, T.D. Road, Ernakulam, Cochin-11, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(433)/82-PF-II]

का० आ० 582.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी विजयालक्ष्मी फाइनेंस (प्रा०) लि०, कुनियामुथुर पोस्ट, कोयम्बटूर-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(434)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 582.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Vijayalakshmi Finances (Private) Limited, Kuniamuthur Post, Coimbatore-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S.35019(434)/82-PF-II]

का० आ० 583.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत फाइनेंस कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, 20/1 आसफअली रोड, नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(46)/82-पी०एफ०-2]

S.O. 583.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Finance Corporation (Private) Limited, 20/1, Asaf Ali Road, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(46)/82-PF-II]

का०आ० 584.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्लेस्टन केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स, गुनाडाला, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/109/82-पी०एफ० 2]

S.O. 584.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Blesston Chemical and Pharmaceuticals, Gunadala, Vijayawada, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(109)/82-PF-II]

का०आ० 585.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लेम्टफ प्लास्टिक्स, प्लाट सं० 3, एक्सपेंशन प्रोग्राम, कुतुबुल्लापुर, बालानगर, हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35019(110)82-पी०एफ० 2]

S.O. 585.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lematuf Plastics, Plot No. 3, Expansion Programme, Kuthbullapur Balanagar, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(110)/82-PF-II]

का०आ० 586.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० एटचन्ना नायडु कान्ट्रेक्टर, श्री हरिपुरम, विशाखापटनम-II, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35019(111)82-पी एफ 2]

S.O. 586.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. Atchanna Naidu Contractor, Sriharipuram, Visakhapatnam-11, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(111)/82-PF-II]

का०आ० 587.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारती कन्सट्रक्शन्स इंजीनियर्स एण्ड कन्ट्रेक्टर्स, 43-5-20, नई कालोनी, विशाखापत्तनम-530016 (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस-350191(430)82-पी०एफ०-2]

S.O. 587.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharati Constructions Engineers and Contractors, 43-5-20, New Colony, Visakhapatnam-530016 (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(430)/82-PF-II]

का०आ० 588.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रसिकलाल हेमानी एजेंसीज (प्राईवेट) लिमिटेड 506, खारी बावली, दिल्ली-110006, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/490/82-पी०एफ०-2]

S.O. 588.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rasiklal Hemani Agencies (Private) Limited, 506, Khari Baoli, Delhi-110006, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(490)/82-PF-II]

का०आ० 589.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डागा शीपींग एजेंटस प्राईवेट लिमिटेड, 8, केनींग स्ट्रीट (बीपलाबी रासबिहारी बासु रोड), कलकत्ता-700001, जिसमें उनकी कान्ता भवन, 1, जैन मन्दिर रोड, नई दिल्ली-110001 स्थित शाखा भी शामिल है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/491/82-पी०एफ०-2]

S.O. 589.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Daga Shipping Agents Private Limited, 8, Canning Street, (Biplabi Rasbehari Basu Road), Calcutta-700001 including its branch at Kanta Bhawan, 1, Jain Mandir Road, New Delhi-110001, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(491)/82-PF-II]

का०आ० 590.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रजिक प्रीसीसन प्रोडक्टस, 44, कामाकशीपालया, मगाडी रोड, बंगलौर-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/452/82-ए०एफ-2]

S.O. 590.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Razic Precision Products, 44, Kamakshipalya, Magadi Road, Bangalore-23, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(452)/82-PF-II]

का०आ० 591.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स कर्नाटक ग्राउन्डनट प्रोडक्टस (प्रा०) लिमिटेड, 370/1, गोकुल विलेज, हुब्ली (कर्नाटक) जिसके अन्तर्गत न्यू काटन मार्किट, हुब्ली-29 स्थित उसका प्रशासनिक कार्यालय, 47/48, शान्ती कालोनी (नार्थ), हुब्ली-32 में स्थित उसका रजिस्टर्ड कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/454/82-पी०एफ०-2]

S.O. 591.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estblishment known as Messrs Karnataka Groundnut Products (Private) Limited, 370/1, Gokul Village, Hubli (Karnataka), including its administrative Office at new Cotton Market, Hubli-29 and Registered Office at 47/48, Shanti Colony (North), Hubli-32, have agreed that the provsions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(454)/82-PF-II]

का०आ० 592.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजन लेदर मैन्यूफैक्चरर्स (प्रा०) लिमिटेड, टेनरी, मदुरै रोड, बेगमपुर, डिंडीगुल-2, नामक स्थापन से संम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस/35019/449/82-पी०एफ०-2]

S.O. 592.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajan Leather Manufacturers (Private) Limited, Tannery, Madurai Road, Begampur, Dindigul-2, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(449)/82-PF-II]

का० आ० 593.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कार्नीयल ईस्टेट, सिरुमालई हिल्स, पट्टीवीरापट्टी, मदुराई डिस्ट्रीक्ट (तमिल नाडू) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/450/82-पी० एफ-2]

S.O. 593.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Corneal Estate, Sirumalai Hills, Pattiveeranpatti, Madurai District (Tamil Nadu), have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(450)/82-PF-II]

का० आ० 594.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिंकसन फर्मा, 148, मद्रास त्रिवेल्लोर हाई रोड, तिरुनीनरावर-602024 चंगालपट्ट, जिला अपने प्रशासनिक कार्यालय जो 152, नैनाप्पा नायक स्ट्रीट, मद्रास-3 में है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/444/82-पी० एफ०-2]

S.O. 594.—Wheeas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Linkson Pharma, 148, Madras Tiivellore High Road, Tiruninravur-602024 Chengalpattu District including its Administrative Office at 152, Nyneappa Naick Street, Madras-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(444)/82-PF-II]

का० आ० 595.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे० बी० एक्सपोर्टस हाउस (प्रा०) लि०, 7/26, कीर्ती नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-110015 अपने रजिस्टर्ड आफिस जो कठोक बिल्डिंग, ग्राउन्ड फ्लोर, दादर रोड, दादर, बम्बई-14 में स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/497/82-पी० एफ०-2]

S.O. 595.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs J. B. Exports House (Private) Limited, 7/26, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-15 including its Registered Office at Kathoke Building, Ground Floor, Dadar Road, Dadar, Bombay-14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(497)/82-PF-II]

का० आ० 596.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गंगावती क्लाथ सेन्टर, दजिबन पथ, हुबली-20 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/438/82-पी० एफ०-2]

S.O. 596.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gangavati Cloth Centre,

Dajiban Peth, Hubli-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(438)/82-PF-II]

का० आ० 597.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मोहन जूपैक लि०, 4-एफ, हंसालया, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/495/82-पी०एफ०-2]

S.O. 597.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mohan Zupack Limited, 4-F, Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(495)/82-PF-II]

का० आ० 598.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माफिया इलैक्ट्रोनिक्स, सी-148, नरायणा इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-28 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है

[सं० एस-35019/496/82-पी०एफ०-2]

S.O. 598.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Matha Electronics, C-148, Naraina Industrial Area, New Delhi-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(496)/82-PF-II]

का० आ० 599.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रीमियर जनरल फाइनेंस लि० "प्रीमियर हाऊस", ए०टी०डी० स्ट्रीट, रेस कोर्स, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु स्टेट नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/494/82-पी०एफ०-2]

S.O. 599.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Premier General Finance Limited, "Premier House", A.T.D. Street, Race Course, Coimbatore-641018, Tamil Nadu State, have agreed that the provisions of the Emjloyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(494)/82-PF-II]

का० आ० 600.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंडियान कैमिकल्स लि०, नरसिंगामपट्टी, मेलूर, तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु, अपने प्रशासनिक कार्यालय जो सं०-9, विनायगा नगर, मदुरै-20 में स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/492/82-पी०एफ०-2]

S.O. 600.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pandian Chemicals Limited, Narasingampatti, Melur Taluk, Madurai District, Tamil Nadu including its Administrative Office at No. 9, Vinayaga Nagar, Madurai-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicatle to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(492)/82-PF.-II]

का० आ० 601.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलैक्ट्रो मैकेनिकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज, कुशायगुडा, हैदराबाद-5000762 (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एस-35019/493/82-पी० एफ०-2]

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 601.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electro Mechanical & Electronics Industries, Kushaiguda, Hyderabad-762, (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(493)/82-PF-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

New Delhi, the 7th January, 1983

S.O. 602.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 76 of 1978

PARTIES:

Employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Mr. D. L. Sen Gupta, an Executive Committee Member of the Union with Mr. Paresh Bose, Asstt. Secretary of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port

AWARD

The following dispute was referred to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No. L-32011(i)/78-D.IV(A) dated 29th August, 1979 for adjudication:

"Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in following a policy of 50 per cent direct recruitment and 50 per cent promotion on the basis of seniority-cum-suitability for appointment to the post of Junior Scientific Assistant and Scientific Assistant in the Chief Hydraulic Engineer's Department from 1976? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The Hydraulic Study Department came into being in the year 1962 headed by a Chief Hydraulic Engineer. This department is an essential and integral part of the CTP, its function being to study the character of the river Hooghly and Bhagirathi and find out ways and means to keep it navigable from the sand head to Faraka through the year. Dr. K. Bandopadhaya, MW-1 described the nature of work as below:

"Initially the navigational depth of Calcutta Port started dwindling off at fast rate and the study of the estuary and navigational channel became utmost important to the Port of Calcutta to provide sufficient effective depth for navigational purposes and to economise the dredging aspect which otherwise is a colossal expenditure. To provide these facilities study of water circulation pattern, sediment transport pattern, salinity intrusion, optimum dredging, corrective works in effective region and associated analytical and simulation studies by model and proto-type data had to be undertaken. These data have to be collated, analysed for use of hind-casting and forecasting the system behaviour for short range, medium range and long range forecasting. Initially it was meant to meet the needs of the Calcutta Port Trust, but as the expertise being unique advices to other ports like Kandla, Vizagapattanam and other navigational problems elsewhere are being imparted by the department in the present day as the technology is changing so far, i.e. the original meatre which measures the water flow and direction has now reached a new dimension. It now measures silt, salinity, temperature and depth over and above flow velocity and direction. The statistical techniques have covered a new field where parametre variations are uncontrolled and statistical in nature, superposed over influences which are deterministic. Further studies with computer system have become an indispensable too to cope with the studies which have become time bound in nature. We started using sophisticated navigational aids and electronic equipment of the latest generation. We have technical and laboratory personnel in our department. It started with Chief Hydraulic Engineer, then Deputy Chief Hydraulic Engineer, the Senior Scientific Officer/Assistant Hydraulic Engineer/Electronic Instrument Engineer then Assistant Scientific Officer/Assistant Engineer, Scientific Assistant, Jr. Scientific Assistant, Sr. Laboratory Assistant and Laboratory Assistant/Hydraulic Observer. Quite possible the bottom most cadre is Jr. Laboratory Assistant."

*** *** ***

"Actually this department was newly set up in Calcutta Port and is unique in its kind even in respect of other ports. No other port has got hydraulic study department and naturally every time local rules are framed on need based pattern with CPT administrative approval subject to finally approve by the Government of India in the long run."

From the terms of reference it is clear that the dispute relates to the mode of appointment to the post of Junior Scientific Assistant (all Class III posts) in the department of the Chief Hydraulic Engineer. Post of Junior Scientific Assist-

ant did not exist prior to 1969. One such post was created for the first time in 1969. There was, therefore, no question of promotion for the staff of this department to that post from 1962 to 1969. Rules were framed thereafter. More posts of Junior Scientific Assistant were created after 1969, that is in 1970, 1971 and in 1975. It seems that from the year 1976 the management of the CPT followed a policy of 50 per cent by direct recruitment and 50 per cent by promotion for filling the posts of Junior Scientific assistants and Scientific assistants. The question is whether this action of the management is justified. The union contends that this policy of the management is arbitrary, capricious, illegal, unwarranted, unjustified and against the existing rules usages.

3. Before I proceed further I would like to mention as to what are the duties of the Scientific Assistants and Junior Scientific Assistants. They are as below :

Designation	Duties and responsibilities
1. Scientific Assistants	(i) Organisations and supervisions of field observations and Laboratory analysis.
	(ii) Collection of special data in the field and also where according to requirements in context to departmental investigations
	(iii) Preparation of preliminary technical reports in the investigations including compilation of data and results.
	(iv) Miscellaneous computations related to scientific work on computers and other miscellaneous jobs.
	(z) Assistance to technical officers in their work.
2. Jr. Scientific Assistant	(i) Hyderabad observation in the field, river, etc.
	ii) To assistant scientific Asstt. and Asstt. Scientific Officer in analysis of scientific data and preparation of preliminary Technical report
	(iii) Miscellaneous computations and plottings related to works in the department and general assistance to Scientific assistant.
	(iv) Other work allotted from time to time by scientific Assistants and other Officer

MW-1 Dr. K. K. Bandopadhyay has also said in his evidence :

> "The responsibility of the Scientific Assistants are to supervise, laboratory analysis, field observation, preliminary reporting, assisting Scientific Officers in the study and collation of channel data. By report I mean technical report, but that is preliminary level. They have also to work on Computers. They have to go out for collecting data."

It is clear from the above that the duties and functions of the Scientific Assistants and Jr. Scientific Assistants are such that the progress of the department in the research work will depend on the initiative, interest in the subject and sustained and dedicated work of the staff concerned and that some capacity of original thinking is essential. In the present case the aggrieved persons are the laboratory assistants. They want that the vacancies in the posts of Jr. Scientific Assistants should be filled by promotion of Sr. Laboratory assistants on the basis of their seniority-cum-suitability and that vacancies in the post of Scientific assistants should be filled by promoton of Jr. Scientific Assistants and if there is no suitable departmental candidate than only persons from outside can be taken. According to the Union, there exists hierarchy of channel of promotion and therefore promotion should be made from Jr. Laboratory assistant to Sr. Laboratory Assistant to Jr. Scientific Assistant to Scientific Assistant. According to the management the practice of filling half the number of the posts of Jr. Scientific Assistants by departmental candidates and the remaining half by direct recruitment from the open market had been in vogue for years and it was in conformity with the rules and procedure of the management and that there had been no change in that. It is said that prior to 1969 there was no post of Junior Scientific Assistant, that the Scientific Assistants were all being recruited directly and so there was no scope for promotion for the Sr. Laboratory Assistants.

4. It is contended by the union that the laboratory assistants have been unjustifiably deprived of their promotional opportunity in their hierarchical chain from Jr. Laboratory assistant to Sr. Laboratory assistant to Jr. Scientific Asstt. to Scientific Assistant on account of the change in the procedure of promotion in the year 1976 and that the policy of the management is contrary to the existing rules and usages and is in violation of Section 9A of the Industrial Disputes Act. It is pointed out that the laboratory assistants knew if from the very time of their appointment as an implied condition of their service that as a matter of course they will automatically go to the scale/grade of Scientific assistant by promotion on the basis of seniority-cum-suitability and that all such posts shall be filled in from amongst them, that this expectation was in conformity with the provisions of the Das Gupta Tribunal award of 1958, rules of the CPT as well as long usage and practice in vogue under which promotion to higher posts was made from existing incumbents of the lower cadre. It is urged that resort to direct recruitment from outside has deprived them of their expectation of being promoted. It is said that there were few posts of Scientific Assistants and Jr. Scientific Assistants, that there were few vacancies and therefore the change of promotion became remote if 50 per cent from outside were recruited. In my opinion the argument is not sound. As already stated, this department started in the year 1962 for the first time. Prior to 1969 Scientific Assistants were all being recruited directly. There was no established procedure of promotion and there could not be any at that time. In view of the fact that the progress in research depended on the intiative, interest in the subject, original thinking and on sustained as also dedicated service of technical and scientific personnel, a scheme of promotion (Ext M-1 dated 1 March 1969) was prepared by the Chief Hydraulic Engineer in the year 1969 and it was submitted to the Chairman of the CPT in the same year. By that scheme it was suggested and recommended that 50 per cent of the posts of Jr. Scientific assistance and Scientific assistants should be filled from outside and the remaining 50 per cent by promotion of the internal candidates. This recommendation of the CHE was approved by the Administration in principle, vide Ext. M-2 dated 15-1-70. It seems, however, that in the year 1969 there was only one post of Jr. Scientific assistant which had been created for the first time in that year i.e. 1969. There was no such post earlier to 1969. There was, therefore, no question of any practice or usage or any rule of promotion for filling the post of Jr. Scientific assistant prior to 1969 and there could not be any. As there was only one post, the Administration made the following ad hoc order in respect of its filling up :—

> "Since there is only single post of Junior Scientific Assistant, the Administration suggests that instead of reservation of 50 percent of the vacancies in this post of filling up by selection from among the senior Laboratory Assistants, it should normally be filled up by promotion of Senior Laboratory Assistants, direct recruitment being resorted to only when there is no suitable candidate for promotion. In case of direct recruitment the minimum qualifications suggested by you should apply."

It is to be noticed that this was a temporary measure and that the administration had already accepted (see Ext.

M-2) the recommendations of the Chief Hydraulic Engineer for filling 50 per cent of the post by direct recruitment.

5. It is to be noticed that correspondence for formulating the scheme of promotion started from the very time of creation of the post of Jr. Scientific assistant i.e. from 1969 between the Chief Hydraulic Engineer and the Chairman of the CPT. The work of research went on increasing. Hence seven more temporary posts of Jr. Scientific assistants were created subsequently : one in 1970, two in 1971 and four in 1975. In the opinion of the administration the Senior Laboratory assistants were not sufficiently equipped to meet the needs of technology which was advancing with extraordinary rapidity in the field of investigation, instrumentation and research and, therefore, they thought that there should be partial direct recruitment to the post of Jr. Scientific assistants and Scientific assistants. They decided to recruit 50 per cent of the newly created posts to be filled by direct recruitment and 50 per cent by promotion on the basis of seniority-cum-suitability from the internal candidates. I have already said that there were no rules of promotion in the year 1969 when the post of Jr. Scientific assistant was created for the first time. Rules were framed in the next year i.e. in 1970 for both the posts of Jr. Scientific as assistants and Scientific assistant, vide Ext. M-2. I have already pointed out that more temporary posts of Jr. Scientific assistants were created in 1970, 1971 and upto 1975. Arrangement for filling those posts were made in the year 1976 following a policy of 50 per cent direct recruitment and the rest 50 per cent by promotion. In 1976 those posts of Jr. Scientific assistants were to be filled in. The management selected three Sr. Laboratory assistants and appointed them to the post of Jr. Scientific assistants. The remaining three posts were filled up by direct recruitment. It is thus clear that by the increase in the number of posts of Jr. Scientific Assistants from one in 1969 to eight in 1976 the scope of promotion of the existing incumbents in the cadre of Sr. Laboratory assistants became better. Furthermore, it is clear that higher post of Junior Scientific Assistant was newly created in 1969 and thereafter and it could not have then any promotional arrangement and as such the post was selective and new person from outside could be appointed to that post. As pointed out in Vishnu Sugar Mills Ltd. v. Workmen, 1960 SC 812, new men from outside can be appointed to newly created posts. From this point of view also the stand taken by the union cannot be accepted as correct. I think, the management is justified in filing 50 per cent of the posts by direct recruitment and there is nothing wrong in that.

6. In continuation of the above submission it was argued by the union that the management wanted to provide for their friends and relations in the 50 per cent of the posts and that corruption being rampant all the appointments made from 1976 from outside should be cancelled as there was no moral sanction behind it. In my opinion, it is not possible to agree with this contention. There cannot be any presumption that the policy aforesaid was adopted by the management for their friends and relations. If such argument is accepted then there can never be any recruitment from outside. Sri Sen Gupta appearing for the union relied on Workmen of M/s. Williamson Magor & Co. Ltd. v M/s. Williamson Magor & Co., AIR 1982 SC 78 in order to show that unjustified promotions can be cancelled and they were cancelled by the Supreme Court even after several years. In my opinion that decision has not been properly appreciated. In that case the management had not framed any norms/rules fixing quota for the grades and for promotion/upgradation of the workmen and they had unjustifiably promoted some junior clerks superseding without any reason or necessity a large number of senior clerks. The Supreme Court, therefore, cancelled unjustified promotions and directed the management to frame norms/rules in consultation with the workmen under the direction, supervision and control of the Labour Commissioner of the region and to make future promotions according to the norms-rules so framed. There was no question of recruitment from outside in that case. All the promotions had been made from internal candidates though they were all juniors. Such is not the case here. The facts of that case, therefore, are wholly different and can be of no assistance to the union in the present case. The issue involved here is a different one. In the present case, the management has taken a policy decision regarding recruitment 50 per cent by promotion and 50 per cent by direct recruitment and the question is, whether the action of the management is justified. I think it is justified. I may illustrate it by an example of a house in which there are several rooms having inter-connected doors. If the internal doors are open, air of one room will pass to the other but if the windws are shut no fresh air can come in although the air of one room will go to another room. If windows are open fresh air will come. In the same way if there is fresh recruitment from the public at large, fresh talent may come and there will be chance of progress in the research work. The contention of the union is rejected.

7. It is next contended by Sri Sen Gupta for the union that existing incumbents were better qualified and more suitable for promotion having good education and long experience of service and there was no justification for change of existing rule and that the Laboratory assistants are, therefore, entitled to be promoted on the basis of seniority-cum-suitability with retrospective effect from 1976 even by creating supernumerary posts if required. It is said that for none of the promotional post any standard of knowledge or quality is prescribed; that even if advanced scientific knowledge is at all required it should be so at the higher level in Class I posts for which already 67 per cent of the direct recruitment provision exists and not for class III posts. In my opinion the contention is not correct. In the first place this Tribunal is not supposed to decide as to whether the existing incumbents are sufficiently and better qualified or not. It is purely the function of the management to assess the capability of their employees. They are the best judge of their merits. According to the administration the prescribed qualification for the post of Scientific assistants are Master Degree in Science which most of Laboratory assistants do not posses. Dr. K. K. Bandopadhyay, MW-1, has deposed :

> "To exemplify only B.Sc. qualification were put to computer training in the statistical institute to finally associate in the computerizing work in the department but unfortunately it was not very rewarding. On the other hand direct recruitee with higher qualification plus the same training fared better. There are different types of work, statistical, computerized, chemical analysis or instrumentation. One is not inter-changeable with the other particularly when time bound objective is the task assigned. It depends on the qualification the Junior Scientific Assts. have i.e. whether they possess the requisite qualification for being recruited as Sr. Scientific Assistant. The main consideration is qualification and then experience for filling up the post of Scientific Assistant."

His evidence has been bitterly critized by Sri Sen Gupta mainly on the ground that there is no record to substantiate the same. In my opinion the criticism is not justified. MW1 is a highly qualified and responsible Officer of the CPT and I do not find anything in his evidence to disbelieve him. I rely on him. However, I think that the contention is not relevant for the purpose of decision in the instant case because the issue here is regarding the justification of the policy of the management for filling the posts of the above two categories, 50 per cent by direct recruitment and 50 per cent by promotion. It is not the issue here to determine whether the existing incumbents are superior or inferior to the outsiders who may be appointed to the said posts from time to time in future. The contention is rejected

8. It is next contended by the Union that the new service rule relating to recruitment which is being followed from 1976 being without any approval of the Government of India could not have any legal sanction or operation. It is pointed out that the scheme of recruitment of 50 per cent by direct recruitment and 50 per cent by promotion was never considered in any meeting of the CPT and had not been approved by the Board of Trustees and hence it was invalid and therefore the existing rule of promotion of the CPT based on the principle of seniority-cum-suitability applicable to other employees should be held to be the only recognised rule to be applied to the Hydraulic Study department also and any departure therefrom is illegal and void. In my opinion, this contention also has no substance. It has

come in the evidence of MW-1 Kalyan Kumar Bandopadhaya that sanction of the Chairman for class III employees is enough. Sri Sen Gupta has not pointed out any provision of law to show that the Chairman had no authority to sanction the rule for class III employees. My attention has been drawn to Ext. M 3 dated 4 February 1976 which is a letter sent by CHE to the Chairman to approve 50 per cent to be filled by direct recruitment and 50 per cent by promotion as 6 posts of Jr. Scientific Assistants were to be filled up. The Secretary sent it to PA&CAO for favour of early comments. The PA&CAO suggested that the matter be gone into by a committee consisting of departmental officers and others. Sri Sen Gupta argues that the matter was never considered by the Board of Trustees of the CPT. In my opinion the suggestion of the CHE made in 1969 (Ext. M-1) had already been approved by the Administration in principle in 1970 (vide Ext. M-2) and there was no necessity to ask for approval again. The contention is accordingly rejected.

9. The fourth contention of Sri Sen Gupta is that Section 9A of the Industrial Disputes Act 1947 was infringed by changing the service condition in 1976. I do not think so. There has been no change in the service condition because, as already stated, there was no rule for promotion in the deppartment in question. It cannot therefore be said that any change was brought in any existing rule of promotion. Section 9A is not attracted to the facts of the present case. The contention is rejected.

10. The fifth contention of Sri Sen Gupta for the union is that the policy decision of the management aforesaid is in violation of the terms and spirit of the Das Gupta award and as such it is inoperative and void. But that award was only in respect of the avenue of promotion for class IV employees and it has no application in regard to the promotion of class III posts. In the instant case we are concerned only with class III posts. The argument is, therefore, rejected.

11. The last contention of Sri Sen Gupta for the workmen is that under the agreement, Ext M-10 between the CPT and the Calcutta Port Shramik Union which was effective from 1 April 1974 in respect of class III employees, no one could be recruited from outside. In my opinion, the contention is not accurate. By that agreement of the promotional opportunities were widened for the clerical post. The agreement does not prohibit the Management from framing new rules for the staff of the Hydraulic department in which posts were created even in 1975. The contention is rejected.

12. After having considered the materials on record my concluded award is that the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in following a policy of 50 per cent direct recruitment and 50 per cent promotion on the basis of seniority-cum-suitability for appointment to the posts of Junior Scientific Assistants and Scientific assistants in the Chief Hydraulic Engineer's department from 1976. It follows, therefore, that the workmen are not entitled to any relief.

[No. L-32011/1/78/D.IV(A)]

M. P. SINGH, Presiding Officer

Dated, Calcutta,
The 20th December, 1982.

S.O. 603.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs New Bharat Commercial Services Private Limited, Bombay, and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/6 of 1981

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs New Bharat Commercial Services Pvt. Ltd., Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer—No appearance.

For the workman—Shri S. R. Wagh, Advocate.

STATE : Maharashtra. INDUSTRY : Ports & Docks.

Bombay the 16th December, 1982

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By their order No. L-31012(4)/81-D.IV(A) dated 3-6-1981 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 viz.,

"Whether the action of the management of Messrs New Bharat Commercial Services Private Limted, Bombay in terminating the services of Shri Vithal Arjun Narvekar, Custom Clerk, is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The dispute has arisen because of the alleged oral retrenchment of the workman in question namely Shri Vithal Arjun Narvekar on 18-12-1979, despite he having put in seven years of service namely from 16-10-1973 to 17-12-1979. The contention of the Union on behalf of the workman is that on the relevant date when the workman tried to attend his duty the management told him not to attend from 18-12-1979, which oral direction according to the workman is illegal, improper and unjustified and against the provisions of the law.

2. In reply to this contention the management filed first Ex. 3/M and subsequently they also filed additional written statement at Ex. 3/AM. By the first written statement the plea of the management is that on 14-12-1979 when the workman resumed his duties after returning from leave he picked up some quarrel with the Director and threatened him and thereafter he left the premises of the company and did not report till 18-12-1979. It is further alleged that on 18-12-1979 the workman visied the office of the company and informed the Director his unwillingness to serve the company any more. According to the management when the workman was told to resign in writing there was a refulsal on his behalf and it is further alleged that since the said time the workman never reported for duty. Accoring to the company on 26-12-1979 the workman sent the claim for his difference in salary but since the same was not to be granted the company declined to pay anything.

3. By the additional written statement plea of the company is further clarified and it is alleged that the workman had given threat to do away with the Director and the management sought permission to establish the said misconduct:—

4. To substantiate these allegations regarding the threat the management examined Shri Nirmal Kumar and further to establish that from January, 1980 the workman is gainfully employed with M/s Narendra & Co., Clearing and Forwarding Agents, a witness by name Shri C. Krishnan Unni has also been cited. Against this there the affidavit of the workman denying all these allegations which affidavit Ex. 4/W as the matter stands remains unchallenged.

5. In view of the dispute the following issues arise for determination and my finding thereon are:—

ISSUES

1. Does the employers prove that the employee abandoned the service on 14-12-1979	NO
2. Is it also established that on 18-12-1979 the workman reiterated his intention not to serve the Respondent any more?	NO
3. Whether this action on the part of the workman, if proved, severes relationship of employer-employee between the parties?	Does not arise.
4. If not whether the workman proves that he was told verbally on 18-12-1979 not to attend the duties any further?	Yes
5. Whether this amounts to valid retrenchment?	NO
5A. Whether the employer establishes that the employee was guilty of the misconduct as stated in the first para. of their Additional written statement filed to-day?	NO
5B. If yes whether the management was entitled to terminate the services?	Does no arise.
6. If no is the workman entitled to any relief?	Yes
7. If yes, is he entitled to reinstatement, compensation or any such other relief?	Not of reinstatement but other reliefs.
8. What award?	As per order.

REASONS

6. Although the management has come forward with the plea it was the workman who left the service and that there was never an oral direction issued by the management and further there is a plea of alleged misconduct on the part of the workman, except the word of Shri Nirmal Kumar in this regard, there is nothing to substantiate these allegations particularly when there is denial on the part of the workman. If what the workman asked for was rise in salary, having regard to the fact that he had put in seven years of service with the opponent company it is far from believable that all of a sudden he would become violent and thus create adverse situation. The threat is alleged to have been heard by other employees working in the office but none of them has been examined although some writing alleged have given by one of them is on record. After considering the totality of the circumstances and considering the denial of the workman, I am convinced that what is stated about the threat is not at all believable, much less proved and the change in employment must be the result not of volition on the part of the employee but must be in pursuance of the direction given by the Director.

7. Once we arrive at this conclusion the only inference possible is that on 18-12-1979 the workman who had put in almost seven years of service, illegally retrenched in violation for the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act and therefore the said severance is invalid from the inception and the workman would be entitled to all the reliefs which arise out of such illegal retrenchment. On the reliefs would be the order of reinstatement but Shri Wagh on behalf of the workman says that since the workman has now joined the service of another employer namely M/s Narendra & Co, he is no longer interested in the service with the opponent company. What then remains is to award the reliefs like retrenchment compensation and notice pay payable under Section 25F of the I.D. Act.

8. Normally had the workman remained unemployed he would have also entitled to the subsequent wages. However, it is on record which was stablished by the witness No. 2 of the Management that from January, 1980 the workman is in the service of M/s Narendra & Co. In the month of January, 1980 he was getting Rs. 600, from February 1980 to December, 1980 his emoluments were at the rate of Rs. 700 and while from January, 1981 to Agust, 1981 he was drawing emoluments at the rate of Rs. 735 plus fixed D.A. of Rs. 135 and varying D.A. of Rs. 30. From September, 1981 he was drawing Rs. 770 and Rs. 135 as fixed D.A. plus Rs. 30 as varing D.A. and if the last drawn salary with the Opponent company was Rs. 920 as stated by the workman, from September, 1981 he started getting something more than what he was getting while in te service of the Opponent company. On the strength of the material if the calculations are made then for the month of January, 1980 the workman would be entitled to Rs. 320. from February, 1980 to December, 1980 he would be entitled to Rs 2420 while from January, 1981 August, 1981 he would be entitled to get Rs. 160 that is in all Rs. 2900. Since from 18th December, 1979 he was not allowed to attend his duties there is force in the contention that no wages were paid for the month of December, 1979, which amounts to Rs. 920 and if the sum of Rs. 2900 is added it makes a grand total of Rs. 3820. The workman shall be entitled to receive this much amount besides retrenchment compensation and notice pay as stated earlier.

Award accordingly. No order as to costs.

20th December, 1982

M. A. DESHPANDE Presiding Officer,

[No. L-31012/4/81-D.IV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer.

का० आ० 604.—मैसर्स थिआगराजार मिल्स कप्पालुर, तमिलनाडु (तमिलनाडु/1049) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/288/82-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 11th December, 1982

S.O. 604.—Whereas Thiagarajar Mills, Kappalur, Distt. Madurai, Tamil-Nadu (TN/1049) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaenous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be brone by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol **him as a member of the Group Insurance Scheme and pay** necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/288/82-PF-II]

का०आ०605.—मैसर्स राठी अल्लोयज एण्ड स्टील लिमिटेड 3-ए, वन्धना, 11 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-1 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदे से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त

स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/422/82-पी० एफ-II]

S.O. 605.—Whereas Messrs Rathi Allow and Steel Limited 3-A, Vandhna, 11, Tosltoy Marg, New Delhi-1 (DL/4739) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner New Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time ti time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Rgional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sun assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(422)/82-PF-II]

का० आ० 606.—मैसर्स इस्ट्रेक्ट लिमिटेड, कोटा,-324005 राजस्थान, (राजस्थान/1139,) (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त-अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/403/82—पी० एफ० -II]

S.O. 606.—Whereas Messrs Instrumentation Limited Kota-324005 (Rajasthan), (RJ/1139) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the Employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns tothe Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, (Rajasthan (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(403)/82-PF-II]

का० आ० 607—मैसर्स मेमूकी हैड्रौलिक्स लिमिटेड, उद्यमबाग इण्डस्ट्रियल एस्टेट, खानपुर रोड, बेलगाँम, कर्नाटक (कर्नाटक/168), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो

यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/398/82-पी०एफ० II]

S.O. 607.—Whereas Messrs Bemco Hydraulics Limited, Udyambag Industrial Estate, Khanapur Road, Belgaum, (Karnataka) (KN/168), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(398)/82-PF-II]

का०आ० 608.—मैसर्स टेक्समेन्ट इण्डिया लिमिटेड, गोपालपुर, बज-बज रोड, डाकघर सरकारपुल, जिला 24-परगना, (पश्चिम बंगाल/7767), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में, फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/397/82-पी० एफ०-II]

S.O. 628.—Whereas Messrs Tecalemant India Limited, Gopalpur, Budge Budge Road, Post Office Sarkarpool, District 24-Parganas, (WB/7767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval,

give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(397)/82-PF-II]

का०आ० 609.—मैसर्स कोयम्बतूर जिला सेन्ट्रल को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, पोस्ट बेग नं० 1098, आर०एस० पुरम पोस्ट आफिस, कोयम्बतूर-641002 (तमिलनाडु/2616), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के, कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/415/82-पी० एफ०-II]

S.O. 609.—Whereas The Coimbatore District Central Co-operative Supply and Marketing Society Limited, Post Bag No. 1098, R. S. Puram Post Office, Coimbatore-641002 (TN/2116) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. 35014(415)/82-PF-II]

का०आ० 610.—मैसर्स प्रेसिशन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 33 बी/ए, लक्ष्मीबाई नगर, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फोर्ट, इन्दौर-452006, (मध्य प्रदेश/2108), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त

दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारीयों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/370/82-पी० एफ०-II]

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 610.—Whereas Messrs Precison Electicals and Electronics (Private) Limited, 33 B/A Laxmibai Nagar, Industrial Estate, Fort, Indore-452006 (MP/2108) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(370)/82-PF-II]

का०आ० 611—मैसर्स इन्दौर डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव एण्ड डेवेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, 21-महारानी रोड, इन्दौर-452002, (महाराष्ट्र/3119), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/368/82-पी० एफ-II]

S.O. 611.—Whereas Messrs The Indore District Co-operative Land Development Bank Limited, 21, Maharani Road, Indore-452002, (MP/3119) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance, which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be brone by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(369)/82-PF-II]

का०आ० 612—मैसर्स किरलोस्कर कुम्मिन्स लिमिटेड, कोथरूड, पूणे - 411029 (महाराष्ट्र / 7063), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/367/82-पी० एफ०-II]

S.O. 612.—Whereas Messrs Kirloskar Cummins Limited, Kothrud, Pune-411029, (MH/7063) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if, the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(367)/82-PF II]

का०आ० 613.—मैसर्स गाबरा बेवेल गीयर्स लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एरिया, ए-बी रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश / 3424), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम

1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/368/82-पी० एफ०-II]

S.O. 613.—Whereas Messrs Gajra Bevel Gears Limited, Industrial Area, AB Road, Dewas-455001 (MP/3424) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(366)/82-FF-II]

का०आ० 614.--मैसर्स लेप्रोसी मिशन, 5-अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली-110003, (दिल्ली/3569) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत., केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/364/82-पी० एफ-II]

S.O. 614.—Whereas Messrs The Leprosy Mission, 5, Amrita Shergill Marg, New Delhi-110003 (DL/3569) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member concerned under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(364)/82-PF-II]

का० आ० 615.—मैसर्स गेस्ट कीन विलियाम्स लिमिटेड, स्क्रीवज एंड फास्टेनर्स डिवीजन, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भण्डुप, बम्बई-78 (महाराष्ट्र/711) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/363/82-पी० एफ०-II]

S.O. 615.—Whereas Messrs Guest Keen Williams Limited, Screws and Fasteners Division, Lal Bahadur Shastri Marg, Bhandup, Bombay-78 (MH/711) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme fo a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspecting, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employers than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect

adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(363)/82-PF-II]

का० आ० 616.—मैसर्स वसन्त फाईन आर्ट लिथो वर्क्स, मनोहर कालोनी रोड, गोण्डिया-441601, (महाराष्ट्र/3549), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम, का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन, आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/362/82-पी०एफ० II]

S.O. 616.—Whereas Messrs Vasant Fine Art Litho Works, Manohar Colony Road, Gondiya-441601 (MH/3549) (hereinafter refrered to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Cetral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life

Insuranc Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and where amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme. if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explaint their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(362)/82-PF. II]

का० आ० 617.—मैसर्स नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरटिव मार्केटिंग फेडेरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, सपना बिल्डिंग, 54-इस्ट आफ कैलाश, पोस्ट बाक्स नं० 3580, नई दिल्ली-24 (दिल्ली/507), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किस सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/296/82 पी० एफ० II]

S.O. 617.—Whereas Messrs National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited, 'Sapna Building, 54, East of Kailash, P.B. 3580, New Delhi-24 (DL/1507) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner,, New Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and where amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employers than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(296)/82-PF. II]

का०आ० 618.—मैसर्स वैक्यूम प्लान्ट एण्ड इनस्ट्रूमेन्ट्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मुन्धवा, पूणे-411036 (महाराष्ट्र/8673), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/287/82-पी० एफ०-II]

O.S. 618.—Whereas Messrs Vacuum Plant and Instruments Manufacturing Company Private Limited, Mundhwa, Pune-411036 (MH/8673) (hereinafter refrered to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. 35014(287)/82-PF. II]

का०आ० 14.—मैसर्स फिरलोसकर फिल्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कोथुड पूणे-411029 (महाराष्ट्र/12280), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-- 35014/286/82-पी० एफ०-II]

S.O. 619.—Whereas Messrs Kirloskar Filters Private Limited, Kothrud, Pune-411029 (MH/12280) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaenous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity of the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption is liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(286)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का. आ. 620 :—केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में डा. पी. पी. संथापनम के स्थान पर डा. एन. उमाशंकर, चिकित्सा अधिकारी, इंगलिश इलैक्ट्रिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास-600043, को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् के सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3329, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नाम-निर्दिष्ट)", शीर्षक के नीचे मद 25 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

डा. एन. उमाशंकर,
चिकित्सा अधिकारी,
इंगलिश इलैक्ट्रिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड,
मद्रास-600043 ।

[संख्या यू-16012/8/82-एच. आई.]
ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 620.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (e) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. N. Umashanker, Medical Officer English Electric Corporation of India Ltd., Madras-600043 as a member of the Medical Benefit Council in place of Dr. P. P. Santhanam;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments concerned under clause (c) of sub-section (1) of section 10)" for the entry against item 25, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. N. Umasanker,
Medical Officer,
English Electric Corporation of India Ltd.,
Madras-600043."

[No. U-16012/8/82-HI]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983